हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 मार्च, 1995

खण्ड 1, अंक 8

अधिकृत विवरण

Hus/Lib/9

विषय सूची

बुधवार, 15 मार्च, 1995

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(8)1
वाक आउट	(8)15
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(8)16
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(8)19
राज्यपाल से सन्देश	(8)21
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री द्वारा लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा जाना	(8)21
ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं	(8)22
मीडिया व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना की गई सभी पार्टियों के एम0एल0 एज0 की एक समिति के गठन सम्बन्धी मामला	(8)24
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	

मूल्य :

12.00

	पृष्ठ संख्या
(i) चौधरी बंसी लाल द्वारा	(8)30
(ii) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा	(8)31
(iii) चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा	(8)31
श्री कर्ण सिंह दलाल, एम0 एल0 ए0 द्वारा श्री राम रतन, एम0 एल0 ए0 को धमकी देने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी मामला	(8)32
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)33
वाक आउट	(8)34
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)35
बैठक का समय बढ़ाना	(8)71
वर्ष 1995–96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(8)72

©
Vic
&

ERRATA

To

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 1, No. 8, dated the 15th March, 1995.

Read	For	Page	Line
प्राइवेट	प्रइवेट	3	10
Auction	Aucation	12	29
वाक-आउट	वाक-काउट	15	28
भारी	ारी	22	19
श्री अध्यक्ष	श्री अथ्यक्ष	25	21
बात तो	बात को तो	28	17
मुनकर	मुकर	28	20
पंचकूला	पचकला	39	1
परसैंट	परसट	39	20
स्कूल	स्क्ल	39	31
संस्थाएं		40	25
नारनौंद	नारनौल	50	19,20
जरिए	जारए	68	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 15 मार्च, 1995

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Pass Percentage of Results

***1024. Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the percentage of the result of Middle Standard, Matric and 10+2 System Examinations of Government Schools, Government aided Private Schools and Non-Government aided Private Schools during the year 1993-94 in the State ;

(b) whether it is a fact that the result of the Government aided Private Schools and Non-Government aided Private Schools is higher than that of Government Schools in the State ; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps taken or proposed to be taken to streamline teaching system in order to improve the results of the Government Schools in the State ?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana) :

(a) (b) and(c) : The Information is laid on the Table of the House.

Information

(a) Percentage of the result is as follows :—

Examination **Result** (1993-94)

Level	Govt. Schools	Govt. aided Private Schools	Non-Govt. aided Private Schools
Middle	30.64	63.56	58.99
Matric	24.91	66.76	45.51
10+2	8.43	23.76	17.32

(b) Yes

(c) Reason for lower results in case of Govt. Schools are shortage of staff and curbing the menance of copying. The following steps have been taken to improve the results of Govt. Schools.

(i) Inspection of Schools has been made more intensive and extensive and a special campaign has been launched for inspecting maximum number of schools, especially those which have given less than 50% results.

(ii) System of monthly tests and quarterly examination has been introduced and the progress of the students would be communicated to the parents regularly.

(iii) Extensive in-service training programmes are being organised for the professional growth of teachers.

(iv) Class-wise syllabus has been distributed month-wise.

(v) The pattern of internal examinations of the Schools has been made uniform in order to prepare the child for the Board Examination. In order to introduce continuous and comprehensive evaluation, marks of half yearly Exam. held in Dec.—Jan., will be added in the Annual Examination results.

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने मिडल, मैट्रिक और टैन प्लस टू की परीक्षाओं के रिजल्ट का जो विवरण दिया है, वह बहुत ही हृदय विदारक है । मंत्री महोदय ने गवर्नमैंट स्कूलों का रिजल्ट अच्छा न होने के कारण दर्शाए हैं कि गवर्नमैंट स्कूलों में स्टाफ की कमी है । यह तथ्यों से दूर की बात है । गवर्नमैंट ने नकल रोकने का मानसिक प्रयास किया है । गवर्नमैंट के पास तीन डी० पी० आईज० हैं जोकि आई० ए० एस० केडर के हैं, डी० ई० ओज०, एस० डी० ई० ओज० और इंस्पैक्टिंग स्टाफ है लेकिन इंस्पैक्शन बिल्कुल न के बराबर है ।

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आप सवाल पूछें ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं । इस प्रकार से हरियाणा वासियों के बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गवर्नमैंट स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिये कोई कारगर कदम उठाएगी ? इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन गवर्नमैंट स्कूलों में रिजल्ट बहुत ही खराब आया है, क्या उन स्कूलों के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कोई उपाय करेगी ? जो अच्छा काम करने वाले टीचर्ज हैं, उनको कोई इनसैंटिव दिया जाएगा तथा जिन टीचर्ज का रिजल्ट खराब है, क्या उनको कोई पनिशमैंट दी जाएगी ? जो रिजल्ट खराब आ रहा है, उसका कारण स्टाफ की कमी नहीं है बल्कि एजुकेशन डिपार्टमैंट में टीचर्ज की ट्रांसफर पालिसी का नतीजा है । किसी टीचर का दिसम्बर के महीने में ट्रांसफर कर देते हैं और किसी का जनवरी में ट्रांसफर कर देते हैं । क्या सरकार टीचर्ज की ट्रांसफर की कोई ऐसी पालिसी बनाएगी ताकि टीचर्ज पूरे साल पढ़ाई की तरफ लग सकें ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने तीन चार सप्लीमैंटरी पूछी हैं। इनकी पहली सप्लीमैंटरी का उत्तर यह है कि जो सरकारी स्कूल हैं, वे मासिज़ को डील करते हैं । सरकारी स्कूलों में सभी दाखिला लेते हैं । प्राईवेट स्कूलों में स्टाफ भी अच्छा है और वे शहरी क्षेत्र में हैं । हमारे सरकारी स्कूल ढाणी, बस्ती और गांवों में है । जो हमारा समाज गांव में रहता है, वह ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है और न ही वह खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं । छतर सिंह जी खुद शहर में रहते हैं और इसी वजह से इनके बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है । दूसरा कारण यह है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे दाखिला लेते हैं, हम उन सभी की परीक्षा दिलाते हैं जबकि प्राईवेट स्कूल वाले जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, उनकी परीक्षा तो अपने स्कूल की तरफ से दिला देते हैं लेकिन कमजोर बच्चों की परीक्षा वे प्रईवेट कैंडीडेट के तौर पर दिलाते हैं, इसीलिए उनका रिजल्ट अच्छा आता है । कुछ कमियां हमारे स्कूलों में हैं, इनको मैंने माना है । एक तो हमारे पास स्टाफ की कमी है । दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने जो नकल रोकी है, मुख्यमन्त्री जी के आशीर्वाद से इस में हम सफल भी हुए हैं, का भी रिजल्ट पर असर पड़ा है । मैं आप के माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि अभी 10+2 की परीक्षा समाप्त हुई है। हमारे यहां पर आधा परसैंट के करीब ही नकल के केसिज़ पाये गए हैं। यानि 99.5 प्रतिशत पेपर फेयर हुए हैं । इन्होंने पूछा कि कदम क्या उठाये जा रहे हैं । सबसे बड़ा कदम तो नकल रोकने का है, जिससे बच्चों में भी और अध्यापकों में भी चेतना आई है । जहां पर हमारा रिजल्ट पहले 10 परसैंट था, बाद में सप्लीमैंटरी के दौरान वही रिजल्ट 46 परसैन्ट तक बढ़ गया था और अब उसमें और अधिक इम्प्रूवमैंट होने जा रही है । एक बात इन्होंने यह पूछी कि जो अच्छे टीचर हैं, उनको ईनाम दिया जाये । मैं बताना चाहता हूं कि जो अच्छे टीचर हैं, उनको ईनाम भी दिया जा रहा है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिन स्कूलों का रिजल्ट 50 प्रतिशत या कम रहा है, वहां पर इन्सपैक्शन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । जो अच्छे टीचर हैं, उनको रिगार्ड दिया जा रहा है और जो ठीक तरह से नहीं पढ़ाते, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है । एक सवाल इन्होंने ट्रांसफर पालिसी के बारे में पूछा । उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने कोई जनरल ट्रांसफर नहीं की और जनरल ट्रांसफर्ज अब भी नहीं होंगे ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि इन्होंने नकल रोकने का मानसिक प्रयास किया है और जिसकी वजह से रिजल्ट पर असर पड़ा है । मैं पूछना चाहूंगा कि क्या नकल सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही रोकी गई ? क्या प्राईवेट स्कूलों में खुली नकल हुई है ? प्राईवेट स्कूलों में टीचर भी कम होते हैं, पे भी कम होती है और दूसरी सुविधाएं भी कम होती हैं । इस सब के बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा रहता है और हमारे अध्यापकों का अच्छा वेतनमान और उनकी अपेक्षा बहुत सी सुविधाएं लेते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो है । मैं तो यह कहूंगा कि हमारे स्कूलों की प्राईमरी और मिडिल शिक्षा तो एक प्रकार से खत्म हो चुकी है। जब उनका बेसिक

[प्रो0 छतर सिंह]

आधार ही खत्म हो गया, तो फिर हायर एजुकेशन में कैसे वे आगे आ सकेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि जिन स्कूलों में 8.5 परसैन्ट रिजल्ट रहा है, उन स्कूलों का डायरैक्टोरेट में बैठे डी0 पी0 आई0 और फील्ड में बैठे डी0 ई0 ओ0 व एस0 डी0 ई0 ओ0 ने कितनी कितनी इन्सपैक्शन की है ? ये इन्सपैक्शन की बजाये यहीं पर ए0 सी0 कमरों में ही बैठे रहते हैं । कृपया बताएं, जिनका रिजल्ट निम्न स्तर का रहा है, वहां पर कितनी कितनी इन्सपैक्शन की गई है ? कितने हाई स्कूलों का डायरैक्टर आफ स्कूल एजुकेशन ने निरीक्षण किया है ? कितने स्कूलों का डी0 ई0 ओज0 तथा बी0 ई0 ओज0 ने निरीक्षण किया है ? अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में स्टुडैंट्स टीचर्ज की क्या रेशो है ? प्राईवेट स्कूलों में स्टुडैंट्स टीचर्ज की क्या रेशो है ? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा कि नकल रोक दी है, इसलिए रिजल्टस पर असर पड़ा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तो अभी दूर की बात है । माननीय मन्त्री जी क्या इन्सपैक्शन और रेशो के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी छतर सिंह जी को बताना चाहूंगा कि इम्तिहान प्राईवेट स्कूलों में भी और सरकारी स्कूलों में भी होते हैं और नकल भी दोनों जगहों पर होती है । ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में ही नकल होती थी । नकल तो सारी जगहों पर होती थी । नकल के नाम पर सारे हरियाणा को बदनाम किया जा रहा था । स्कूलों में नकल होती नहीं थी, बल्कि नकल करवाई जाती थी । इसमें सरकारी और प्राईवेट स्कूल दोनों शामिल रहे हैं । अब नकल में कमी आई है। अब तो केवल नाममात्र ही शायद रह गई है । अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल उन्होंने यह पूछा कि टीचर्ज और स्टुडैंट्स की रेशो क्या है ? प्राईवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में टीचर और स्टुडैंट की रेशो एक समान है । 40 स्टुडैंट्स पर एक टीचर की रेशो है । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि स्कूलों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए पिछले साल हमने करीब साढ़े-पांच हजार टीचर्ज की भर्ती की थी और अब भी 3200 के करीब रिक्विजीशन हमने एस0एस0एस0 बोर्ड या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजी हुई है और स्टाफ की कमी को शीघ्र पूरा किया जाएगा । एक इन्होंने प्राईमरी स्कूलों के स्ट्रक्चर को मजबूत कैसे किया जाएगा, यह सवाल पूछा है । इन्होंने कहा है कि अगर प्राईमरी स्कूल का स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा, तो आगे कैसे इम्प्रूवमैंट लाएंगे ? इनकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि हर गांव में प्राईमरी स्कूल खुले हुए हैं । लेकिन आगे भी हर साल हम 100 नये प्राईमरी स्कूल्ज गांवों में खोल रहे हैं । आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के प्रयत्न से वर्ल्ड बैंक के तहत 160 करोड़ रुपये मन्जूर हुए हैं, 4 जिले सिलैक्ट कर लिये गए हैं । अभी काम शुरू किया गया है और 4 ऐसे जिलों को सिलैक्ट किया गया है, जहां पर महिला एजुकेशन की कमी है । प्राईमरी एजुकेशन का ढांचा वहां पर भी मजबूत किया

जाना है । हमारे अधिकारी स्कूलों में इन्सपैक्शन के लिए जाते हैं । डायरैक्टर लैवल पर कई अधिकारियों को इन्सपैक्शन के लिए भेजा गया है उसके बाद डी० ई० ओज० तथा बी० ई० ओज० के लैवल पर भी इन्सपैक्शन स्कूलों की की जा रही है । डायरैक्टर लैवल पर अभी 90 स्कूलों का इन्सपैक्शन किया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, मैंने पर्सनली भी कई स्कूलों को विजिट किया है । डायरैक्टर ने खुद कई स्कूलों को इन्सपैक्ट किया है । इस तरह से इन्सपैक्शन को पूरी तरह से स्ट्रैथन किया जा रहा है । दूसरे रिजल्टस को इम्प्रूव करने के लिए टीचर्ज बच्चों की तरफ पूरा ध्यान दें, इस बात को देखा जा रहा है तथा मंथली टैस्ट भी होते हैं, क्वार्टरली टैस्ट भी होते हैं और फाईनल एग्जामिनेशन के अलावा दिसम्बर टैस्ट्स भी स्कूलों में लिए जा रहे हैं जिससे शिक्षा के स्तर में काफी सुधार हुआ है ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए क्या टीचर्ज के स्टैंडर्ड को स्ट्रैथन करने की कोई कार्यवाही की गई है ? मन्त्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि टीचर्ज स्कूलों में कई गलत बातें भी करते हैं, हुक्का पीते हैं या ड्रिंक्स भी लेते हैं। क्या उनकी जानकारी में यह बात है कि कोई टीचर हुक्का पीते हुए स्कूल में पकड़ा गया था ? स्कूल में हुक्का पीने वाले या ड्रिंक करने वाले टीचर्ज को पकड़ कर सजा देने या स्कूल की नौकरी से हटाने बारे क्या कोई कार्यवाही की जाती है ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या शीशर खरबला हाई स्कूल में हैड मास्टर ने चार्ज लेते ही 2 लाख रुपये का गबन किया था ? मैं यह बात इसलिए इनसे पूछ रहा हूं कि इस बारे में लोग इनसे मिले थे और मामला इनके नोटिस में है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उस हैड मास्टर के खिलाफ महकमे ने क्या सोचा है और इस प्रकार की जो कुप्रथा है, इसको बन्द करने बारे में महकमा क्या कर रहा है ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मक्कड़ जी ने पहला जो सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि टीचर्ज को एक्सट्रा ट्रेनिंग दी जाती है । टीचर्ज की ट्रेनिंग इस प्रकार से दो तरह की हो जाती है । एक तो मास्टर लगने से पहले जे० बी० टी० या बी० एड० की ट्रेनिंग तो होती ही है । उसके बाद सर्विस में आने के बाद टीचर्ज को इन-सर्विस ट्रेनिंग भी दी जाती है तथा डिस्ट्रिक्ट लैवल पर भी उन को इन-सर्विस ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि उनके पढ़ाने का स्तर ऊंचा हो सके और इस बारे में भी हम दो सैन्टर खोलने जा रहे हैं । दूसरे, इन्होंने कहा कि कोई मास्टर हुक्का पीते हुए पकड़ा गया था, तो उस बारे में हम ऐक्शन लेंगे । इन्हें सिफारिश करने की जरुरत नहीं है । (विघ्न) तीसरा जो इन्होंने सवाल पूछा है वह आगे भी आ रहा है । उस समय ही मैं इसका जवाब दे दूंगा ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसी भी स्कूल का अच्छा परीक्षा फल निकालने के लिए हैड का होना

[डा० राम प्रकाश]

आवश्यक है। जहां हाई स्कूल, 10+2 स्तर के स्कूल और प्राईमरी स्कूलज में प्रिंसीपल्ज/हैड नहीं हैं, क्या सरकार इनको भरने की कोशिश करेगी, यदि हां तो यह पद कब तक भरे जाएंगे ।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है । हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी स्कूल प्रिंसीपल के बिना न रहे । इनको लगाने के दो तरीके होते हैं । एक तो डायरैक्ट लगते हैं और दूसरे बाई परमोशन लगते हैं । परमोशन के लिए तो हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है और डायरैक्ट के लिए एस० एस० एस० बोर्ड को और पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजीशन भेज रखी है । अभी तक उनकी तरफ से कोई रिकोमैंडेशन नहीं आई है । हमें आशा है कि हम इसे अगले सत्र तक पूरा भर पाएंगे ।

श्री सूरज मल : अध्यक्ष महोदय, मैं बहादुरगढ़ की बात करता हूं कि वहां पर दो सौ के करीब प्राईवेट दुकानें स्कूल के नाम से खोल रखी हैं । वहां पर पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं है । वे बच्चों को मैट्रिक तक ऐसे ही धकेल देते हैं । यह सिर्फ बहादुरगढ़ में ही नहीं, बल्कि सारी स्टेट में हो सकता है । तो क्या सरकार के पास ऐसे कोई समाधान हैं जिससे यह सारी धांधली बन्द हो सके ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, हमने स्कूलों को रिकोग्नाईज करने का काम ऐजुकेशन डिपार्टमैंट को सौंप दिया है । इन्होंने जो बात बताई थी, उस बारे में मुख्यमन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम एक ऐसा ला बनाने जा रहे हैं, जिससे इस प्रकार के स्कूलों पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा ।

Anganwari

*1030. **Shri Krishan Lal :** Will the Minister of State for Social Welfare be pleased to state whether it is a fact that the functions of Anganwari in Madlauda Block, District Panipat has been entrusted to a private institution; if so, the reasons thereof together with the name of said institution ?

Minister of State for Social Welfare (Capt. Ajay Singh) : Yes Sir. The Government of India has directed that one ICDS Project in the State should be implemented by a Voluntary agency. In accordance with these directions, Janta Kalyan Samiti, Rewari, a registered voluntary agency, has been entrusted with the Project.

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मडलौडा ब्लाक में आंगनवाड़ी स्कीम कब चालू की गई, जनता कल्याण समिति को कब सौंपी गई और कितने समय के लिए सौंपी गई है ? क्या इस ब्लाक

के अलावा प्रदेश में यह स्कीम किसी और नए ब्लाक में भी सौंपी गई है ? इस बारे में भी मंत्री जी पूरा ब्यौरा दें ।

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो पूछा है, उसमें इन्दरब्यू हो चुके हैं और आंगन वाड़ी के वर्कर्ज की सिलैक्शन हो चुकी है । उनकी ट्रेनिंग भी फरवरी में शुरू हो चुकी है । यह ट्रेनिंग 2 मई, 1995 को खत्म हो जाएगी । इसके अलावा, तीन ब्लाकस हैं उकलाना, भट्टूकलां और मंडलौडा । इन तीनों में आंगनवाड़ी स्कीम देने का विचार था । लेकिन एक ब्लाक को हमें यह देनी चाहिए थी, भट्टू-कलां में पहले से ही आंगनवाड़ी स्कीम चल रही थी और भारत सरकार के भी यह निर्देश थे कि अगर कोई स्वयं सेवी संस्था हो, तो उसको ही यह काम दिया जाए । अध्यक्ष महोदय, यह हमारे राज्य में ही नहीं है, बल्कि पूरे देश में है । चूंकि यह एक सामाजिक कार्य है, इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए ही यह कार्य जनता कल्याण समिति को दे दिया गया है । मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इनके ब्लाक में भी यह योजना मई में सुचारू रूप से चालू हो जाएगी ।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जनता कल्याण समिति रिवाड़ी को यह परियोजना कितने समय के लिए दी गयी है और इस पर खर्च कितना होगा तथा क्या इस परियोजना पर इन्वैस्टमैन्ट करने के लिए कल्याण समिति को पूरा पैसा खर्च करना होगा या फिर स्टेट गवर्नमैंट को भी इसमें पैसा खर्च करने के लिए देना होगा ?

कैप्टन अजय सिंह : स्पीकर साहब, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई अवधि नहीं दी गयी है । अगर यह समिति इस कार्य को ठीक करती रहेगी तो समिति इस कार्य को चलाती रहेगी । इसके अलावा, इन्होंने यह भी सवाल किया कि इस पर कितना खर्चा होगा ? अध्यक्ष महोदय, इस पर एक साल में 12.08 लाख रुपए खर्चा आएगा । कर्मचारियों को वेतन भत्ता डी0ए0 वगैरह भी इसी पैसे में आ जाएगा । लेकिन इस स्कीम में खाने का जो सामान देना होगा, उसको हमारी सरकार देगी यानि वे खुद सामान परचेज नहीं करेंगे । जो भी सामान और ब्लाकों में दिया गया है, वही सामान इनको भी दिया जाएगा ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जनता कल्याण समिति रिवाड़ी ने और कितने ब्लाकों में यह स्कीम ली है तथा इस समिति ने जो कर्मचारी भर्ती किए हैं क्या वे टैम्पोरेरी तौर पर भर्ती किए हैं या परमानैन्ट तौर पर किए हैं ? क्या सरकार इन कर्मचारियों को तन-ख्वाह देगी या फिर प्राईवेट समिति ही तनख्वाह देगी तथा सरकार ने किस बेसिज पर इस समिति को यह ब्लाक दिया है ?

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया है कि केवल एक ही ब्लाक में यह स्कीम इस समिति को दी गयी थी । इस संस्था में काफी स्कीम्ज

[कैप्टन अजय सिंह]

हैं, जो भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि और भी बहुत सी 20-25 स्कीम्ज हैं जिनकी मेरे पास लिस्ट हैं । इसके अलावा, सोशल एडवाइजरी बोर्ड की भी स्कीम्ज दी हुई हैं, जिनकी मेरे पास लिस्ट हैं । अगर आप कहें तो मैं इनको पढ़ कर बता सकता हूं लेकिन पढ़ने में काफी समय लगेगा ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह बात ठीक है कि ये स्कीम तो भारत सरकार की ही है, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इन स्कीमों को लागू करने के लिए प्राईवेट समिति को देने का क्या क्राईटेरिया है ?

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका क्राईटेरिया कुछ नहीं होता । चार संस्थाएं इसके अंदर आयी थीं । ये संस्थाएं हैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, अखिल भारतीय महिला परिषद, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय मैमोरियल ट्रस्ट और जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी । जो भी संस्था मैरिट में ऊपर आयी, उसको ही यह काम दिया गया ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : स्पीकर साहब, जो सरकारी कर्मचारी सोशल वैलफेयर विभाग के हैं, क्या वे यह स्कीम को लागू करने में सक्षम नहीं थे; प्राईवेट एजैंसी को ही यह काम चलाने की इजाजत क्यों देनी पड़ी ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ठीक ही जवाब दिया है । भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को बार-बार कहा कि आपको किसी वालन्ट्री एजैंसी को ही यह काम देना चाहिए, तब हमने 1992 में यह काम इस वालन्ट्री एजैंसी को एक ब्लाक में दिया है । अगर आपके पास भी कोई और वालन्ट्री एजैंसी हो, और आप जिस ब्लाक का उसको काम दिलाना चाहें, तो बतायें । सरकार सबसे पहले उसको यह काम दे देगी क्योंकि यह तो एक सामाजिक सेवा का काम है । जो संस्था समाज की सेवा करना चाहती है और अपने पास से पैसा लगा कर बच्चों का जीवन सुधार करना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है । अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास कोई इस तरह की संस्था है, तो उसको हमारे पास भेजें । हम उसको और कोई ब्लाक इस काम के लिए दे देंगे ।

Institution of Maharishi Balmiki Chair

*1029. **Dr. Ram Parkash :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to institute the Maharishi Balmiki's Chair in any University of Haryana;

(b) if so, the name of the University together with the time by which it is likely to be instituted ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana) :

(a & b) Yes, there is a proposal under consideration of the Government to institute Maharishi Balmikis Chair in Kurukshetra University of Haryana.

डा0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह जो शुभ कार्य करने का आश्वासन माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, उस बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आदि कवि महर्षि बाल्मीकि के नाम पर जिस चेयर की स्थापना की जाएगी, वह टीचिंग-कम-रिसर्च के लिए होगी या केवल रिसर्च के लिए होगी और इसका क्षेत्र क्या होगा ? दूसरे क्या ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो नया एकैडेमिक सैशन जुलाई से प्रारम्भ होगा, उससे पहले सारी फौर्मलिटीज पूरी कर ली जाएं ताकि इस चेयर की स्थापना हो सके ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह जान कर खुशी होगी कि माननीय मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ने करनाल में 19-10-94 को बाल्मीकि सभा में घोषणा की कि बाल्मीकि चेयर की स्थापना की जाएगी । उसी समय विभाग ऐक्शन में आया और यूनिवर्सिटीज से ऑप्शन मांग ली कि कौन इस चेयर की स्थापना करने के लिए तैयार है ? डाक्टर साहब की इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र में शुरु हो । सबसे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑफर दी । आदरणीय मुख्य मंत्री जी की ओर से केस अप्रूव करके तुरन्त फाइनैंस डिपार्टमैंट को भेज दिया गया है और मुझे आशा है कि बहुत जल्द इस पर कार्य शुरु हो जाएगा । जहां तक डाक्टर साहब ने पूछा है कि इस पर क्या कार्य होगा ? अध्यक्ष महोदय, सारे समाज का जो दबा हुआ तबका शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास का है, उस पर शोध कार्य होगा और आदि कवि महर्षि बाल्मीकि, जो संस्कृत के बड़े भारी कवि थे, उनकी पोइट्रिक इन्टर-प्रैटेशन है, उस विषय पर भी पूरा शोध कार्य होगा ।

Construction of Roads

***1046. Chaudhri Bharath Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from village Sajuma to Dubal and Guhna and from Singwal to Shimla of Distt. Kaithal; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be constructed ?

Public Works Minister (Chaudhri Amar Singh) :

(a) No Sir.

(b) In view of (a) above question does not arise.

चौधरी भरथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सजूमा से गुना तक और सजूमा से दुबल तक सड़क बनाने से सरकार को फायदा होगा क्योंकि इन सड़कों पर बसें चलने लगेंगी, इसलिए ये सड़कें बननी चाहिएं। इसके अलावा शिमला से सिंगवाल तक भी सड़क बनाने का सरकार का कब तक विचार है ?

चौधरी अमर सिंह : स्पीकर सर, सजूमा से दुबल तक 7 किलोमीटर की सड़क है और निर्माण लागत 28 लाख रुपये है लेकिन गांव सजूमा पहले ही दोनों तरफ से मिला हुआ है और दुबल भी एक तरफ से मिला हुआ है। इसलिए यह सड़क बनाने का प्रावधान नहीं है। सजूमा से गुना तक यह 4.5 किलोमीटर की सड़क है और 43 लाख रुपये इस पर लागत आएगी क्योंकि बीच में एक ड्रेन पड़ती है, यह सड़क निर्माणाधीन है। इसके बनने से गांव गुना से किलायतपुर बिना लम्बे रास्ते के तय किए जा सकेंगे। इसी तरह सिंगवाल से शिमला, इस सड़क की लम्बाई 3.9 किलोमीटर है। गांव शिमला पहले ही नरवाना कैथल सड़क से जुड़ा हुआ है और सिंगवाल-मंडी सड़क पर स्थित है। इस प्रकार यह सड़क एक दोहरी सड़क है। इसको भी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। स्पीकर सर कलायत में कुल 153.65 किलोमीटर की लम्बाई की सड़क पड़ती है। इनका पैच-वर्क किया गया है और ये सड़कें बिल्कुल ठीक हैं। एक सड़क चौसाला से मटोर तक की 6.60 किलोमीटर 10.00 बजे | लम्बी है। उस पर लगभग 24 लाख 13 हजार रुपये खर्च आने वाला है जिसमें से 5.34 किलोमीटर सड़क पर काम चल रहा है और 1 किलोमीटर सड़क पर अर्थ वर्क हो गया है। इसलिये 15/8 तक यह सड़क बनाकर जनता के सुपुर्द कर दी जाएगी।

Case of Embezzlement

***1052. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any case of embezzlement in the School of village Sisar-Kharbala, Tehsil Hansi, District Hissar has come into the notice of Government during the year 1993-94 ; and

(b) if so, the total amount involved therein togetherwith the names of the officers/officials held responsible for the aforesaid embezzlement and the action taken against them ?

शिक्षा मन्त्री (श्री फूल चन्द मुलाना) :

(क) जी हां ।

(ख) श्री हरि सिंह, मुख्याध्यापक के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी हिसार द्वारा दर्ज करवाई गई एफ0 आई0 आर0 के अनुसार स्कूल के फण्डों से 2,01,246.21 पैसे की राशि अनियमित तौर पर निकलवाई गई तथा इस मुख्याध्यापक को राशि अनियमित तौर पर निकलवाने के लिये जिम्मेदार ठहराया गया है । पुलिस स्टेशन नारनौंद में एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवाई गई तथा इस मुख्याध्यापक को निलम्बित किया गया ।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक हैडमास्टर को 3-11-93 को सस्पैन्ड किया गया और 18-10-94 को उसको बहाल कर दिया । इस मास्टर ने केवल 15-16 दिनों में 13-9-93 से 28-9-93 तक 2 लाख रुपये का गबन किया था । क्या यही एजुकेशन का स्तर है ? इस तरह से सरकारी कर्मचारी पैसे का गबन करके, उसका दुरुपयोग करते हैं और स्कूलों के कमरों के अन्दर बैठे शराब पीते रहते हैं । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के कितने केसिज़ सरकार के नोटिस में हैं ? अगर इस प्रकार बच्चों के पैसों का गबन का मामला चलता ही रहेगा तो शिक्षा का क्या स्टैण्डर्ड होगा; बच्चों के भविष्य का क्या होगा ? अगर इसी तरह से फण्ड्ज़ का दुरुपयोग होता रहा तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा आएगा, शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर उठेगा ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस तरह के टीचर्ज़ जोकि पैसे ले ले कर रखे गये हों, क्या उनको इस तरह से खुला छोड़े रखेगी ताकि वे अपनी कमाई करते रहें ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का हो सकता है । सरकार का यह फर्ज़ बनता है कि जब भी कभी कोई ऐसी बात उसके नोटिस में आये तो उस पर फौरन कार्यवाही की जाए । जब यह मामला हमारे नोटिस में आया हमने उसी वक्त उस अध्यापक को सस्पैन्ड किया और उसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज करवायी । वह हैड मास्टर 3-11-93 को सस्पैन्ड हुआ और 19-9-94 को बहाल हुआ लेकिन बहाल करने के बाद हमने उसको उस हक से वंचित कर दिया और उससे डी0 डी0 ओ0 की पावर्ज़ भी छीन लीं ताकि वह आगे से ऐसा काम न कर सके । श्री राम भजन जी शिक्षा के गिरते हुए स्तर से बहुत चिंतित हैं । लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है । अगर हमें बच्चों की शिक्षा के बारे में चिन्ता है, तो हमें अध्यापकों से काम लेना ही होगा । कोर्ट के फैसले के अनुसार हम सस्पैंडिड व्यक्ति से काम नहीं ले सकते । केवल उसे तनख्वाह ही दे सकते हैं । अगर कोई सस्पैन्ड होगा तो वह सरकारी काम नहीं कर पाएगा । इसीलिये हमने उसको बहाल कर दिया और उसे बहुत दूर के स्कूल में लगा दिया

[श्री फूल चन्द मुलाना]

ताकि वह पढ़ाने का काम तो करता रहे । जब ऐसा कहीं केस नोटिस में आएगा तो उस पर अवश्य कार्यवाही भी होगी । केवल पढ़ाने के लिये उस अध्यापक को दूर के स्कूल में लगा दिया गया है लेकिन उसको यह हक नहीं होगा कि वह कोई पैसा ड्रा/खर्च कर सके । फिर इन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास इस तरह के कितने केसिज हैं । जो भी इस तरह के केसिज आते हैं, उन पर पूरी तरह से कार्यवाही होती रहती है । विभाग में ऐसे केसिज पर अवश्य कार्यवाही की जाती है । ऐसे केसिज पर पूरी तरह से चैक हो, स्कूलों में हर प्रकार से कार्य ठीक से चले, तभी हमने इस तरह की इंस्पैक्शन के कार्य को सुदृढ़ बनाया है और आगे से रैगुलर इंस्पैक्शन भी होगी । जो इररैगुलैरिटी होगी, उस के ऊपर कार्यवाही होगी ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसी बारे में पहले भी पूछा था कि इस हैडमास्टर ने इस स्कूल से पहले भी क्या कहीं पर इतना ही गबन किया था ? इसको सस्पैन्ड किया गया और एफ0 आई0 आर0 भी उसके खिलाफ दर्ज है । इसके बाद आया उसको परमोट भी किया गया था नहीं या उसको हैडमास्टर ही रहने दिया गया था कि प्रिंसिपल बना दिया गया है ? जो जांच इस केस में चल रही है, क्या आगे उस पर कार्यवाही हो रही है या नहीं ? लोगों ने वहां पर इसी रोष में उस स्कूल को ताला लगा रखा था । क्या ऐसे आदमी को परमोट तो नहीं कर दिया गया ?

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी सूचना नहीं है । हमारे यहां कुछ केसिज में भर्ती बाई परमोशन होती है और कुछ में बाई डायरैक्ट रिक्रूटमैंट होती है । यह अध्यापक डायरैक्टली प्रिंसिपल सिलैक्ट हो गया था, पब्लिक सर्विस कमिशन से । लेकिन हमने इसको प्रिंसिपल लगने नहीं दिया । वह केवल हैड मास्टर का कार्य कर रहा है । वह प्रिंसिपल के तौर पर कार्य नहीं कर रहा है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1055

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी सूरज भान काजल सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Aucation of Land of Municipal Committee/Council, Palwal

***1073. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any land of Municipal Committee/Council of Palwal was auctioned in the year 1993-94; if so, the amount received therefrom ?

Minister of State for Local Government (Chaudhari Dharambir Gauba) : Municipal Committee/Municipal Council Palwal, had not auctioned any land during the financial year 1993-94 (*i.e.* from 1-4-93 to 31-3-1994). Therefore, the question regarding amount received does not arise.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल पलवल की म्युनिसिपल कमेटी के बारे में दिया था । मैंने सवाल में लिखा था कि 1993 से ले कर 1994 तक क्या पलवल म्युनिसिपल कमेटी की कोई जमीन बेची गई । माननीय मन्त्री महोदय ने सवाल को वर्ष 1993-94 का बना दिया । इसका मतलब तो यह निकलता है 1-4-93 से 31-3-94 तक । अध्यक्ष महोदय, वहां पर डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन बेची गई है । सरकार ने अपने ही बनाए हुए नियमों को ताक पर रख दिया है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो लोग रहते हैं, उनके घरों के आगे प्लाट बना-बना कर जमीन बेची गई है । मैं आपके द्वारा सारे सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले साल भी मैंने यह सवाल किया था तो मन्त्री महोदय ने खड़े हो कर कहा था कि इसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते; हमें समय दिया जाए । आज जब यह सवाल आया है तो इन्होंने साफ मना कर दिया है कि कोई जमीन नहीं बेची गई । मैं बताना चाहता हूं कि पलवल में डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन बेची गई है । चौधरी देवी लाल के समय में गुड़गांव में एक करोड़ रुपए की जब जमीन बेची गई थी तो यहां हो-हल्ला मचा था । यह सरकार जान-बूझ कर इसको दबाना चाहती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी के नोटिस में यह बात है कि पलवल में डेढ़ करोड़ रुपए की जमीन 1993 से दिसम्बर, 1994 तक बिकी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : क्या आप श्योर हैं कि आपका क्या क्वैश्चन था ?

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, वह यह है :—

> "Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether any land of Municipal Committe./Council of Palwal was auctioned in the year 1993-94 ; if so, the amount received therefrom ?"

इसका जवाब मैंने क्लीयर कट दिया है । अब इन्होंने जो सप्लीमैंटरी पूछा है, उसका जवाब यह है कि वर्ष 1994-95 में वहां पर 1 करोड़ 33 लाख 29 हजार तीन सौ निन्यानबे रुपए की जमीन नीलाम की गई है । वहां पर जो 79 प्लाट नीलाम किए गए हैं, उनमें चार प्लाट दलाल साहब के भी हैं । स्पीकर साहब, यह वही जमीन है जिस पर 30-40 साल से लोगों ने इन्क्रोचमैंट कर रखी थी । हमने उस इन्क्रोचमैंट को हटाया है । यदि वह जमीन वैसे ही पड़ी रहती तो फिर लोग उस पर दोबारा इन्क्रोचमैंट करते क्योंकि वह जमीन मकानों के बीच में है । उस जमीन के बारे में यह फैसला हुआ कि उसको डी० सी० से परमिशन ले कर नीलाम किया

[चौधरी धर्मवीर गाबा]

जाए और डी0 सी0 से परमिशन ले कर एस0 डी0 एम0 ने वह जमीन नीलाम की है ताकि उस पर दोबारा इन्क्रोचमैंट न हो । वह जमीन म्युनिसिपल कमेटी के काम नहीं आ सकती । उस जमीन को डी0 सी0 से परमिशन ले कर 1 करोड़ 33 लाख 29 हजार 399/- रुपये में नीलाम किया गया है । वह सारा पैसा पलवल म्युनिसिपल परिषद के अन्दर डिवैल्पमैंट पर खर्च किया गया है । वहां पर इतनी जबरदस्त डिवैल्पमैंट हुई है, अगर आप कहें, तो मैं उसकी डिटेल बता सकता हूं । वहां पर डिवैल्पमैंट पर 1 करोड़ 46 लाख 53 हजार 891/- रुपए खर्च किए गए हैं ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मंत्री जी ने यह कहा है कि वहां पर मैंने चार प्लाट लिए हैं तो क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि मेरे नाम से वहां पर कौन-कौन से प्लाट्स हैं ? क्या मैंने वह प्लाट बोली लगा कर लिए हैं या किस तरीके से लिए हैं ? एस0 डी0 एम0 ने अपने घर में बैठ कर उन प्लाटों को नीलाम किया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि वह जमीन डी0 सी0 से परमिशन ले कर नीलाम की गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा राज्य के जो कानून हैं, वे इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई भी एस0 डी0 एम0 इस तरह से जमीन को नीलाम कर सकता है ? इस हरियाणा प्रदेश में पता नहीं कितने लोगों ने म्युनिसिपल कमेटीज की जमीनों पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी म्युनिसिपल कमेटीज में जिन-जिन लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनको पलवल म्युनिसिपल कमेटी की तरह हटा कर नीलाम किया जाएगा ?

चौधरी धर्मवीर गाबा : स्पीकर साहब, केवल पलवल म्युनिसिपल कमेटी की ही बात नहीं है, जहां जहां पर भी नाजायज कब्जे हैं और जो जमीन म्युनिसिपल कमेटी के काम नहीं आ सकती उन जमीनों को कब्जे में ले कर नीलाम करने का हमारा प्रयास जारी है । वह थोड़ी-थोड़ी जमीन है, जिस पर न कोई सरकारी बिल्डिंग बन सकती है और न ही कोई कम्पलैक्स बन सकता है ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह जमीन डायरैक्टर की परमिशन ले कर नीलाम की गई है ?

श्री अध्यक्ष : आपका मेन लिखा हुआ क्वैश्चन यह है —

> "Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—has any land of Municipal Committee/ Council, Palwal been auctioned in the year 1993-94 if so....."

तो मंत्री जी ने 1-4-93 से 31-3-94 तक का आपको जवाब दे दिया ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैंने मूल रूप में जो सवाल लिख कर आपके यहां दिया था, वह अपने हाथ से लिख कर दिया था । आप वह मंगवा कर देखें ।

श्री अध्यक्ष : उसमें आपने यही तो लिखा था ।

Chaudhri Dharambir Gauba : Under the Haryana Municipalities Management of Municipal Properties and State Properties Rules, 1976, the permission of the D.C. was obtained by S.D.M.

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, डी० सी० और एस० डी० एम० ने पैसा खाया है । उस जमीन को नीलाम करने के लिए राज्य सरकार से कोई परमिशन नहीं ली गई ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, जिसके बारे में डी० सी० परमिशन देने के लिए कम्पीटेंट हैं, उसकी डायरैक्टर से क्यों परमिशन लेंगे ? Under the Haryana Municipalities Management of Municipal Properties and State Properties rules, 1976 the permission of the D.C. is to be obtained and not of the Director.

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कर्ण सिंह दलाल ने मर्किट कमेटी पलवल की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह कब तक खाली करवा ली जाएगी ? इसी प्रकार से कर्ण सिंह दलाल ने गांधी समुदाय की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है, वह कब तक खाली करवा ली जायेगी ? इसके अलावा कर्ण सिंह दलाल ने जितने कब्जे कर रखे हैं व जिन पर दुकानें बना रखी हैं, कब तक खाली करवा ली जायेंगी ? (शोर)

Mr. Speaker : Next question please,

वाक आउट

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, ये बे-बुनियाद बात कह रहे हैं । मेरे सवाल का जवाब मंत्री जी की तरफ से नहीं आ रहा । यदि सरकार मेरे सवाल का जवाब नहीं देती और आप हमें और सप्लीमैंट्री पूछने की इजाजत नहीं देते तो हम विरोध स्वरूप वाक-काउट करते हैं ।

(इस समय विपक्ष के सदस्य सर्वश्री कर्ण सिंह दलाल, छतर सिंह चौहान तथा राम भजन अग्रवाल सदन से वाक-आउट कर गए ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Dowry case in Rohtak

*1090. **Chaudhri Om Parkash Beri :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of dowry cases registered in Civil Lines Police Station, Rohtak, during the month of June, 1994 togetherwith the action taken thereon ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : दो मुकदमें दर्ज हुए । धारा 304-बी/498-ए भा0 द0 स0 और 406/498-ए भा0 द0 स0 के अन्तर्गत एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया । इन दोनों मुकदमों का चालान न्यायालय में दिया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुकदमा नं0 237 दिनांक 12-6-94 अंडर सैक्शन 304-बी/498-ए आई0पी0सी0 में, क्या मुख्य मन्त्री के आदेश पर क्राईम ब्रांच के इन्सपैक्टर चमन लाल री-इन्वैस्टीगेशन कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसकी प्रोग्रैस क्या है ? क्या यह भी सही है कि इस केस में इम्पोर्टेंट ऐवीडैंस श्री धर्मचन्द के बयान की ओडियो कैसेट तथा मृतका के पिता करतार सिंह का जो पूरक बयान है, उसको इग्नोर कर दिया है ? क्या यह सही नहीं कि मरने वाली पूनम डाउरी के केस के कारण तो नहीं मरी ? दूसरे मैं बताना चाहूंगा कि इस केस में धारा 406 लगनी चाहिए थी, वह नहीं लगायी गई । जरा मुख्य मन्त्री महोदय क्या इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस मरने वाली लड़की ने छत से छलांग लगा कर खुदकशी की है । उसने एक चिट्ठी लिखकर छोड़ी थी । उस चिट्ठी के मुताबिक उसके पति, देवर, ससुर का कोई जिक्र नहीं था । सिर्फ यह लिखा था कि उसकी सास उसे तंग करती थी, इसलिए वह खुदकशी कर रही है । इसीलिए उसकी सास के खिलाफ केस दर्ज किया गया और चालान किया गया । बाद में लड़की के पिता ने एक एप्लीकेशन दी कि इसमें इसके पति को, ससुर को और ननद व देवर को भी गिरफ्तार किया जाये । इसकी जांच की गई लेकिन जांच में डी0एस0पी0 और एडीशनल एस0पी0 की रिपोर्ट से यही निष्कर्ष निकला कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है । मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी इस केस की इन्क्वायरी चल रही है । यह इन्क्वायरी हमारा जो क्राईम ब्रांच का स्पैशल स्टाफ है, उस द्वारा की जा रही है । अभी इस केस में वारसान (लड़की के पिता) की तसल्ली नहीं हुई है, इसलिए इस केस की कोर्ट से इजाजत लेकर दुबारा इन्क्वायरी करने की परमिशन 11/94 में ले ली गई है । जांच अभी चल रही है । इतना ही नहीं, हमने इस केस में धारा 406 भी लगा दी है और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सप्लीमैंटरी चालान पेश किया जाएगा ।

Sale of Lottery Tickets

*1092. **Prof. Sampat Singh** : Will the Minister for Finance be pleased to state the total amount received from the Sale of State run Lottery tickets during the year 1994-95 togetherwith the profit earned therefrom during the said period ?

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) :

Total sale proceeds of lottery tickets during 1994-95 upto 28-2-1995	Rs. 2789.91 Crores
Estimated profit upto 28-2-1995	Rs. 73.89 Crores

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री श्री गुप्ता जी ने जो फिगर्ज दी हैं, वे काफी अलार्मिंग फिगर्ज हैं । इन्होंने बताया है कि 2789.91 करोड़ रुपये के टिकट बिके और आमदनी केवल 73.89 करोड़ रुपये हुई । अध्यक्ष महोदय, लाटरी आम आदमी खरीदता है । इस साल का अभी एक महीना और रहता है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि 2789.91 करोड़ रुपये में कुल बैनिफिट 73.89 करोड़ रुपये हुआ है । बाकी के जो बैनिफिशरीज हैं, वे कौन लोग हैं और इतनी एमाउंट किसको किस काम के लिए दी गई है ? स्पीकर सर, इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल यह है कि लाटरी की जो टिकटें छपती हैं, क्या उनको छपवाने के लिए सरकार ने कोई टैंडर इन्वाईट किया था और अगर टैंडर इन्वाईट किया था तो क्या जिसने कम से कम रेट दिया था उसी को ही छपाई का काम दिया गया था किसी अन्य व्यक्ति से ये टिकटें छपवाई गई हैं ? स्पीकर सर, इसके साथ ही एक और सवाल मैं माननीय मांगे राम गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी अपनी प्रिंटिंग प्रैस है, तो प्राईवेट लोगों से ये छपाई क्यों करवाई जा रही है और आप इन टिकटों की छपाई अपनी प्रैस में क्यों नहीं करवाते ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी बहुत ही समझदार आदमी हैं । मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोगों की दिक्कत को समझते हुए या इसको एक सामाजिक बुराई समझते हुए सरकार ने पहले ही लाटरी को बन्द करने का फैसला ले लिया है । दूसरे स्पीकर सर, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि लाटरी की स्कीम आज की वर्तमान सरकार ने नहीं चलाई थी, 1968 से हरियाणा में लाटरी स्कीम चल रही है और सभी सरकारों के वक्त में रही । चौधरी बंसी लाल जी की सरकार रही हो, चाहे चौधरी भजन लाल जी की सरकार रही, या दूसरी सरकारें रहीं, लाटरी की स्कीम चलती रही । यह स्कीम जिस तरीके से पहले से चल रही थी और जैसे टिकटें छपती और बिकती थीं, हमने उसमें कोई चेंज नहीं की । अध्यक्ष महोदय, यहां पर इन्होंने यह कहा कि इतनी टिकटें छपीं और फायदा कम हुआ । अध्यक्ष महोदय, ये समझदार आदमी हैं और इनको पता भी है कि 20

[श्री मांगे राम गुप्ता]

रुपये की टिकटों के ब्लाक में से 18 रुपये तो टिकट खरीदने वाले को ही मिलते हैं सिर्फ 2 या अढ़ाई परसैंट, प्रैस का खर्च, हमारे सारे खर्च वेजिज वगैरा निकाल कर जो बचता है, वह प्रोफिट है। यह दो या अढ़ाई परसैंट को रायल्टी मान लें या कमीशन कह लें (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं चौधरी सम्पत सिंह जी को यह भी बताना चाहूंगा कि इनके समय में जो टिकटों की छपाई होती थी, उस रेट से कम रेट पर हम टिकटें छपवा रहे हैं हालांकि उसके बाद कागज के रेट्स भी बढ़े हैं और वेजिज भी ज्यादा देने पड़ रही हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे यह जानना चाहा था कि क्या छपाई के लिए इन्होंने टैंडर काल किये थे या कि नहीं ? अब अगली छपाई के लिए कोई और टैंडर काल किया गया है या कि नहीं ?

श्री मांगे राम गुप्ता : जब हमने लाटरी बन्द करने का फैसला ले लिया है, तो फिर टैंडर काल करने की क्या आवश्यकता है ? बाकी जो पहले टैंडर की बात है, उसके बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि इन्होंने खुद क्या रेट्स दिए थे (विघ्न) स्पीकर सर, यह रिकार्ड की बात है। मैं इनकी जानकारी के लिए इन्हें बताना चाहूंगा कि जिन रेट्स पर इन्होंने टैंडर एक्सैप्ट किया था, उसके बाद हालांकि कागज की कीमतें बढ़ी हैं, और वेजिज भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन रेट्स से हमने कम रेट्स पर छपवाई करवाई है।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इनके राज में 1987-88 में टोटल इन्कम 38.71 करोड़ रुपये हुई थी और खर्च जो हुआ था वह 35.43 करोड़ रुपये हुआ था। सिर्फ 3 करोड़ रुपये बचत सरकार को हुई। 1988-89 में 69.73 करोड़ रुपये की सेल हुई और खर्चा हुआ 62.56 करोड़ रुपये और इसमें इन्कम हुई 7.17 करोड़ रुपये की। 1989-90 में सेल हुई 103 करोड़ रुपए की और खर्चा आया 93 करोड़ रुपये का, इसमें इन्कम 10 करोड़ रुपये की हुई। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बहुत बड़ी डिटेल दी है। अब मैं इनकी बात पर ही सवाल पूछ रहा हूं। इन्होंने जो फिगर्ज दी हैं, वह ठीक ही दी होंगी। अध्यक्ष महोदय, 38 करोड़ में से 35 करोड़ का खर्चा आया और उसमें से 3 करोड़ बच गए। इसका मतलब यह हुआ कि 9 प्रतिशत प्रोफिट हुआ। अगर हम 2789 करोड़ रुपए का 9 प्रतिशत लगाएं तो तकरीबन यह 250 करोड़ बनता है। उस रेशो के हिसाब से टोटल एम्बैजलमैंट पौने दो सौ करोड़ रुपए की बनती है। अब ये बताएं कि वह पैसा किसको दिया ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि यह पैसा कहां गया ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इनको बताना चाहता हूं कि इनके टाईम में 10 टिकटों का ब्लाक 20 रुपए का था और ये वापिस 16 रुपए देते थे । हमने इसको इम्प्रूव किया है कि जो भी ब्लाक खरीदेगा, उसको 18 रुपए दिए जाएंगे और जो ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहां गया है तो यह जो हम 18 रुपए देते हैं, वहां पर गया है ।

Prof. Sampat Singh : I am saying nearly 9%. It will be 8%. It means that the amount has been paid to the commission agents.

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह कमीशन एजेंट नहीं हैं । जो भी टिकटों का ब्लाक खरीदता है, हम उसको 18 रुपए देते हैं । ये तो अपने टाईम में 16 रुपए ही देते थे । हमने तो इनसे 2 रुपए ज्यादा दिए हैं और इस वजह से हमारी सेल भी बढ़ी है ।

प्रो0 सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप भी इस मामले को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं । गुप्ता जी ने फरमाया कि बेचने वाले को प्रोफिट देते हैं लेकिन जो गरीब आदमी दिन भर टिकट खरीदने में लगा रहता है, उसको क्या प्रोफिट दिया है ? उसको सुसाईड जैसा प्रोफिट दिया है । ये 75 करोड़ रुपए कमाने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं ।

श्री मांगे राम गुप्ता : हमने किसी भी एजेन्ट को कमीशन नहीं दिया है । जिसने भी 20 रुपए की टिकटों का ब्लाक खरीदा है, उसको 18 रुपए वापिस दिए हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखत उत्तर

Rejected Coal

*1105. **Shri Satbir Singh Kadian** : Will the Minister for Power be pleased to state—

(a) the yearwise total quantity of Coal purchased by the Thermal Power Plant, Panipat during the year 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1993-94 and 1994-95 ; and

(b) the total quantity of Coal, if any rejected out of the Coal as referred to above togetherwith the criteria adopted for the rejection of Coal ?

Power Minister (Shri Verender Singh) : A statement is laid on the table of the House.

"STATEMENT"

(a) The yearwise quantity of coal purchased for Panipat Thermal Power Station was as follows :—

Year	Quantity purchased (Lac Tonnes)
1987-88	11.52
1988-89	11.64
1989-90	15.15
1993-94	16.78
1994-95 (Upto 12/94)	12.88

(b) No rejection of received coal is made except for visible stones and boulders which are removed. However, the coal grinding mills reject some quantity of poor grage coal and stones etc. The yearwise details of coal rejected by mills is as follows :—

Year	Quantity rejected (Tonnes)
1987-88	21,126
1988-89	24,216
1989-90	40,625
1993-94	85,166
1994-95 (Upto 12/94)	62,093

Construction of Road

*1168. **Sardar Jaswinder Singh** : Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from village Adhoya to Kraha Saheb of district Kurukshetra, if so, the number of culverts proposed to be constructed on the said road ?

Public Works Minister (Chaudhri Amar Singh) : Yes Sir, 16 Nos. culverts are under construction.

Damaged Road

*1174. **Shri Daryao Singh :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state the time by which the damaged road from village Ahari to Kulana is likely to be repaired ?

Public Works Minister (Chaudhri Amar Singh) : Patch work (repair) on the road from Ahari to Kulana has been done.

राज्यपाल से सन्देश

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a letter from the Governor, which reads as under :—

> "Thank you so much for your communication No. HVS-LA-36/95/4659, dated 10th March, 1995, sending therewith a copy of the 'Motion of Thanks' on my address passed by Haryana Vidhan Sabha on 10th March, 1995."

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री द्वारा लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखा जाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Notice No. 25, given notice by Shri Ram Bilas Sharma, regarding the non-availability of kerosene oil and wheat on ration shops and black-marketing of these items. I admit it. Shri Ram Bilas Sharma may read his notice.

(As Shri Ram Bilas Sharma was not present in the House, the notice of motion was not read)

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम बिलास जी तो इस समय किसी कारणवश हाउस में उपस्थित नहीं हैं लेकिन आपने उनकी मोशन ऐडमिट कर ली है । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हाउस की जानकारी के लिए इस मोशन का जवाब दे सकता हूं । मेरे पास यह लिखित में स्टेटमैंट है ।

श्री अध्यक्ष : आप इस स्टेटमैंट को हाउस की टेबल पर रख दें ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : ठीक है जी : मैं रख देता हूं ।

[श्री महेन्द्र प्रताप सिंह]

Sir, With your permission, I beg to lay on the Table —

A copy of statement* in respect of Calling Attention Notice No. 25, given notice of by Shri Ram Bilas Sharma, regarding non-availability of kerosene oil and wheat on ration card-shops and black marketing in the State.

— — —

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/नियम 84 के अधीन प्रस्तावों की सूचनाएं

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने और मेरी पार्टी के सभी एम०एल०एज० ने एक कालिंग अटैन्शन मोशन दी है जिसमें हमने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की जमीनों के आक्शन के आर्डर हो चुके हैं । नारनौल और रिवाड़ी के डी०सीज० की कोठी, दफ्तर, ऐक्सियन के दफ्तर और रैंजीडैंस तथा नारनौल कैनाल रैस्ट हाऊस के आक्शन के आर्डर हो चुके हैं । किसानों को जो दो करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया है, उसके बदले में यह आर्डर हुए हैं । इसका मतलब फाईनैंशियल क्राईसिज है ।

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन अभी अंडर कंसीड्रेशन है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : सर, मेरा भी एक कालिंग अटैंशन मोशन था जो कि मैंने 9 तारीख को दिया था । यह मोशन पानीपत थर्मल पावर प्लांट के आस-पास के गांव जैसे खुखराड़ा, आसनकला, सकलाना खुर्द और जाटल आदि, में बड़ा ारी जो प्रदूषण फैल रहा है, के बारे में है ।

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन अभी गवर्नमैंट के पास कमैंट्स के लिए भेजा है ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल 3.55 मिनट पर आपको अपना एक मोशन दिया है । यह मेरा मोशन बहुत महत्वपूर्ण है । यह मोशन शराब के आन्दोलन के बारे में था ।

श्री अध्यक्ष : अभी आपका यह मोशन अंडर कंसीड्रेशन है । अब आप बैठिए ।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : सर, मेरा एक मोशन और भी था जो मैंने आपकी सेवा में सुबह ही दिया है । यह मोशन किसानों को कम्पनसेशन न देने के बारे में है । इसके अलावा एस०वाई०एल० के बारे में और यमुना ऐग्रीमैंट के बारे में भी मैंने आपको अपने मोशन दिए हुए हैं जोकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । उन मोशन का क्या हुआ ?

---

*Copy of the Statement in original is placed in the Library.

श्री अध्यक्ष : आपके ये मोशन रूल 84 के अंडर हैं और ये अभी अंडर कंसीडेशन हैं ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाऊस के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा एक भाई छत्तरपाल सिंह हाऊस के बाहर बैठा हुआ है.....

श्री अध्यक्ष : आप केवल अपने मोशन के बारे में ही पूछें ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो कालिंग अटैंशन मोशन से भी ज्यादा गम्भीर है । इसी हाउस का वह सदस्य बेचारा सड़क पर बाहर बैठा हुआ है । मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस सदस्य को हाउस के अन्दर बुलाने की इजाजत दी जाए ।

श्री अमर सिंह ढांडे : स्पीकर सर, 10 तारीख को मैंने एक काल अटैंशन मोशन दिया था । जिला कथल के गांव क्योड़क में अनेक जगहों पर हरिजनों के साथ जो अत्याचार हुआ, वह चर्चा का विषय बना हुआ है । हरिजनों के पीड़ित परिवार गांव छोड़कर चले गए हैं ।

Mr. Speaker : It is under consideration. यह गवर्नमैंट की कमैंट्स के लिए भेजा हुआ है ।

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । जैसे अभी अमर सिंह ढांडे जी ने बताया कि क्योड़क गांव में हरिजनों पर अत्याचार किया जा रहा है । इसी प्रकार से सिवानी कस्बे में भी हरिजनों के ऊपर जुल्म किये गए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह आलरैडी डिस-अलाउड है । इस पर बोलने की जरुरत नहीं है ।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, हाउस में कई बातों का जिक्र आ चुका है । विपक्ष की बात तो आ गई लेकिन सरकारी प्रापर्टी की अटैच-मैंट की जो बात आई है, उसके बारे में सरकार का पक्ष नहीं आया है । यह जो इन्होंने काल अटैंशन मोशन दी है कि सरकार की प्रापर्टी अटैच हो रही है, यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अभी तो कोई बात नहीं की है । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बात नहीं आई । यह बात ठीक नहीं है । या तो ये कहते कि हमारे काल अटैंशन मोशन का फलां नम्बर है, फलां तारीख को दिया है लेकिन इन्होंने तो डिटेल में बात कह दी है, हालांकि यह अंडर कंसीडेशन है ।

मीडिया व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना की गई सभी पार्टियों के एम०एल०एज० की एक समिति के गठन सम्बन्धी मामला

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं स्पीकर सर, एक बात अखबार में आई है, जिसके बारे में प्रैस के मैम्बर यहां आकर डिफैंड नहीं कर सकते, वह है :—

"Newsmen seek all-party probe."

यह बड़ा अहम मसला है। इस हाउस के माननीय सदस्य चौधरी बंसी लाल जी ने अखबार वालों पर इस तरह के रिमार्कस पास किए, जो ठीक नहीं है। फैक्चुअल पोजीशन को छिपाकर राजबीर सिंह को पार्टी में एडमिट कर लिया। उसने बनारसी दास गुप्ता पर गोली चलाई थी और उसे सजा हो चुकी है। पेपर वालों के सामने उसे एडमिट कर लिया और अखबार वालों ने इस बारे में रैजोल्यूशन पास किया है और लिखकर भी दिया है। यहां आकर प्रैस वाले अपने आपको डिफैंड नहीं कर सकते कि यह बात सही है या गलत। जो आदमी यहां डिफैंड नहीं कर सकते, उनके खिलाफ चौधरी बंसी लाल जी ने ऐसी बातें कहीं। स्पीकर सर, वह राजबीर सिंह, जो एक क्रिमिनल है, उसको पार्टी में एडमिट किया और सबके सामने ऐडमिट किया। वे यहां आकर हाउस में कह रहे हैं कि नहीं ऐंडमिट किया, यह गलत बात है। आज के दैनिक "दी ट्रिब्यून" इंगलिश में पूरी डिटेल है। इसकी कगनीजैंस आप लें। प्रैस वाले अपने आपको डिफैंड नहीं कर सकते। उन्होंने आपको लिखकर भी दिया है। इसके बारे में आप भी कार्यवाही करें।

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा) : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजबीर सिंह मेरे हल्के हिमाऊंपुर का रहने वाला है और चौधरी बंसीलाल जी ने खुद पत्रकारों के सामने उस आदमी को पेश किया था। पत्रकारों ने खुद इस बात को माना है कि चौधरी बंसी लाल जी ने राजबीर सिंह को उनके सम्मुख पेश करके उनको इन्ट्रोड्यूस किया और बाद में चौधरी बंसी लाल जी इस बात से भी मुकर रहे हैं। (व्यवधान व शोर) बंसी लाल जी ने हाउस में और बाहर भी इस तरह की गलतबयानी की है, इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह बात बिल्कुल गलत व निराधार है कि मैंने राजबीर सिंह को ऐडमिट किया है। न तो मैंने इसको ऐडमिट किया और न ही कोई ऐसी बात है। (शोर) अब ये भाई यूंही कहानी घड़कर प्रैस पब्लिसिटी के लिये जो कहना है, वह कह लें। जो चाहे कहानी घड़ लें, लेकिन मेरी पार्टी में ऐसे आदमियों के लिये न तो कोई स्थान है, न ही कोई ऐसी बात है और न ही इस तरह का कोई सवाल ही पैदा होता है। (शोर)

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर साहब, इस के लिये हाउस की कमेटी बना दीजियेगा । राजबीर सिंह के रिलेशंज इस घटना से पहले चौधरी बंसी लाल जी के साथ रहे हैं । (शोर) वह भिवानी में जब रहता था, तब भी इनके घर आता-जाता था । इनके बेटे सुरेन्द्र सिंह से और इनसे उसके पूरे रिलेशंज रहे हैं और इनके घर उनका आना-जाना रहता था । उस का बाप और वह मेरे पास आए और उन्होंने यह सारी बात मुझे बतायी । इसलिये मेरा सुझाव है कि इसकी जांच के लिये हाउस की एक कमेटी बना दी जाए ताकि सारे फैक्ट्स सामने आ जाएं । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मेरा फिर प्वायंट आफ आर्डर है क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर यह इलजाम लगाया है कि उस राजबीर सिंह का मेरे घर आना-जाना रहा है । मैं यह कहता हूं कि मैंने उसको शक्ल से पहली बार प्रैस कांफ्रैंस में देखा था, वह भी चलते-चलते । मेरा तो उसके साथ न कोई ताल्लुक है और न ही कोई ऐसी बात है । न ही उसको पार्टी में एडमिट करने का सवाल ही पैदा होता है । (शोर) जब बनारसी दास गुप्ता पर गोली चली तो सब से पहला आदमी मैं था, जिसने इस बात को कंडैम किया था और कहा था कि इसको अवश्य सजा मिलनी चाहिये और इस के रोष स्वरूप मंडी में हमने हड़ताल भी करवाई थी । (शोर)

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर साहब, इन्होंने इतना तो माना कि मैंने उसको पहली बार देखा था । (शोर)

श्री राम रत्न : स्पीकर साहब, मुझे भी बोलने का समय चाहिये । (शोर)

श्री अध्यक्ष : राम रत्न जी, आप बार-बार बोलने के लिये खड़े क्यों होते हैं ? आप बैठें । आपको भी इसके बाद बोलने के लिये समय दिया जाएगा । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी बंसी लाल जी ने कहा और माना कि मैंने एक बार ही राजबीर सिंह को प्रैस कांफ्रैंस में चलते-चलते शक्ल से देखा था । जैसाकि हुड्डा साहब ने भी बताया है और पत्रकारों ने बतलाया है कि इन्होंने उसको स्वयं पत्रकारों के सम्मुख प्रस्तुत किया था और उसके बाद जब यह समाचार पत्रों में आया कि यह एक क्रिमीनल टाईप का आदमी है, जिसको सजा हो चुकी है तो ये मुकर गए । उसको यदि ये पार्टी में एडमिट करते तो इनकी पार्टी की बदनामी थी । इस वजह से ये उसको पहचानने में आना-कानी कर रहे हैं । इन्होंने पत्रकारों के सामने ही उस को पेश किया था और फिर ये कह रहे हैं कि वे पत्रकार गल्त कह रहे हैं । इस बारे में बड़े-बड़े 15 पत्रकारों ने स्पीकर साहब, आपको लिख कर भी दिया हुआ है । हिन्दुस्तान अखबार, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रैस, नवभारत टाईमज़, पंजाब केसरी,

[चौ० जगदीश नेहरा]

दैनिक जागरण, संध्या हिन्द टाईम वगैरह-वगैरह जो मेन अखबार है, इन के पत्रकारों ने आपको लिखकर दिया हुआ है कि जो चौधरी बंसी लाल जी ने कहा है, वह हमारे सम्मुख कहा है । इस तरह के बड़े-बड़े पत्रकार जो अपने आप को हाउस में डिफैन्ड नहीं कर सकते, उनको बंसी लाल जी झूठा कह रहे हैं । यह बड़ा ही गम्भीर मसला है । इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था । (शोर) इसका एक ही हल है कि जो पैटीशन उन्होंने आपको दी है, उस पर यहां के रूल्ज एण्ड रैगूलेशन के तहत निर्णय लें । इस तरह के पार्लियामैंट में भी कई प्रैसीडैन्ट्स मौजूद हैं । उनके अनुसार आप निर्णय लेकर आगे कार्यवाही करें ताकि जो आऊट साईडर्ज हैं, उनके राईट्स को सेफ किया जा सके । अगर इन जैसे सीजन्ड पार्लियामैंटेरियन इस तरह की गल्तबयानी यहां पर करेंगे, खुद किसी बात को कहकर मुकरेंगे तो आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? अगर इस मामले पर यहां पर आप द्वारा कोई कार्यवाही न की गई तो बाहर जो प्रैस है, आफिसर्ज हैं और दूसरे जो साधारण व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति क्या रहेगी ? इन जैसे आदमी, जोकि 10-10 साल लगातार राज्य के मुख्य मन्त्री रह चुके हों और पार्लियामैंट में भी उच्च पदों पर विराजमान रहे हों, भी अगर इस तरह की बातें करें, तो यह उचित नहीं है । इस लिये स्पीकर साहब, आप स्वयं इस का निर्णय करें ।

श्री अध्यक्ष : यह अंडर कंसिडेशन है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गलत और बे-बुनियाद बात करते हैं । मैंने उसको कभी एडमिट नहीं किया । अगर ये अखबार की बात पढ़ते हैं तो मैं भी एक अखबार की बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूं । मेरे पास यह नव भारत टाइम्ज अखबार है ।

श्री अध्यक्ष : आप इसी कनैक्शन में बात करें ।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मुझे भी अपनी बात कहने का पूरा राईट है । ये कैक्टर असैसीनेशन कर रहे हैं । मैं इसी कनैक्शन में बता रहा हूं । मैं सच्ची कहानी बताऊंगा । इसमें कांग्रेस सांसद चिरन्जी लाल शर्मा की भजन लाल को खुली चुनौती के नाम से खबर छपी है । (शोर) पंडित चिरन्जी लाल ने कहा है कि हरियाणा में सरकारी अधिकारी ही कांग्रेस पार्टी की जगह लिए हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस बात का उससे कोई कनैक्शन नहीं है । (शोर)

चौधरी बंसी लाल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का पूरा हिक है । यदि ये बार-बार मेरा कैक्टर असैसीनेशन करते हैं तो मुझे सच्ची बात बताने दो ताकि सही बात तो सामने आए । पंडित चिरन्जी लाल ने कहा है कि अधिकारी ही कांग्रेस पार्टी की जगह लिए हुए हैं । उपायुक्त जिला कांग्रेस का अध्यक्ष,

पुलिस अधीक्षक महा सचिव, तहसीलदार कोषाध्यक्ष, बी०डी०ओ०—संगठन सचिव और कानूनगो व पटवारी कार्यकर्ता का स्थान लिए हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह बात उससे संबंधित नहीं है । आपकी बात का सब्जैक्ट उससे संबंधित नहीं है ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं और अखबार में भी मेरी बात आ चुकी है कि यह गलत है । फिर ये बार-बार ऐसी बात क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिए ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में बात करना चाहता हूं । कई दिन से इस सदन में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप इससे अलग बात न करना ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मैं इससे अलग नहीं जाऊंगा । आपको मेरे खड़े होते ही पता नहीं क्या वहम हो जाता है, आप मुझ पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : मैं चेयर का पूरा सम्मान करता हूं । कई बार आपकी मजबूरी होती है । आप कोई बात कह नहीं सकते इसलिए वह बात मुझे कहनी पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष : हमारी कोई मजबूरी नहीं है ।

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : तो मैं कह रहा था कि इस विषय पर कई बार चर्चाएं चली हैं और इन चर्चाओं के दृष्टिगत लोगों को यह सोचने-समझने पर मजबूर होना पड़ता है कि राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसी व्यक्ति के बारे में मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा । जब बनारसी दास गुप्ता पर गोली चलाई गई थी, तो सब से पहले भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और मौजूदा मुख्य मन्त्री की तरफ से ब्यान छपा था कि ओम प्रकाश ने बनारसी दास को गोली मरवाई है । अच्छा हुआ बिल्ली छिक्के से बाहर आ गई और अब उस मुद्दे को ले कर दोनों में नोंक झोंक हो रही है । श्रम मन्त्री जी अभी कह रहे थे कि वह व्यक्ति मेरे पास भी आया था । तो अपराधी किस्म के लोगों के एक प्रकार से पनाहगार ट्रेजरी बैंचिज के लोग बने हुए हैं । उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है और उसका नाजायज लाभ उठा करके इस प्रकार के जो लोग हैं, वे राजनीतिज्ञों

[चौधरी ओम प्रकाश चौटाला]

को गुमराह करने के प्रयास में लगे हैं । इसी हाउस में अध्यक्ष महोदय, कभी लेखू अपहरण कांड को ले कर तो कभी पहाड़ी पर चर्चा चली थी । कभी जितेन्द्र का भी जिक्र आया ।

श्री अध्यक्ष : इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है । आप बैठें । (शोर)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं आ रहा हूं । आप जरा मुझे भूमिका बांध लेने दें । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि इस सारे मामले के लिए विधान सभा के जो सम्मानित सदस्य हैं, उनका अपना आचरण ठीक हो । आपकी तरफ से आचार संहिता मुकर्रर की जानी चाहिए वरना यह प्रथा बढ़ती चली जाएगी और राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी । अगर हम पब्लिकली कोई बात कहते हैं तो उसको फेस करने की हिम्मत होनी चाहिए । अगर प्रैस के लोगों को इस प्रकार की बातें कही जाएं तो उनको वह बात डिफैंड करने का अवसर नहीं मिल सकता । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी का तो जनतन्त्र में विश्वास रहा ही नहीं है । प्रैस पर अंकुश लगाने के लिए विदेशी मीडिया को बुलाया जा रहा है । इस प्रदेश में तो पत्रकारों पर जानलेवा हमले भी हुए हैं और उनको डराने धमकाने की कोशिशें भी की गई हैं । आज इसी बात को लेकर अगर हम लोग कोई बात कहें और उसके बाद हम अपनी बात से मुकर ही जाएं तो प्रदेश के लोगों के सामने सही बात कैसे आ पाएगी ? मैं यह बात को तो मान सकता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी किन्हीं कारणों से अपने दिमागी सन्तुलन को खो बैठे हैं, इसलिए वे कभी मानव को 'चिचड़' की संज्ञा देते हैं और कभी एमरजैंसी को डिफैंड करते हैं । पत्रकारों को कही हुई बात से भी मुकर होने का प्रयास करते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि किसी कमेटी का गठन करने की बजाय आप आचार संहिता मुकर्रर करें । प्रैस की जो भूमिका है, वह कायम रहनी चाहिए । फ्रीडम ऑफ प्रैस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए । इस प्रकार का आपको कोई निर्णय देना चाहिए ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, आप पिछले 28 साल से इस हाउस के सम्मानित सदस्य रहे हैं । आपने बार-बार चुनाव जीता है और इस चुनाव के बाद आप इस हाउस के अध्यक्ष चुने गए । मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप राजनीति में आए, उस समय मैं कालेज में एक स्टुडैंट था । उस समय हमने एक सेमीनार किया था । उस सेमीनार में कुछ बातें ऐसी आई थीं जैसे शिक्षा का प्रसार और प्रचार सभी जगह होना चाहिए । लेकिन वह इसलिए नहीं होता क्योंकि साधनों की कमी है । आपने उस समय यह कहा था कि साधनों की कमी होते हुए भी शिक्षा का प्रसार और प्रचार होना चाहिए । शिक्षा तो एक अमृत है । उसको अगर ओक से भी पिलाया जाए तो भी वह पिलाना चाहिए । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज सदन में जो चर्चा हुई है, उसका कोई औचित्य नहीं

है । वह बात रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के किसी भी रूल में शामिल नहीं है । लेकिन कुछ वरिष्ठतम साथी, जो पूर्व मुख्य मन्त्री भी रहे हैं या वे सीनियर मैम्बर होने का दावा करते हैं, अपनी सीनियरिटी की वजह से खड़े हो कर अपनी सारी बात कह देते हैं । उन पर कोई रूल लागू नहीं होता है । मौका लगते ही वे खड़े हो कर अपनी बात कह जाते हैं । चौधरी ओम प्रकार चौटाला ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया । मैं कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 1987 से पहले कोई राजनैतिक हत्याएं नहीं होती थीं और न ही राजनीति का कोई अपराधीकरण हुआ था । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी आपने अपनी बात कहने का मौका दे दिया, वरना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वह बात कहने का कोई औचित्य नहीं था । मैं यह बात कहना चाहता हूं कि राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत कहां से हुई, इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है । मेहम में जो काण्ड हुआ, वह उसकी चरम सीमा थी । उस समय राजनीति में अपराधियों को शह किसने दी ? दुकानों पर कब्जे करवाना, गरीब आदमियों को उनके घरों से बाहर निकालना, जमीनों पर नाजायज कब्जे करना अनेकों-अनेक ऐसी बातें हैं, जिनका विवरण इतिहास के अन्दर कहीं पर भी नहीं है । चौधरी बंसी लाल जी के चुनाव में और मेरे चुनाव में जिस तरीके से वहां का वातावरण आतंकित था और किस तरीके से वहां पर लोगों को गोलियों से भूना गया, वह सारी की सारी कहानी किस के नाम से जानी जाती है ? यह बात मैं नहीं कहता, हरियाणा प्रदेश की जनता कहती है कि किसने राजनीति का अपराधीकरण किया । स्पीकर साहब, आपको हाउस की कुछ मर्यादायें तो रखनी पड़ेंगी । मैं आपकी शान में कोई गलत बात नहीं कहता । आप बहुत शिक्षाविद हैं । आप इस सदन के पिछले चार साल से अध्यक्ष हैं । मैं यह कहता हूं कि जो नए एम0एल0ए0 हैं और मैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नया एम0एल0ए0 मानता हूं क्योंकि ये कभी भी चुनाव जीत कर नहीं आए । ये तो उप-चुनाव जीत कर आते हैं लेकिन अब तक ये जनरल चुनाव जीत कर नहीं आए । इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैम्बर चुनकर आए उनको 5–6 महीने के बाद 5–10 दिन की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए । इस बारे में तो मैं भजन लाल जी का भी कसूर मानता हूं कि जो नए मैम्बर चुनकर आए हैं, उनको ट्रेनिंग देने की बजाये सीधे मिनिस्टर बना दिया, उनको ट्रेनिंग का मौका ही नहीं मिला । (विघ्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : आज कल आप खाली हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए लगा देते हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अगर आप मेरे को इस काम पर लगाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा । स्पीकर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि

[चौ० वीरेन्द्र सिंह]

प्रो० छत्रपाल जी को हाउस से बाहर निकाला हुआ है और वे बाहर बैठे हुए हैं । वे प्ले-कार्ड लिए हुए बैठे हैं । अब हाउस की मर्यादा यही है कि आप उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनको मौका दीजिए ताकि वह भी अपने हल्के की बातें कह सकें । बाहर जनता में जो प्रदर्शन वे कर रहे हैं, वह हाउस की मर्यादा के बाहर की बात है । यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है कि किन मुद्दों पर कौन आदमी खड़ा होकर कब क्या बात कह सकता है ? कैसे आदमी को हाउस से बाहर निकालने के आदेश देते हैं ? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात पर पुनर्विचार करें । यह बात सही है कि कोई भी कोड आफ कण्डक्ट हाउस के अन्दर नहीं है । अब आप देखिए कि नेहरा साहब ने कह दिया कि बंसी लाल जी ने कुछ कह दिया है या संपत सिंह जी ने कुछ कह दिया है, इसलिए मुझे भी मौका मिलना चाहिए । क्यों मिलना चाहिए ? आपने उनको मौका किस रूल के तहत दिया ? जब आप यह कहते हैं कि बैठ जाइए तो फिर सदस्य क्यों खड़े रहते हैं ? बैठते क्यों नहीं और अपनी बात पर वाजिद रहते हैं, चाहे कितने भी सीनियर सदस्य हों, जब आप खड़े हों, तो उनको बैठ जाना चाहिए । इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि यह विचारणीय विषय है, इस पर आप सोचिए ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

(i) चौधरी बंसी लाल द्वारा

चौधरी बंसी लाल : आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर ! अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बात श्री जगदीश नेहरा ने उठाई कि बंसी लाल ने पहले तो उसको एडमिट कर लिया और फिर पता लगा कि वह तो क्रिमिनल है, अगले दिन इन्कार कर दिया । एक मन्त्री कहते हैं कि उसका हमारे घर आना-जाना था । पहले ये दोनों फैसला कर लें कि सरकार में सच कौन सी बात है ? ये कौन से दर्शन पर टिकते हैं ? दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, जैसा अखबार ने लिखा है, मैंने उसको एडमिट किया । उसी अखबार ने यह भी लिखा है कि बंसी लाल ने उसको प्रैस कांफ्रैंस में धमकाया । धमकाने के बाद क्या मैं उसको एडमिट करूंगा ? कोई सोच सकता है क्या ? मैं उसी को धमका रहा हूं और उसी को एडमिट कर रहा हूं, यह कैसे हो सकता है ? मैं कम्पलीटली डिनाई करता हूं कि न तो मैंने उसको अपनी पार्टी में लिया, न उसका कोई वैल्कम किया और न ही ऐसे आदमियों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह है । मेरे बारे में चौटाला साहब ने कहा कि बंसी लाल तो दिमाग का संतुलन खो बैठा है । शायद मैं इनके हिसाब से संतुलन खो बैठा हूंगा । यह तो हरियाणा की जनता जानती है कि दिमाग का संतुलन मैं खो बैठा हूं या चौटाला साहब खो बैठे हैं । यह तो हरियाणा की जनता पर छोड़ दें ।

(ii) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला द्वारा

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : पर्सनल एक्सप्लेनेशन सर ! अध्यक्ष महोदय, हाउस के सम्मानित सदस्य चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने मेरा नाम लेकर कुछ कहा । मैंने कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है । विशेष रूप से ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए लोगों पर अपराधीकरण के मुकदमे चल रहे हैं। शायद चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को ध्यान नहीं कि 307 का केस इनके खिलाफ अब भी है । केस चल भी रहा होगा । अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए कह रहा हूं । कि इस प्रकार का राजनीति अपराधीकरण न हो, और दोगली बातें न अपनाई जाएं । चौधरी बंसी लाल जी में हिम्मत होनी चाहिए कि कोई बात कही जाये तो उसे धड़ल्ले से एक्सैप्ट कर लें । प्रैस के लोगों को अब परेशान किया जा रहा है । उस पत्रकार के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर सम्पर्क स्थापित करके उसे पत्रकारिता से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, वे चुनाव जीत कर आए हैं 11.00 बजे] तथा वे जनता के प्रतिनिधि हैं इसलिए उनकी बात जनता जनार्दन तक जानी चाहिए । चौधरी बीरेन्द्र सिंह भी दोगली नीति पर चल रहे हैं । हाउस के बाहर तो कहते हैं कि चौधरी भजन लाल करप्ट हैं लेकिन यहां पर हाउस में उनका गुणगान गाने में लगे हुए हैं । शायद अब भी बचे-खुचे अर्से में मन्त्री पद की उनकी लालसा रही होगी । चुनाव आएगा तब बंसी लाल जी को भी आटे दाल का भाव पता लग जाएगा । और यह जो विभूतियां सामने बैठी हुई हैं, इनमें से कोई भी जीत कर आने वाला नहीं है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर यह निर्णय करना है तो आज ही निर्णय क्यों न कर लिया जाए (विघ्न)

(iii) चौधरी बीरेन्द्र सिंह द्वारा

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है । एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ 307 का कोई केस नहीं है ये बिल्कुल गलत और निराधार बात कह रहे हैं । (विघ्न)

चौधरी ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुकद्मा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है या नहीं ? आप हाउस को गुमराह मत करिये (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि वह केस चल रहा है । मेरे खिलाफ 307 का कोई केस नहीं चल रहा है, वह बिल्कुल गलत बयानी है । अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ 307 का केस हिसार में दर्ज हुआ था । मेरे ही साथियों को गोलियां लगी थीं, मेरे ही वर्कर की हत्या की गई थी क्योंकि चौटाला साहब और चौधरी देवी लाल की हुकुमत थी इसलिये केस भी मेरे खिलाफ दर्ज हुआ । स्पीकर सर, इससे ज्यादा राजनीति का अपराधीकरण और क्या होगा ? पुलिस की देखरेख में इनके शासन में गुण्डों को जेलों से पैरोल पर छुड़वा कर भिवानी और हिसार में लोगों को आतंकित करा रहे थे । इस से बड़ा राजनीति का अपराधीकरण और क्या होगा ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल के बारे में जो मामला पत्रकारों ने दिया है वह अण्डर कंसीडेशन है। अब इस पर और डिस्कशन नहीं होनी चाहिये। अब श्री राम रतन अपनी बात कहें।

श्री कर्ण सिंह दलाल, एम० एल० ए० द्वारा श्री रामरतन, एम० एल० ए० को धमकी देने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी मामला

श्री राम रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाना चाहता हूं। रोजाना हरिजनों के बारे में बात होती है और हरिजनों पर अत्याचार भी होते हैं। इसी सदन के साथी जो विधायक हैं, उनसे बढ़कर हरिजनों पर अत्याचार करने वाला शायद पूरे हरियाणा में और कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक दरख्वास्त दी है जो कि निम्न प्रकार से है :—

"श्री मान अध्यक्ष महोदय,
हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़।

करना खिलाफ कार्यवाही कर्ण सिंह दलाल, विधायक।

श्रीमान जी,

मैं राम रतन, विधायक, हल्का हसनपुर जिला फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं निम्नलिखित रूप से आप से प्रार्थना करता हूं :—

कल रात जब मैं एम0 एल0 ए0 होस्टल में था तो श्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक ने बिना वजह से कहा कि तू हरियाणा विधान सभा में हमेशा मेरा विरोध करता है। इसके बावजूद मैंने उनको कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद मेरे को मां बहन की गालियां दीं और कहा तू मेरे से दूर हट, तू चमार है और तेरे से बदबू मार रही है। फिर जाते हुए मेरे को जान से मार देने की धमकी दी और देख लेने की धमकी दी। अध्यक्ष महोदय, मुझे उनकी धमकी (जान से मारने की और देख लेने की) से बड़ी मानसिक पीड़ा पहुंची है और उनसे मुझे जान का खतरा है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी जान की रक्षा की जाए और श्री कर्ण सिंह दलाल, विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।" (विघ्न)

मेरी इस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही हुई है ?

Mr. Speaker : Ram Rattan Ji, it is under consideration. (Interruptions) It is under consideration, that's all.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए हैं। न मैंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और न ही गाली-गलोच की। अध्यक्ष महोदय, सारे सदस्य वहां पर सदन में बैठे हुए हैं। यह कल शाम की बात है। मैं कमरा नं0 —1 में बैठे हुए डाक्टर से दवाई लेने जा रहा था। तो वहां से माननीय कटवाल साहब जा रहे थे। मैं इधर डाक्टर के कमरे की तरफ जा रहा था। श्री राम रतन जी अपने कमरे से निकल कर शायद ऊपर की तरफ जा रहे थे। जब इन्होंने पहली सीढ़ी पर पैर रखा तो कटवाल साहब ने इनका हाथ पकड़ा और मेरी तरफ इनको खींच कर लाने की कोशिश कर रहे थे। कटवाल साहब इनसे क्या कह रहे थे या इन्होंने कटवाल साहब से क्या कहा, यह मैंने नहीं सुना। कुछ कहते हुए कटवाल साहब मेरी तरफ इनको ला रहे थे। मैंने उनसे कहा कि इन्हें मेरे से दूर रखें। मेरी इनसे बनती नहीं है। यह कह कर मैं डाक्टर के कमरे की तरफ चला गया। अध्यक्ष महोदय, मैं औन औथ यह बात कह सकता हूं। उस वक्त वहां पर 20-25 आदमी खड़े हुए होंगे और अगर उनमें से कोई भी यह कह दे कि मैंने इन्हें गाली दी या और कुछ कहा हो, तो आप जो भी सजा मुझे देंगे, वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल के पास मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं है और ये मेरे सवालों के जवाब में राम रतन को खड़ा कर देते हैं। मैं इनको कहता हूं कि ये फरीदाबाद में आमने सामने जन-सभा कर लें तो मैं इनको जवाब दूंगा और इनको इनकी हैसियत का भी पता चल जाएगा।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, बात तो कुछ और थी और ये किसी दूसरी साईड पर ले गए। ये दोनों एक ही जिले के रहने वाले हैं और इनके कारनामे राम रतन जानता है और राम रतन के बारे में ये जानते हैं। (शोर) अब इन्होंने मेरे बारे में कह दिया कि फरीदाबाद में जन सभा करके देख लो। अध्यक्ष महोदय, ये पहले मेरे साथ थे और मैंने इनको तीन तीन गाड़ियां दे रखी थीं और ये गाड़ियां लेकर बंसी लाल जी के पास चले गए। मैंने कहा कि भाई गाड़ियां तो दे दो। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो इनके हल्के पलवल से ही चुनाव लड़ लेंगे और इनको भी पता चल जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : राम रतन जी, जो आपने मुझे लिखकर दिया है, वह अभी अन्डर कंसीडेशन है। आनरेबल मैम्बर्ज, अब बजट पर जनरल डिस्कशन रिज्यूम की जाएगी। श्री सतबीर सिंह कादयान अपनी स्पीच शुरू करें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो . . .

. . . . . .

(इस समय चौधरी ओम प्रकाश बेरी बोलने के लिये खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्ष : बेरी साहब, आप कल आधा घन्टा बोल चुके हैं। (शोर)

वाक आउट

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके चैम्बर में फैसला हुआ था कि दो पार्टी के लीडर आधा-आधा घन्टा बोलेंगे और बाकी मैम्बर्ज 5-7 मिनट अपनी कांस्टीचुएंसी के बारे में बोल लेंगे। अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब आधा घन्टा बोल चुके हैं और अब ये जितना समय भी बोलेंगे, आप वह समय मेरे आधा घन्टा में से काट लेना। बाकी जितना समय बचेगा, मैं उतने समय में ही बोल लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर ये दोनों के समय में बोल लेंगे तो मैं अपने समय पर नहीं बोलूंगा। इसीलिए आप बेरी साहब को बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, ये कल आधा घन्टा बोल चुके हैं।

चौधरी ओम प्रकाश बेरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कल 10 मिनट तक इन्ट्रप्ट किया गया था। आप मुझे वह समय तो दे दें।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, क्या आप बोलेंगे ?

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे टाईम में से बेरी साहब को टाईम दे दें। ये जितना समय बोलेंगे, उतना ही समय मेरे टाईम में से काट लेना।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, अगर ये लोग 1—1 घंटा बोलेंगे तो बाकी मैम्बर कहां पर जाएंगे ? 60 मैम्बर्ज तो हमारे भी बैठे हुए हैं। आपको इनको भी मौका देना चाहिये।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि हर पार्टी से दो मेन स्पीकर्ज के आधा आधा घंटा बोलने के लिये जो फैसला हुआ था, हम उनसे बाहर तो नहीं जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आपके ग्रुप को भी उसी तरह से टाईम दिया जाएगा जिस तरह से डिसाईड हुआ था। इसलिये अब कादयान साहब बोलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यदि आप बेरी साहब को बोलने का समय नहीं देते हैं तो हम इसके विरोध में एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

* * * * *

श्री अध्यक्ष : यह जो मेरी परमिशन के बिना बोल रहे हैं उसको रिकार्ड न किया जाए।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सभी उपस्थित माननीय सदस्य एवं असम्बद्ध सदस्य श्री ओम प्रकाश बेरी सदन से वाक आउट कर गए)

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। 13 तारीख को जो माननीय वित्त मंत्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने 1995-96 का बजट पेश किया है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जो नीरस बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, इस बारे मेरा कहना यह है कि ऐसा नीरस बजट, ऐसी निगाहों से, ऐसे इरादों से हरियाणा में कभी भी पेश नहीं किया गया जैसा कि गुप्ता जी के रहते हुए पेश किया गया है। स्पीकर सर, गुप्ता जी इतनी बड़ी उम्र में भी सिन्दूर पर और मंगल सूत्र पर टैक्स माफ करते हैं जबकि गुप्ता जी को कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हैल्थ में, बिजली में, सिंचाई में और बाढ़ पर राहत देनी चाहिए थी। जब हमारी पार्टी की सरकार यानी चौधरी देवी लाल जी की सरकार और ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने जो-जो ध्यान इन क्षेत्रों में दिया था, उसको मैं आपको पैरावाइज बताऊंगा। मैं मक्की और ज्वार के बारे में बताना चाहता हूं। इनके डिपार्टमैंट के जो स्टेटिक्स या आंकड़े हैं, मैं उनके हिसाब से ही वित्त मंत्री जी को बताऊंगा। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी तो व्यापारी हैं और इनकी आढ़त की दुकान भी हैं अगर किसी भी मंडी में ज्वार की सेल एक क्विंटल से ज्यादा हुई हो, तो ये हमें बता दें। इसके अलावा बाजरे की और मक्की की सेल तो बहुत ही कम हुई है। हमारी सरकार ने 1990-91 में जो बजट पेश किया था, उसमें कृषि के ऊपर बहुत खर्च किया गया था। इन्होंने अपने बजट में कृषि के ऊपर 7.2 परसैंट ही कुल प्लान का पैसा खर्च करने के लिये रखने का निश्चय किया है जबकि 1990-91 में यह 12.20 परसैंट था और 1991-92 में यह 15.12 प्रतिशत था जब हमारी पार्टी की सरकार थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार इस तरह का बजट पेश करके गयी थी, पास करके गयी थी। लेकिन आपने तो इसको घटाया ही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो किसान ट्रैक्टर लेते हैं, तो चाहे कौमर्शियल बैंक हो या कोई दूसरा बैंक हो, ऐसे बैंकों में किसानों को इसके लिए बैंक गारंटी के रूप में 1.5 परसैंट रैन्ट देना पड़ता है क्योंकि उन्हें लगता है कि

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री सतवीर सिंह कादयान]

कहीं किसान बैंक को अपना कर्जा अदा न करें। उपाध्यक्ष महोदय, एक डी0आई0सी0 जी0सी0 यानी डिपौजिट इंशयोरैन्स क्रैडिट गारन्टी कोरपोरेशन, बम्बई नाम की संस्था है। इसने किसानों को 1.5 परसैंट रैन्ट पर इसलिये कर्जा दिया है कि कहीं किसान उसका पैसा न दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसानों का क्या कसूर है? वे क्यों गारन्टी दें? इस तरह की गारन्टी का हरियाणा सरकार क्यों नहीं अपने बजट में प्रावधान करती कि अगर किसान इस तरह के इम्पलीमैन्ट्स खरीदने चाहें या और दूसरी ऐसी चीजें खरीदना चाहें तो हरियाणा सरकार को इस बात की गारन्टी अपने बजट में से उनको देनी चाहिये और कहना चाहिये कि बहुत समय तक उनसे कोई गारन्टी या फीस नहीं ली जाएगी। जहां तक कृषि की बात है तो खाद की क्या दुर्दशा थी? आपकी ही पार्टी की केन्द्र में सरकार है और वहां आपके ही वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हैं। आप उनसे समय पर खाद देने के लिये क्यों नहीं कहते? मैं खाद पर सबसिडी देने के बारे में हरियाणा सरकार से पूछना चाहूंगा कि कौन सी खाद पर कब सबसिडी दी गई है? पैस्टीसाईड्ज और इनसैक्टीसाईड्ज की पिछले सालों के मुकाबले में सेल भी घटी है लेकिन उन पर इन्होंने सबसिडी भी खत्म कर दी है। इस सब के बावजूद सारे प्रदेश में खाद के लिये हाहाकार मची। आपके चहेते लोगों ने खाद को ब्लैक कर दिया। जो यूरिया का कट्टा 166 रुपये का हुआ करता था, वह कट्टा 200 से 250 रुपये तक में बिका। साथ ही नकली डी0ए0पी0 बिकी। समय पर न खाद दिया, न दवाई दी। यह तो भगवान की दया हो गई कि बारिश हो गई वरना तो नहरों में भी पानी नहीं होना था और रजवाहों में भी पानी नहीं होना था। कौमर्शियल सेल टैक्स की जो वृद्धि है वह ज्यादा है क्योंकि किसान का उत्पादन बिकने के बाद उस राशि का चार परसैंट आपके खजाने में जाता है। अनाज ज्यादा पैदा हुआ इसलिये टैक्स की राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। गन्ने का भाव आया तो चीनी घोटाले जैसे काम आपने कर दिए। कृषि की पालिसी पूरी तरह से गलत है। किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये पूरे धन की व्यवस्था नहीं करवाई जाती है। पिछले दिनों एक सवाल के जवाब में यह बात आई थी कि 100 ग्राम टमाटर का बीज विदेश से खरीदकर लाए। वह 22 हजार रुपये का आया। एक किलो बीज दो लाख 20 हजार का लेकर आए। यह टमाटर के बीज का भाव नहीं है। इसमें विदेश जाने का खर्चा भी इन्कलूडिड है। मैं भी विदेश गया था। मैं तो 20 हजार रुपये में एक किलो बीज लेकर आया। जो बीज लेकर आए, उस बीज को किस किसान ने ट्रायल किया? कैसी उसकी आउटपुट रही? इस बात का जनता को इलम नहीं है और प्रदेश में जिस तरह से मिलावटी बीज बिक रहे हैं, उससे लगता है कि आपकी जो सर्टीफाईंग एजैन्सी है, वह अपना काम सुचारू रूप से करने में नाकाम रही है। नकली बीजों को सर्टीफाई करके किसानों को दिया जाता है, जिससे उसकी उपज घटती है। उसके साथ-साथ अच्छे भाव नहीं मिलते क्योंकि मिलावटी बीज है, उच्च किस्म नहीं है। चौधरी देवी लाल जी के समय में स्कीम चलाई थी कि यदि किसान मंडी में अनाज लाता है

तो 3 रुपये मार्किट फीस कमेटी को मिलती है। उस पैसे से उसका रास्ता बनाया जाए। सड़क का काम शुरू किया गया था। गांव से मंडी को जोड़ने के लिये सड़क बनाई जाती थी। रास्ते पक्के किए जाते थे। आज वे सड़कें गांव में नहीं बनती। कहीं दूसरों की फैक्ट्रियों में सड़क बनती हैं। चौधरी देवी लाल जी ने जो स्कीम मंजूर की थी, उन पर काम नहीं हो रहा है। मार्किटिंग बोर्ड ने शराब ढोने का काम भी खुद ले लिया है। 8 तारीख को पानीपत में एस0डी0ओ0, जे0ई0 और क्लर्क दारू की चार पेटी ले जा रहे थे। चार पेटी शराब हुड्डा कालोनी पानीपत में चांदनी बाग के एस0एच0ओ0 ने बरामद की। चौधरी देवी लाल के समय में जो सड़कें मंजूर हुई थीं, वे सारी बनानी बंद कर दीं। एक सड़क अहर से अलूपुर की इन्होंने बनवाई थी, उस पर साइकिल भी नहीं चल सकती। किनारे से सड़क टूट जाए तो मंत्री जी कह देंगे कि पुलड से टूट गई लेकिन अगर सड़क बीच से बैठ जाए तो गुप्ता जी और कृषि मंत्री जी क्या बहाना करेंगे? मैंने कहा कि इस सड़क की इंकवायरी कराई जाए और मुझे भी इस इंकवायरी में शामिल कर लिया जाए। कृषि मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। डिवाणा ऐ प्रोच रोड से सिवाह वैटनिरी हौस्पिटल तक एक किलोमीटर की सड़क बननी है, और एक उरलाना खुर्द से गुरुद्वारा की सड़क है। यह सड़क भी नहीं बनाई। यह मेरे हल्के के गांव हैं और मैं विपक्ष का एम0एल0ए0 हूं इसलिये मेरी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।

अब मैं पी0डब्ल्यू0 डी0 विभाग से सम्बन्धित कुछ बातें कहना चाहूंगा कि आपकी जो इकनामिक सर्वे आफ हरियाणा की रिपोर्ट है, उसमें पेज 21 पर सड़कों के बारे में लिखा गया है कि 1990-91 में हरियाणा के अन्दर 23168 किलोमीटर्ज सड़कें थीं जोकि अब घटकर 22787 रह गई हैं यानि 181 किलोमीटर सड़कें कम हो गई, पता नहीं कहां गई। ये तारकोल व रोड़ी खा गये पता नहीं इनको कितना कुछ हजम हो गया। मैं आपको बताता हूं कि एक सड़क परहाना से शाहपुर तक मन्जूर हुई थी और उसके ऊपर चार लाख रुपये की मिट्टी पड़ चुकी थी परन्तु वह सड़क न बनाकर इन्होंने पड़ाना से जवारा तक की सड़क का काम शुरू कर दिया जोकि सोनीपत के हल्के में पड़ती है और यह हल्का इनके कांग्रेस अध्यक्ष * * * का पड़ता है। इस सड़क के ऊपर सरकार का काफी लगाव है (शोर) और वे इनके लिये एक पार्टी मीटिंग में पिट भी गये थे। इस लिये अपने किसी चाहने वाले की खातिर हमारे हल्के के साथ इस तरह के भेदभाव की नीति नहीं बरतनी चाहिये थी। (शोर एवं विघ्न)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो स्पीच दे रहे हैं, आया यह बजट पर है या कि कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ है? कांग्रेस अध्यक्ष का नाम लेकर जो इन्होंने कहा है, वह एक्सपन्ज होना चाहिये। जो आदमी इस हाउस का मैम्बर न हो, उसका नाम नहीं लेना चाहिये। जो आदमी अपने आप को डिफैन्ड न कर सकता

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[चौधरी जगदीश नेहरा]

हो, उसका नाम यहां नहीं आना चाहिये। जो नाम लिया गया है, उसको कार्यवाही में से निकाल देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। किसी का नाम कार्यवाही में नहीं आना चाहिये, वह रिकार्ड न करें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : मैं जो कह रहा हूं यह फैक्ट्स हैं। हम तो कहते हैं कि जहां चाहो सड़कें बनाओ लेकिन हमारे पानीपत के जिला की जिन सड़कों का जिकर आया है, उनको भी प्राथमिकता दी जाए। जैसे पानीपत से कांबड़ी, पानीपत से कुतानी तक की सड़कें बलबीर पाल शाह की कांस्टीच्यूएंसी की हद पर लगती हैं, वहां तीन-तीन फुट के गड्ढे हैं, इसलिये इन सड़कों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा न हो। इसी तरह से आसन कलां से आसन खुर्द की सड़क है, जिसके बारे में मैंने कई बार ग्रिवेंसिज कमेटी में भी कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस इलाके की सड़कें ऐसी बुरी हालत में हैं कि वहां व्हीकल्ज तो क्या, आदमी पैदल भी नहीं चल सकता। मैं यह भी कहूंगा कि असन्ध और नौलथा विधान सभा क्षेत्रों को हर लिहाज से बुरी तरह से इग्नोर किया गया है। इसी तरह से एक और सड़क मडलौडा से कुराना की है। उस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं रूट परमिट्स के बारे में कहूंगा कि सरकार ने लोगों को परमिट तो दे रखे हैं लेकिन सड़कें खराब होने की वजह से बसें खड़ी हैं। ब्राह्मण माजरा गांव से बाहूपुर तक की सड़क दो साल से बन्द पड़ी है। उस पर सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी सड़क के ऊपर एक बस रूट परमिट सहकारी संस्था को मिला हुआ है। उस बस को सीख से नौलथा तक चलना है लेकिन बस पिछले 6 महीने से खड़ी है। न ही उसका रूट परमिट बदला गया है और न ही उस सड़क की मुरम्मत हो रही है जिस कारण से लोग बेरोजगार हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे।

इसी तरह से पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के बारे में एक बात और कहूंगा कि वहां पर पैसे की बड़ी वेस्टेज हो रही है। गोदामों में खाली ड्रम हर जगहों पर पड़े हुए हैं और सरकार उनकी नीलामी नहीं कर रही है। उनकी बोली कम से कम क्वार्टरली होनी चाहियें। वहां पर इसीलिये चोरी होती है। ड्रमों के ड्रम वहां से गायब हो जाते हैं और बिकते हैं। इसीलिये नीलामी नहीं होती। अगर सड़कों पर तारकोल यूज हो और वह भी सही तरीके से यूज हो तो सारे के सारे खाली ड्रम बिक सकते हैं जिससे सरकार को काफी पैसा मिल सकता है और जिसका असर हमारे बजट पर भी पड़ सकता है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस चोरी को रोके और कोई ऐसा तरीका अपनाए जिससे कम से कम क्वार्टरली खाली ड्रमों की नीलामी हो जाया करे।

इसी तरह से हुड्डा की बात भी करना चाहूंगा कि इन्होंने डिस्क्रिशनरी कोटे में से लगभग 3600 प्लाट्स अपने खास लोगों को या अपने चहेतों को दिये हैं। कईयों को

पैट्रोल पम्प के लिये प्लाट दिये हैं। जैसे चौधरी लहरी सिंह जी हैं, उनको पंचकला में और श्री जगदीश नेहरा को पैट्रोल पम्प के लिये सिरसा में प्लाट दिया गया है। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर महोदय, मन्त्री जी खुद कबूल कर चुके हैं और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। (विघ्न) तो मैं कह रहा था कि हुड्डा जो जमीन एक्वायर करता है उस पर दस-दस साल तक कोई काम नहीं होता। इनको चाहिए तो यह कि एक साल में एक्वायर कर लें और उस पर उसी साल काम शुरू कर दें। इनको यह भी चाहिए कि एक्वायर की गई जमीन का किसान को पूरा मूल्य दें और जिसकी जमीन एक्वायर होती है, उसके लड़के को नौकरी भी दें। चौधरी देवी लाल ने अपने समय में यह फैसला किया था कि जिसकी जमीन एक्वायर की जाएगी, उसको वहां पर एक प्लाट दिया जाएगा। वह बहुत अच्छी स्कीम थी लेकिन आज कुछ भी नहीं किया जाता। जिन लोगों ने प्लाट ले रखे हैं, उन पर मकान नहीं बनाए, उनको बार-बार एक्सटैन्शन दी जाती है। यह सारा काम मुनाफाखोरी के लिए किया जाता है। चाहिए तो यह कि यदि कोई मकान नहीं बनाता तो उससे प्लाट सरैंडर करवाया जाए और किसी दूसरे को दिया जाए।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन्होंने शिक्षा का जनाजा निकाल रखा है क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी का शिक्षा के प्रति लगाव नहीं है। वर्ष 1994-95 में एक भी स्कूल अपग्रेड नहीं हुआ। कोई गवर्नमैंट कालेज नहीं बना। यह मैं आपकी रिपोर्ट के आधार पर बता रहा हूं। आप इकनौमिक सर्वे में पढ़ें। वर्ष 1990 में उस समय की गतिशील सरकार ने शिक्षा के लिए 23.89 परसैंट बजट रखा था लेकिन वह 1994-95 में घट कर 16.71 परसैंट रह गया। ये गुप्ता जी के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। फिर 1995-96 में तो ताज्जुब की बात है कि वह शिक्षा पर खर्च 8.46 परसैंट रह गया। यानी जहां 1990 में वह बजट का 24 परसैंट था, आज वह साढ़े आठ परसैंट से भी कम रह गया है। हमारी सरकार ने 27-3-1991 को 350 स्कूल अपग्रेड किए थे, लेकिन अब तक इनके राज के लगभग चार सालों में उतने स्कूल अपग्रेड नहीं हुए। हमने जो स्कूल अपग्रेड किए थे, उनकी लिस्ट भी आ गई थी, लेकिन उसके बाद इत्तफाक से हमारी सरकार नहीं रही। उस समय गवर्नर साहब ने कहा था कि इन स्कूलों को जुलाई से चालू कर देंगे लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वे स्कूल नहीं खुलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारें तो चलती रहती हैं लेकिन मुख्य मन्त्री बदलते रहते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल को हम भी यहां बैठेंगे और आपकी तरह हम नहीं करेंगे। इसी तरह से बिल्डिंग फंड के लिए एक-एक लाख रुपया, एक स्कूल के हिसाब से, बीस करोड़ रुपया साल का दिया जाता था लेकिन अब कोई पैसा नहीं दिया जाता। पी0 डब्ल्यू0 डी0 वाले उनकी रिपेयर नहीं करते क्योंकि गुप्ता जी उनको धन नहीं देते। हमारी सरकार के समय नौलथा में एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ट्रेनिंग सैंटर मंजूर हुआ था लेकिन चार साल हो चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। सुनने में आया है कि इनके चहेते विधायक उसको दूसरी जगह बदलवाना चाहते हैं। इसी

[श्री सतबीर सिंह कादयान]

तरह से सिवाह गांव में नवोदय स्कूल के लिए 25 एकड़ जमीन दे रखी है, उसका भी कुछ पता नहीं । ये लोग यहां पर नकल विरोधी प्रचार करते हैं । सुशीला बहिन इस सरकार के घिनौने कामों की वजह से इस नकल विरोधी बात की शिकार हुई । उसने मुख्य मन्त्री के चहेते डी0एस0पी0 के लड़के को नकल मारने से रोका था । उसको नकल नहीं मारने दी । अभी गोहाना के अन्दर इनकी पार्टी के प्रधान हैं । मैं उनका नाम नहीं लूंगा । अगर नाम लूंगा तो इनको तकलीफ हो जाएगी, वह दुर्भाग्य से एम0पी0 भी हैं । उनकी लड़की नकल मार रही थी । पहले जो फलाईंग स्क्वैड आई, उसको कहा गया कि यह धर्मपाल जी की लड़की है, वह चले गए । उनको ऐसा लगा कि हम कुछ करेंगे तो कहीं सुशीला जैसा काण्ड न हो जाए । (शोर)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि इनको ऐसे एलीगेशन नहीं लगाने चाहिएं कि चौधरी धर्मपाल जी की लड़की नकल करते हुए पकड़ी गई और फिर कहते हैं कि कहीं सुशीला जैसा काण्ड न हो जाए । इनको पता होना चाहिए कि सुशीला काण्ड में जिनको पकड़ा था, उनके बारे में कह दिया गया है कि उनका कोई दोष नहीं है । कल उनकी जमानत भी हो गई ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि उनकी लड़की नकल मारते हुए पकड़ी गई और एस0डी0एम0 ने पर्चा दिया । अगर कोई नकल मारता हो, कोई दिक्कत नहीं उसका केस बन जाए लेकिन उसको बचाने की कोशिश की गई और जो बचाने की कोशिश की गई, उसका हम इजहार कर रहे हैं । इस सरकार की स्कूलों में कलर टी0वी0 देने की योजना है और यह सरकार उन स्कूलों को टी0वी0 देगी जिनमें बिजली नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैचिंग ग्रांट के लिए बजट में जो पैसा रखा गया है, वह बहुत कम है । चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने 1979-80 में एक स्कीम बनाई थी कि मैचिंग ग्रांट दी जाए ताकि गांवों की स्वैच्छिक संस्थाएं पैसा इकट्ठा करें और वह गांवों और शहरों का विकास कर सके । वर्ष 1989-90 में हमारी सरकार ने इस काम के लिए 10 करोड़ 90 लाख रुपए दिए और 1990-91 में 7 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए । वर्ष 1991-92 में 3.62 करोड़ रुपए दिए गए, वर्ष 1992-93 में 2.1 करोड़ और 1993-94 में 1.46 करोड़ दिए गए । फिर 1994-95 में इस सरकार ने रिकार्ड तोड़ दिया, केवल 1.52 करोड़ रुपए दिए हैं । कहते हैं बजट की वृद्धि 21 परसैंट है और मैचिंग ग्रांट उसी स्पीड से उल्टे कम से घट रही है । इस सरकार का ध्यान विकास के कार्यों पर नहीं है । 27-3-1991 को ग्रामीण शिक्षा प्रसार समिति, इसराना ने कालेज बनाने के लिए 5 लाख 40 हजार रुपए सरकार के पास जमा करवा रखे हैं । आज तक वहां पर कालेज नहीं बनाया गया है । अगर वे उस पैसे को किसी

बैंक में डाल देते तो वह पैसा डबल हो जाता । यह सरकार वह पैसा लिए बैठी है, उसको डबल नहीं करती । लड़कियों के स्कूलों के लिए तीन गुणा पैसा नहीं दिया जाता है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से आज यह सरकार उद्योगपतियों को बहुत तंग कर रही है । उसकी कोई मिसाल नहीं है । जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने निर्णय लिया था कि जो उद्योगपति बिजली न मिलने के कारण या बिजली की कमी आ रही हो, तो अपना जनरेटर लगाएगा, उसको सबसिडी दी जाएगी । उस समय हमारी सरकार ने 50 हजार रुपए से बढ़ा कर 15 लाख रुपए सबसिडी की थी । वह सबसिडी कंटीन्यू तो है लेकिन उसको ये बंद करने वाले हैं । पिछले तीन साल से किसी भी उद्योगपति को सबसिडी नहीं दी जा रही है । डिप्टी स्पीकर साहब, 1200 रुपए पर के0 वी0 ए0 के हिसाब से सबसिडी दी जाती थी । तीन जिलों में एक उद्योग कुंज खोलने वाले हैं और उसमें 10 कमरे होते हैं । उस तीन जिलों के उद्योग कुंज में 10 आदमी रोजगार पाएंगे । इस तरह से आप कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे । आप जनता को क्यों बहका रहे हैं ? आप कहते हैं कि एक परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे । गुप्ता जी थोड़े दिनों में आपका जनाजा निकलने वाला है । आप देखें नौकरी किसको मिलेगी और किसको नौकरी मिली है । पता नहीं कैसे ये लुभावने-सुभावने नारे दे देते हैं ? डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने सरकार तो बना ली । जब जनता इनकी चिमटों से खाल उतारेगी, तब इनको पता लगेगा । एक ऐसी स्कीम चलाई है कि 25 लाख रुपए की सबसिडी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज को दी जाती है, लेकिन तीन साल से वह सबसिडी किसी को नहीं दी गई है । यह सरकार उद्योग-पतियों को कहती है कि आप एच0 एस0 आई0 डी0 सी0 से लोन ले लें। लोन तो उनको दे देंगे लेकिन सबसिडी रिलीज नहीं करेंगे । अगर लोन देने की सरकार की क्षमता है, तो सबसिडी क्यों नहीं दी जाती ? गुप्ता जी, आप खुद व्यापारी हैं । आप व्यापारियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं ? आप कहीं चूक रहे हो या सारा पैसा आप अपने घर ले जाते हो । बड़ी फैक्टरी लगाने के बारे में इन्होंने एक स्कीम चलाई है कि हुड्डा से 10-10 किल्ले आधी कीमत पर जमीन खरीदें और जो कम्पनी 100 करोड़ रुपए की इनवैस्टमैंट करेगी उसको आधे भाव की रियायत पर जमीन दी जाएगी । डिप्टी स्पीकर साहब, एक छोटा बेरोजगार यदि 500 गज का प्लाट लेगा तो उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा और पूरा पैसा भी 6 महीने के अन्दर देना पड़ेगा । एक रणबीर सिंह एडवोकेट है । उसको एक प्लाट मिला था । वह बेचारा प्लाट के पैसे नहीं भर पाया क्योंकि लैंड की जो कीमत है, उसको हरियाणा फाइनैंस कारपोरेशन ने नहीं माना । उस वकील को चार हजार रुपए का नुकसान हो गया क्योंकि उसको लोन देने के लिए टाल कर दी । बेचारे ने प्लाट लेने से मना कर दिया और 5-6 महीने जो पैसा उसका पड़ा रहा, उसका उसे दण्ड भुगतना पड़ा ।

[श्री सतबीर सिंह कादयान]

मिनरल्ज की माईन्ज भी यह सरकार अपने चहेतों को, रिश्तेदारों को, एम0 पीज0 को और उनके साले आदि को दे रही है । मेरे कहने का मतलब यह है कि मौजूदा सरकार प्रदेश की सम्पत्ति को चारों तरफ से लूट रही है । चाहे हुड्डा के प्लाट्स हैं या पहाड़ की जमीन है, या किसी नदी की जमीन है । ये सब पर कब्जा करने में जुटे हुए हैं ।

जहां तक बिजली का संबंध है, सारे प्रदेश में बिजली की हालत बहुत खराब है । हमारे यहां पर 88 हजार ट्रांसफार्मर्ज वर्किंग कंडीशन में चलते हैं लेकिन आज के दिन इनमें से 21 हजार 500 ट्रांसफार्मर्ज ऐसे हैं, जो वर्कशाप में हैं और 10 हजार ऐसे हैं जिन पर पशु बंधते हैं, यानि वे खूंटे का काम करते हैं । इस बारे में मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि इनको उठा कर इनकी रिपेयर आदि करवाई जाये । जहां तक रिपेयर की बात है, बिजली बोर्ड खुद रिपेयर करने की बजाये प्राईवेट लोगों से ज्यादा पैसा देकर रिपेयर करवा रहा है । प्रदेश के धन का दुरुपयोग किया जा रहा है । आज हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 1700 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है । इतना बड़ा घाटा शायद ही किसी बिजली बोर्ड को हो । मौजूदा सरकार बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही । हमारी सरकार ने 5वीं यूनिट चालू की थी और छठी यूनिट के लिए काम शुरू हो गया था । इस बात के गवाह चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी हैं क्योंकि उस समय ये उस मंत्रिमंडल में भागीदार थे । अब ये अपनी फर्मों से यानि अपने देश की कम्पनियों से बिजली का संयंत्र लगवाने की बजाय इसराईल की कम्पनी से काम करवा रहे हैं । इस बारे में होना तो यह चाहिए था कि यदि हमारे देश की कोई कम्पनी जैसे एन0 टी0 पी0 सी0 या बी0 एच0 ई0 एल0 बाहर की कम्पनी की बजाय 20 परसेंट अधिक पैसा लेती है तो भी यह काम अपनी ही कम्पनी को दिया जाना चाहिए ताकि देश का पैसा देश में रहे । लेकिन ऐसा करने की बजाये ये पानीपत थर्मल प्लांट का काम बाहर की कम्पनी से करवा रहे हैं, जो ठीक नहीं है । इस इजराईल की कम्पनी को यह काम सारे रूल्ज की वायलेशन करके दिया जा रहा है ।

अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी में ट्यूब-वैल्ज की 80 फुट की गहराई तक बिजली का रेट 43 रुपये प्रति हार्स पावर ले रहे हैं और दूसरे एरियाज जैसे करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अम्बाला, में 80 फुट की गहराई तक 60 रुपये प्रति हार्स पावर लिए जाते हैं । पानी तो इनका भी नीचे गया है । जो ऐसा भेदभाव है, यह नहीं होना चाहिए । जिस किसान के ट्यूब-वैल की मोटर 50 फुट से नीचे रखी हुई है, उसको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए । बजट में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए । गुप्ता जी उन किसानों की तरफ भी ध्यान दें । सिर्फ 2 क्षेत्रों का जिक्र किया गया है । जहां-जहां पानी नीचे है, उन सबको यह सुविधा मिलनी चाहिए चाहे वह झज्जर है, चाहे रोहतक जिला हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं टैक्नीकल एजुकेशन पर कुछ कहना चाहूंगा । श्री छतरपाल जी मंत्री बनाए गए थे और चौधरी भजन लाल जी ने उनको ऐसा महकमा दे रखा था कि वे चलते-फिरते घोषणा करते थे । उन्होंने शौर्ट कोर्स डिप्लोमा घोषित कर दिया । शाहपुर गांव में एक कोर्स का ऐलान किया । 2 महीने तक स्टाफ वाले वहां पर रहे । पता नहीं, वहां पर क्या करते रहे ? जो पैसा उन पर खर्च हुआ, वह सरकारी था या मुख्य मन्त्री जी का अपना पैसा था । वहां पर कोई भी आई0 टी0 आई0 या ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट नहीं खुला । एक बार तेजेन्द्र सिंह मान जा कर आए । डिप्टी स्पीकर सर, सीख गांव मेरे हल्के में पड़ता है वहां पर हमने एक आई0 टी0 वोकेशनल एजुकेशन इन्स्टीच्यूट बनाया था । अपने हल्के में उसके लिए फण्ड एलोट करवाया था । दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने उस पर स्टे ले लिया । उसका पत्थर तेजेन्द्र सिंह मान जी ने 3 साल पहले रखा था । इस बारे में जब मैं सवाल पूछता हूं तो जवाब मिलता है कि धन की उपलब्धि नहीं है । जब सरकार के पास धन ही नहीं है, तो यह पत्थर क्यों लगाए जाते हैं । इस प्रकार के पत्थर लगाने की भी सरकार को मनाही होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, आपका टाईम खत्म हो गया है इसलिए अब आप वाईंड अप करिये ।

श्री सतबीर सिंह काद्यान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा । चौधरी देवी लाल जी ने एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत किसानों की जमीन के साथ-साथ पी0 डब्ल्यू0 डी0 या नहरों के महकमें ने दरखत लगाए हैं । वह 10 फुट की हद तक हैं । किसान के लिए कानून के मुताबिक उसका मुआवजा मुकर्रर किया था क्योंकि किसान को उससे फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता था लेकिन इस सरकार ने उस सुविधा से सारे किसानों को वंचित कर दिया है । पानीपत में मुख्य मन्त्री जी का दौरा था । पानीपत के उद्योगपतियों के गेट सड़क पर लगे हुए हैं जो कि 20-20 साल से लगे हुए हैं । उनको नोटिस दे दिये और व्यापारियों ने कोर्ट से जा कर जमानत करवाई । उनका कसूर यह था कि उन्होंने चन्दा नहीं दिया । जिसने चन्दा नहीं दिया, उसको कह दिया तू जी0 टी0 रोड से नहीं जा सकता कहीं और से जाओ । मुख्य मन्त्री जी और रास्ता उनको कहां से देंगे ? क्या उनको कोई जहाज देंगे ? मुख्य मन्त्री जी, जिसका गेट ही सड़क पर है, उसको रास्ता तो देना ही पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, प्लीज आप अपनी बात को समाप्त करके अपनी सीट पर बैठें ।

श्री सतबीर सिंह काद्यान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी कुछ बातें और कहनी हैं इसलिए मुझे थोड़ा समय और दीजिए । उपाध्यक्ष महोदय, दरख्तों का कटान हुआ है। इसके साथ ही आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने आई0 ए0 एस0 में, एच0

[श्री सतबीर सिंह कादयान]

सी0 एस0 और सर्बोर्डिनेट आफिसर्ज को प्रमोट किया था। उन 11 में से केवल दो को पोस्टिंग मिली है जिनमें से एक तो मुख्य मन्त्री जी के ओ0 एस0 डी0 हैं और दूसरे एक अन्य अधिकारी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जगहें खाली पड़ी हैं लेकिन वे बेचारे बेइज्जती महसूस करते हुए अपने पुराने पदों पर बने हुए हैं। उनकी परमोशन हो गई और उनको केडर मिल गया लेकिन सरकार उनको पोस्टिंग नहीं दे रही है क्योंकि इनमें कुछ लोग ऐसी जाति के हैं, जिनसे मुख्य मन्त्री जी घृणा करते हैं। उनको मजबूरी में प्रमोट तो करना पड़ा परन्तु उनको पोस्टिंग नहीं मिली। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्री एक जाति से घृणा करते हैं लेकिन घृणा तो ये लोग करते थे। ये अपने जमाने को याद करें। भजन लाल तो 36 बिरादरी का नेता है और 36 बिरादरी को साथ ले कर चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पोस्टिंग देने का ताल्लुक है, सब को उनके पदों पर पोस्टिंग दे कर लगाएंगे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, अब आप बैठें क्योंकि आपको काफी समय मिल गया है। अब आप और न बोलें और अपनी जगह पर बैठें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे 10 मिनट का समय और दीजिए मुझे अभी काफी बातें कहनी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठें। आप अपनी बात को एक मिनट में खत्म करें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी गवर्नमैंट ने किसानों की तरक्की की। हरित और श्वेत क्रान्ति आई। लोगों को लोन दिए गए। इन लोगों ने लोन नहीं दिए। किसानों को पशुओं की बीमारी के लिए दवाईयां नहीं मिल रही हैं। मेरे हल्के में एक बी0 एल0 डी0 ए0 की लापरवाही से पटवारी की छः भैंसे मर गईं। उसका नाम राम फल था। हमने इस मामले को प्रिवैन्सिज कमेटी में उठाया (विघ्न) उसके खिलाफ इन्क्वायरी हुई और उसको वहां से बदल कर 1-2 किलोमीटर दूसरी जगह पर लगा दिया (घण्टी) एक गांव से बदल कर 1-2 किलो मीटर दूर लगाने से उसको क्या फर्क पड़ा ? (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री सतबीर सिंह कादयान : * * * * * * * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं इसलिए अब आप जो बोलेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं आएगा । कादयान साहब, जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए । कादयान साहब, प्लीज़ आप अपनी सीट पर बैठें ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : * * * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : कादयान साहब, आप बैठ जाएं यह कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा है ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : * * * * * * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी आप बैठ जाएं । मक्कड़ साहब आप बोलें ।

श्री सतबीर सिंह कादयान : * * * * * * * * * * *

श्री उपाध्यक्ष : यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए । मक्कड़ जी, आप शुरू करें ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । वित्तमंत्री जी ने जो परसों बजट पेश किया है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि यह बजट कर रहित है । बिक्री कर में छूट और विकास के बारे में कितना ही अच्छा बजट है । यह एक बहुत ही सराहनीय बजट है । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में हर वर्ग के तथा हर क्षेत्र के विकास की बात की गई है । इसमें हर बात को लिया गया है । वित्त मंत्री जी ने बताया कि बजट में हर प्रकार से, चाहे वह सड़क है, चाहे वह स्वास्थ्य के बारे में है, एजुकेशन के बारे में है, पीने के पानी की बात है, महिलाओं के विकास की बात है, सबके लिए प्रावधान है । आज हम समझते हैं कि इससे हमारी यह स्टेट दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगी । आप सभी समझते हैं कि जब कभी इस प्रदेश की जनता ने हमारे इन साथियों, जो अभी बोल रहे थे और टांट कस रहे थे, का राज हरियाणा में बनवाया तो इन्होंने क्या किया ? यह बात हम सभी जानते हैं । आज यह बजट का विरोध करते हैं । यह बात ठीक है कि इस किस्म की बातें विधान सभा में नहीं होनी चाहिएं जैसाकि हमारे एक साथी भी कह रहे थे । लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि पिछले चार सालों के राज में इन्होंने कहीं भी हरियाणा में विकास के नाम की कोई बात नहीं की सिवाए लूट खसौट के और सिवाए नाजायज कब्जों के और कोई इनका विचार ही नहीं रहा ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

लेकिन आज इस बजट में जितनी भी अच्छी बातें होनी चाहिए थीं, वह सब दर्शायी गयी हैं और आगे आने वाले समय में जो काम होंगे, उनके बारे में भी बजट में बताया गया है जो एक सराहनीय बात है । जैसा कि सड़कों के बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने और लोक निर्माण मंत्री जी ने हाउस को बताया कि कितनी सड़कें जिनको हमारे ये साथी पीछे बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ गए थे, को रिपेयर कराया है । काफी सड़कों के बारे में, यहां पर उन्होंने बताया था जिसमें मुरथल से लेकर करनाल तक और स्टेट हाई-वे नं0 1, 2 और 8 हैं, जिन पर आज काम चल रहा है और इनका रास्ता चौड़ा बनाने की स्कीम बनायी गयी है । ऐसा करने से एक्सीडैन्ट भी कम होंगे और सड़कों पर आने-जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी । इसके साथ ही साथ नयी सड़कों का निर्माण भी आज की सरकार कर रही है । मैं भी प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के की कुछ सड़कें ऐसी हैं जो एक गांव से दूसरे गांव को मिलाती हैं, उनको भी बनाया जाए । इनकी यह बात ठीक है कि हरियाणा में हर गांव सड़क से मिला हुआ है लेकिन कुछ और सड़कें भी बनाना जरूरी हैं ताकि किसानों को मंडियों में जाने के लिए समय कम लगे । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में खरकड़ा से अनाज मंडी की सड़क जो कि तीन किलोमीटर तो बनी हुई है लेकिन अभी 6 किलोमीटर और बनायी जानी है को पूरा किया जाना चाहिए इसके अलावा दूसरी सड़क ढानी जाटू से अनाज मंडी तक है और तीसरी सड़क सुल्तानपुर से अनाज मंडी तक की बननी है। इसी तरह से एक सड़क जी0 टी0 रोड से रामपुर स्कूल तक बननी है । उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसी सड़के हैं जिनसे किसानों को मंडी में और शहर में जाने के लिए पांच या छः किलोमीटर का कम रास्ता तय करना पड़ता है इसलिए ये सड़कें बनायी जानी बहुत जरूरी हैं । जैसा वित्त मंत्री जी ने बजट में बताया भी है कि इस मद में हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि वे यह सड़कें भी जरूर बनाएंगे ताकि मेरे हल्के के किसानों को काफी सुविधा मिल सके ।

इसी तरह से इरीगेशन के बारे में है । मेरे अपोजीशन के भाईयों ने यमुना ऐग्रीमैंट के बारे में काफी कुछ कहा है । उपाध्यक्ष महोदय, ताजेवाला हैड पर हमारी कमेटी गयी थी । यह हैड सौ-साल से ज्यादा पुराना है और उसकी गारंटी की मियाद भी खत्म हो चुकी है । इसलिए चौधरी भजन लाल जी ने और इरीगेशन मिनिस्टर ने अथक प्रयासों से यह समझौता लागू कराकर हथनीकुंड बैराज के बनाने का रास्ता साफ किया है । यह बैराज बनना जरूरी है क्योंकि इसके लिए करोड़ों रुपये की मशीनरी काफी सालों से ली हुई पड़ी है । उस मशीनरी को जंग लग रहा है और उसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है । इस बेकार पड़ी हुई मशीनरी पर जो पैसा हरियाणा सरकार का खर्च किया गया था, उसका इस्तेमाल करने व पानी की कमी को पूरा करने के लिए ही यह समझौता सरकार ने किया है। इन्होंने तो अपने राज में इसके लिए कुछ भी नहीं किया । चाहे वे चौधरी बंसी लाल ही

क्यों न हों जो चीफ मिनिस्टर रहे हों, उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया । अब ये भी इसका यूं ही ऐतराज कर रहे हैं । हमने ताजेवाला से लेकर सारी नहरों का सर्वे किया था । जैसा चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, कि हम बहुत कम पानी इस्तेमाल कर रहे थे । सर, हथिनी कुंड बैराज के बनने से हरियाणा के किसानों को इसका बहुत फायदा मिलेगा और फिर ताजेवाला हैड कभी भी टूट सकता है, कभी भी बह सकता है । अब यह जो समझौता किया है, यह बहुत सराहनीय है, हम सब को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी । विरोधी पक्ष के भाई इसका ऐतराज करते हैं जो कि गलत बात है क्योंकि यह हरियाणा के हित की बात है । इससे हरियाणा के किसान को बहुत लाभ होगा । जब तक नहरों की सफाई नहीं हो जाती किसान की टेल तक पानी पहुंचना मुश्किल है । 180 करोड़ रुपया नहरों और छोटी माइनरों की सफाई के लिए दिया है । यह काम अब शुरू हो रहा है । मैं इसकी भी सराहना करता हूं । हरियाणा सरकार को किसान की चिंता है और किसान के टेल तक पानी पहुंचाने के लिए यह सरकार पूरा प्रयास कर रही है । एम0 आई0 टी0 सी0 खालें पक्की कर रही है । इससे कोई ढाई हजार क्यूसिक पानी की बचत हुई है । इससे कितने हैक्टेयर फसल ज्यादा हुई, यह एक उदाहरण है । आज हरियाणा का किसान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है । आज हमारी उपज 1 करोड़ 7 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा होने जा रही है । उसका यही कारण है कि इरीगेशन सिस्टम ठीक होने की वजह से किसान के खेतों में ज्यादा पानी जा रहा है । मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे हल्के में काफी खालें तो पक्की हो चुकी हैं । कुछ जो रह रही हैं, उनको भी पक्का कराया जाए । खालें पक्की होने से किसान के पानी की बचत होती है । पानी की सीपेज नहीं होती । मेरे हल्के में धमाणा माईनर के लैफ्ट और राईट 9 हजार टेल हैं । इसी तरह कुछ और माइनर्ज हैं जिन में पानी की बड़ी दिक्कत है । जैसे गढ़ी माईनर, पुट्ठी माईनर और मनूमरा माईनर व बीड़ माईनर है जिनमें पानी टेल पर नहीं पहुंचता । मैं चाहूंगा कि इनका दोबारा सर्वे कराकर उनकी लाईनिंग अच्छे लैवल पर कराई जाए जिससे पानी सही ढंग से टेल पर पहुंचे ।

ग्रामीण विकास और शहरी विकास के बारे में भी मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम चल रहा है । 20-20 लाख रुपये हर एम0 एल0 ए0 के अपने क्षेत्र के विकास के लिए रखे हैं । पहले यह राशि मिनिस्टरों के लिए तो रखी जाती थी पर चौधरी भजन लाल जी ने इस तरह से विधायकों का आदर करके एक बहुत अच्छा काम किया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि नये साल की राशि जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी विधायक के हल्के में भिजवाएं ताकि विधायक अपने हल्के में विकास के काम सही ढंग से करा सकें । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम गांवों के अंदर अभी पंचायती राज लाए हैं । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी का यह सपना था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक सपना देखा था कि देश में पंचायती राज होगा और ताकत का बंटवारा किया जाएगा । राजीव गांधी जी ने

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

इसे पूरा करने के लिए स्कीम बनाई । यह ठीक है कि आज वे हमारे बीच नहीं हैं । 12.00 बजे | मगर आज हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सपने को साकार बनाने के लिये, पंचायती राज को लागू करने के लिये इस बिल को पास करवाया और उसके बाद सबसे सराहणीय कार्य हरियाणा सरकार ने यह किया जो इस को सब से पहले लागू किया । इससे महिलाओं को राजनीति में आने का पूरा मौका मिलेगा और 1/3 महिलाएं पंचायत और नगर पालिकाओं की मैम्बर बन सकेंगी । उनको इस प्रकार की पूरी पावर्ज देने की कोशिश सरकार ने उस बिल के द्वारा की है । (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । मेरे माननीय साथी ने पंचायत के चुनावों की चर्चा की है कि बड़े अच्छे ढंग से सम्पन्न हुए हैं लेकिन जब पंचायत, जिला परिषद वगैरह के लिये चुनाव प्रचार हो रहा था, तो उस वक्त ये नारे दिये जा रहे थे कि जो पिलाएगा देसी, उसको वोट कैसी, जो पिलाएगा रम, उसको वोट कम और जो पिलाएगा विस्की सारी वोट उसकी । यह तो इनके चुनावों का हाल था (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी शराब पीता है, उसका नाश हो जाता है, आत्मा का नाश हो जाता है । तो इस तरह की इन लोगों की धारणा हो तो फिर ये लोकतन्त्र में इस प्रकार की चर्चा करें कि चुनाव बड़े ही निष्पक्ष और सही ढंग से हुए हैं, यह कहना उचित नहीं है । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है । यह जो इन्होंने यहां पर चुनाव प्रचार में शराब से सम्बन्धित नारों का जिकर किया है, यह सब कुछ इन्हीं के पार्टी वर्कर्ज करते होंगे । कांग्रेस पार्टी की ओर से इस प्रकार का कभी प्रचार नहीं किया गया और यह सब कुछ इन्हीं लोगों की सरकार का ही काम होता था । इस सब के लिये ये लोग ही जिम्मेवार हैं । हमेशा ही इन्होंने इस तरह के कारनामे किये हैं और अब भी करवा रहे हैं । (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, इन्हीं के नेता के पास शराब बनाने के लाईसैंस हैं । तभी उन्होंने अपनी शराब बिकवाने के लिये ऐसा करवाया है । (शोर) डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी पार्टी ने यह निर्णय किया हुआ है कि जो आदमी शराब पीयेगा उसको चुनाव के लिये पार्टी टिकट नहीं दी जाएगी । (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, शराब पीने के लिये अहाते तो इन्हीं की सरकार के वक्त में खोले गये थे । (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अहाते तो हमने ही खुलवाये थे लेकिन बिना टैक्स के शराब तो आपके वक्त में बिक रही है । (शोर)

श्री अमीर चन्द सक्कड़ : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो इधर-उधर की बातों में इन लोगों ने मेरा समय बरबाद कर दिया है, यह टाईम मेरे टाईम में से निकाल दिया जाए और मुझे अपनी बात कहने का मौका दें । नेहरा साहब ने कहा कि अहातें तो इन्हीं की सरकार के वक्त में खोले गये थे, जिससे शराब पीने वालों को बढ़ावा मिला था । तो फिर ये किस मुंह से यहां पर शराब के खिलाफ बात कर रहे हैं, इनके लिए यह अच्छी बात नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं शहरी विकास की बात करना चाहता था, इन्होंने बीच में टोक दिया । हमारे आदरणीय प्रधान मन्त्री जी और हरियाणा सरकार भी यह बिल ला रही है । महिलाओं की भलाई के लिये सरकार बड़ा कुछ करने जा रही है । जहां पहले महिलाएं मैला ढोने का काम करती थीं, अब वह बिल्कुल बन्द हो जाएगा । पहले सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं थी । शहरों में काफी ऐसी कालोनियां हैं जहां पर इस प्रकार की लोगों को दिक्कत आ रही है और वहां पर सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है । अब सरकार यह सिस्टम हर जगह पर करने जा रही है जिससे महिलाओं को मैला नहीं उठाना पड़ेगा । अभी पंचायती राज बना है । इस तरह की पंचायतों को पावर्ज दी गई हैं । उसमें अब घर-घर में गांवों में लैट्रीन बनाने का प्रावधान किया गया है । काफी गांवों में अभी तक नहीं बनी हैं । उनमें भी बनाने की व्यवस्था की जाएगी । (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा बहुत सारा समय तो इन लोगों ने बरबाद कर दिया है । मुझे कम से कम अपने हल्के की बात तो कह लेने दीजियेगा । तो मैं शहरी विकास के बारे में यही प्रार्थना कर रहा था कि शहरों को भी कुछ ग्रांट दी जाए । शहरों में ऐसी-ऐसी नगरपालिकाएं हैं, जिनकी ज्यादा आमदनी नहीं है और वे अपने स्टाफ को पूरी तनखाह भी नहीं दे सकतीं । उनके अन्दर हांसी भी शामिल है । उनको कुछ ग्रांट दी जाए ताकि वे विकास के कार्य कर सकें । आज मार्किट कमेटियों के पास पैसा है । जैसे पहले इन्होंने आदेश दिए थे कि शहर की सड़कों का विकास मार्किट कमेटी करेगी । मैं उन सड़कों की बात कर रहा हूं, जो अनाज मंडी या सब्जी मंडी को जाती हैं । ऐसी काफी सड़कें हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि शहरी सड़कों का काम मार्किट कमेटियों को दिया जाए । जो सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० बनाता है, वहां पर उनके पानी के निकास का काम भी उन्हीं को दिया जाए ताकि वे सड़कें बनने के बाद चलने के काबिल हों । पानी का निकास न होने के कारण नई सड़क भी दो महीने के बाद वैसी ही हो जाती है । इस काम के लिए चाहे पैसा मार्किट से ले लिया जाए लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० महकमा ही इस काम को करे ।

एजुकेशन के बारे में मन्त्री जी ने काफी विस्तार में बताया कि एक सौ नए स्कूल खोले गए तथा 40 स्कूल अपग्रेड किए गए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विस्तार हो रहा है । मेरे हल्के में बनेरी सिंघवा और खरखला में हाई स्कूल हैं इनको दस-जमा-दो में अपग्रेड किया जाए । जैसे मैंने पहले भी बताया कि भांडाहेड़ी गांव के अन्दर स्कूल के लिए लोगों ने 26 कमरे बना दिए थे । पिछले राज में दो चीफ मिनिस्टर इस गांव में बार-बार गए और

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

उन्होंने उस स्कूल को मन्जूर कर दिया लेकिन वह स्कूल नहीं खुला । वहां पर इन्होंने तीन बार लड्डू भी बंटवाए । उसके बाद मैं बहिन शान्ति राठी को उस गांव में ले कर गया । ये 26 कमरों को देख कर हैरान रह गईं । इन्होंने एक हफते में वह स्कूल खुलवा दिया । तो आप ही अन्दाजा लगाएं कि पिछली सरकार शिक्षा में कितनी दिलचस्पी रखती थी । तीन बार लड्डू बंटवा दिए और एलान करने के बाद भी स्कूल नहीं खुला था । हमारी बहिन जी ने वहां पर प्राईमरी स्कूल खुलवाया, मैं इनका धन्यवाद करता हूं । मेरा निवेदन है कि बांडोहेड़ी तथा ढाणी पुर के स्कूलों का दर्जा भी प्राईमरी से मिडल तक किया जाए क्योंकि वहां पर काफी दूर-दूर गांव पड़ते हैं । कुछ स्कूल शहरों में भी हैं, जिनको अपग्रेड किया जाए । जैसे राम पुरा के स्कूल को भी प्राईमरी से मिडल किया जाए । उसकी मिडल स्कूल के हिसाब से बिल्डिंग बना दी गई है । इसी तरह से कुछ स्कूल मिडल से हाई भी किए जाएं । उनकी लिस्ट मैंने पहले ही दे रखी है । एक ढाणी राजू के स्कूल को मिडल से हाई कर दिया जाए । (घंटी)

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं । हमारी सरकार बहुत बधाई की पात्र है कि इसने पिछले दो सालों से यहां पर कोई उग्रवाद की घटना नहीं होने दी । हमारी पुलिस ने इस पर बहुत अच्छा कन्ट्रोल किया है । अब उनका यहां पर नामो-निशान नहीं छोड़ा है । जो ये गोली की बात करते हैं वह बिल्कुल फिजूल की बात है । डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी बंसी लाल और ओम प्रकाश चौटाला ने यह लांछन लगाया कि नारनौल में पुलिस की गोली से वह लड़का मर गया । मैं इस बारे में आपके सामने उसकी हकीकत बयान करता हूं । नारनौल मेरे हल्के के साथ लगता हुआ हल्का है । वहां पर बी0 के0 यू0 के लोग पत्थरों से ट्रैक्टर ट्रालियां भर कर लाए थे । यह मेरी आंखों देखी बात है । पुलिस ने उनको बड़ी शांति के साथ रोका लेकिन वे लोग पुलिस का घेरा तोड़ कर नारनौल में पहुंच गए और उन्होंने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए । उस समय कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए और एक शमशेर नाम का पढ़ने वाला बच्चा सिर में पत्थर लगने से मर गया । ये मेरे भाई बार-बार यह कहते हैं कि वह पुलिस की गोली लगने से मर गया, यह ठीक बात नहीं है । पुलिस के पास जो हथियार होते हैं, वह कोई देसी छर्रा या देसी कट्टा नहीं होता । उनके पास पिस्तौल या थ्री नाट थ्री की गन होती है । जिसके सिर में थ्री नाट थ्री की गोली लगेगी और वह भी नजदीक से, तो उसका सिर बिल्कुल नहीं बचता और उससे कई आदमी जख्मी हो जाते हैं । आपने एक बात यह भी कही कि उसके सिर के मांस का एक टुकड़ा दिवार पर लगा हुआ था । सिर तो पत्थर लगने से भी फट सकता है । गोली लगने से तो सिर का निशान ही मिट जाता है । आप ऐसी बातें कह करके हाउस को गुमराह न करें । मैं समझता हूं कि ये अपनी लोक-प्रियता बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कहते हैं ।

चौधरी बलवन्त सिंह मायना : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सरकार कहती है कि वह लड़का छत से गिर कर मरा है और ये कह रहे हैं कि पत्थर लगने से मरा है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : मैं कहता हूं कि वह लड़का छत पर खड़ा था और उसके सिर में पत्थर लगा और वह नीचे गिर गया।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला बार-बार उठ चुका है। इसलिए इस पर अब कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मक्कड़ साहब, आप वाईंड-अप करें।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं महिलाओं के बारे में कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मक्कड़ साहब, आप अपनी स्पीच खत्म करें। अब श्री पीर चन्द बोलेंगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : ठीक है। डिप्टी स्पीकर साहब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसकी ताईद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री पीर चन्द (रतिया-अनुसूचित जाति) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री, श्री मांगे राम गुप्ता जी ने परसों जो बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलते हुए अपने हल्के की कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, यह तरक्की की निशानी है क्योंकि गरीब आदमियों का इसमें खास तौर से ध्यान रखा गया है। म्यूनिसिपल कमेटीज, ग्राम पंचायत, ब्लाक समिति और जिला परिषद् के चुनावों में महिलाओं के लिए 30 परसेंट रिजर्वेशन रखी गई है। यह बहुत अच्छा काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं हरिजन कल्याण निगम के बारे में कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने हरिजन कल्याण निगम के माध्यम से मिनी ट्रक खरीदने के लिए बी0 ए0 और मैट्रिक पास लड़कों को जिन की संख्या 50 के करीब है, 2 लाख 75 हजार रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से लोन दिया है। इसी प्रकार से 30 बच्चों के करीब जो लड़के बेरोजगार थे, फोटो स्टेट मशीन के लिए 1 लाख 7 हजार रुपया प्रति व्यक्ति का लोन दिया है, ताकि वे अपना काम चला कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इसी प्रकार हरियाणा हरिजन कल्याण निगम ने महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी और कढ़ाई की ट्रेनिंग दी है। सरकार ने यानि हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि जो महिला सिलाई-कढ़ाई का काम सीखने के बाद अपना काम करना चाहती है, उसे 50 हजार रुपये तक का लोन दे दिया जाये और ऐसा लोन हम देते भी हैं। सरकार एक महिला को ट्रेनिंग देने पर 150 रुपया महीना देती है और 500 रुपये माहवार खर्च आता है। सरकार ये

[श्री पीर चन्द]

सारे काम इसलिए कर रही है ताकि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, वे ऊपर उठ सकें और गरीब आदमियों को लाभ हो सके । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार आधे से ज्यादा ध्यान गरीब व्यक्तियों और महिलाओं के उत्थान की तरफ दे रही है ।

अब मैं अपने हल्के की बाबत बताते हुए कहना चाहता हूं कि 1977 से पहले रतिया में सिर्फ एक थाना और एक बी0 डी0 ओ0 का आफिस था । उस समय मैं भी चौधरी भजन लाल जी के साथ था । जब चौधरी भजन लाल जी 1979 में मुख्य मंत्री बने तो मैंने उनसे रतिया की समस्याओं के बारे में निवेदन किया तो उन्होंने वहां पर जो पहले 33 के0 वी0 का पावर हाउस था, उसको बढ़ाकर 132 के0 वी0 का बनाया । इसी प्रकार से रतिया को तहसील का दर्जा दिया और वहां पर वाटर-वर्क्स बनाए गए जिससे वहां पर पीने के पानी की समस्या खत्म हो गई । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि रतिया और जाखल हल्के में वाटर वर्क्स लग जाने से और बिजली घर बन जाने से बिजली और पानी की कोई कमी नहीं रही है । इस इलाके का नीचे का पानी बहुत ही बढ़िया है । मेरे ख्याल से 1977 के बाद से अब तक वहां पर 500 से ज्यादा ट्यूबवैल्ज लग गए हैं । यह खुशी की बात है कि आज सारे हरियाणा में रतिया हल्के के अन्दर सब से ज्यादा अनाज पैदा होता है । वहां पर बहुत अच्छा और बढ़िया सीड इस्तेमाल होता है । (विघ्न) वहां पर घी की क्वालिटी भी सबसे बढ़िया है क्योंकि वहां बढ़िया नसल के दुधारू पशु हैं । उपाध्यक्ष महोदय, सारे हरियाणा को वहां से अन्न और घी की सप्लाई हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर जमींदार और मजदूर बहुत मेहनत करते हैं और वे अपनी मेहनत से सारे इलाके को खुशहाल बनाने में लगे हुए हैं और वहां की प्रगति में उनका पूरा हाथ है, इसीलिए वे लोग कामयाब हैं । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, बहबल पुर गांव जाखल और रतिया में पीने के पानी की कोई तकलीफ नहीं है । चौधरी भजन लाल जी ने मेरी बात को मान कर वहां पर विकास कार्य करवाए हैं जिसकी वजह से वहां पर आज बिजली और पानी की कोई कमी नहीं है । बहबल-पुर में 33 के0 वी0 का पावर हाउस लगाया है और नौमली में भी 33 के0 वी0 का पावर हाउस लगाया गया है जिससे इस इलाके के लोगों को बिजली में राहत मिली है । ये सारे कार्य इस सरकार के द्वारा किये गए हैं जो कि मेरे विचार से बहुत ही अच्छे काम हुए हैं ।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर कुछ कमियां भी हैं जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । आज रतिया की आबादी 30-35 हजार के लगभग है । 1977 से पहले यहां पर 5 हजार के लगभग आबादी थी अब और आबादी बढ़ी है । म्युनिसिपल कमेटी भी बनी है । अध्यक्ष महोदय, वहां पर एक बहुत बड़ी कमी है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है । टोहाना और फतेहाबाद से होते हुए पंजाब का रास्ता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहां पर रहता है । उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा फाईनैंस मिनिस्टर महोदय से निवेदन करता हूं कि रतिया शहर की इस सड़क को फोर लेन बनवाने के लिए विचार करें ताकि इस इलाके के अन्दर लोगों को सुविधा हो सके और ट्रैफिक कण्ट्रोल हो सके । उपाध्यक्ष महोदय, इस सड़क की फौर-लेनिंग बहुत जरूरी है । इसके साथ ही वहां पर रतिया में सीवरेज की बहुत अधिक आवश्यकता है । उपाध्यक्ष महोदय, रतिया शहर 3-3 या 4-4 किलोमीटर तक बढ़ गया है । अब इतनी आबादी हो गई है लेकिन आज भी औरतों और आदमियों को लैट्रीन बाहर जाना पड़ता है तो मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर भी लैट्रीन का प्रबन्ध किया जाए । आज आबादी इतनी हो गई है कि गन्दगी भी फैलती जा रही है । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर यह दिक्कत न हो, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनको वहां पर सीवरेज का भी प्रबन्ध करना चाहिए ।

दूसरे 1977 के बाद रतिया में हैफेड का कम्पलैक्स बनवाया गया और उस पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं । उस वक्त मैं उसका चेयरमैन था । उपाध्यक्ष महोदय, यह फैक्टरी दूर से ही चमकती है और इसको देखने के बाद ही पता चल जाता है कि रतिया आ गया है । वहां पर तेल भी रिफ़ाईन किया जाता है जो कि बहुत ही अच्छी किस्म का होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर एक और भी कमी है कि वहां पर जो 30 बैड का अस्पताल है वह बहुत ही छोटा है । पिछले दिनों उसका शिलान्यास मुख्य मंत्री जी ने किया था । इसके बाद तहसील की बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया गया था । उपाध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के समय में, उन्होंने एक बस स्टैन्ड का पत्थर रखा था । इनकी सरकार दो साल तक रही और वह बस स्टैन्ड नहीं बना सकी और वह पत्थर भी न जाने कहां पर गया है । मुख्य मंत्री जी ने उसके लिए भी विश्वास दिलाया है कि ये वह भी बनवाएंगे । उपाध्यक्ष महोदय, आज इन तीनों का काम शुरू हो चुका है । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको दिसम्बर 1995 तक पूरा करवा दें ताकि यह सब बनने के बाद गरीब आदमियों का भला हो जाए । (घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : पीर चन्द जी, आप वाईन्ड-अप कीजिए ।

श्री पीर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने वायदा किया था और वह काम शुरू हो चुका है । लेकिन फ़ोर-लेनिंग के बारे में भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और कहा था कि 61 लाख रुपए उसके लिए मन्जूर हो चुके हैं । मैंने उस बारे में पता किया और वह बात ठीक भी है और मुझे विश्वास भी है कि वह सड़क जल्दी ही बन जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह बहुत ही तरक्की का काम है ।

[श्री पीर चन्द]

उपाध्यक्ष महोदय, जाखल से लेकर रतिया तक जो बीस गांव हैं, वहां पर जब बारिश आती है तो फ्लड उन गांवों को तबाह कर जाता है । 1993-94 में भी जाखल गांव के अन्दर मेरे ख्याल से पांच-पांच या छः-छः फुट पानी मण्डी में चला गया था जिसकी वजह से वहां के लोगों को उस गांव से बाहर बैठना पड़ा था । 1981-82 में चौधरी भजन लाल जी ने वहां सवा करोड़ रुपये खर्च करके रंगोई नाले की खुदाई करने में लगाया था लेकिन अब वह सिर्फ चार किलोमीटर ही बीच में बनने से रह गया है । इस वजह से वहां का पानी आगे नहीं जाता और टक्कर मारकर पीछे लौट आता है । मैं मंत्री जी से और मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के जमींदारों को और गरीब आदमियों को बचाने के लिए इसका कोई स्थाई प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि वहां के लोग आराम से रह सकें । (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, आप चौहान साहब से कहें कि ये मुझे बार-बार इंटरप्ट न करें ।

प्रो० छतर सिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसको देखकर मुझे एक बात याद आ रही है कि किसी आदमी की नाक कट गयी और वह कहने लगा कि नाक कटने से भगवान दिखाई देते हैं । इस आदमी को देखकर और दो चार आदमियों ने नाक कटवा दी लेकिन उनको भगवान नहीं दिखाई दिया । फिर एक किसान कहने लगा कि ये तो अपना पंथ बढ़ाते हैं कैसा भगवान दिखाई देता है । तो सर, ये भी इसी तरह से अपना पंथ बढ़वाने में लगे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है ।

श्री पीर चन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फ्लड से वहां पर जो नुक्सान होता है, तो उसका कोई परमानैन्ट इलाज होना चाहिए (विघ्न) जब फ्लड आता है तो मेरे हल्के में बहुत नुक्सान होता है । मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । इसलिए मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में सड़कों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए । मेरे हल्के में एक सड़क तो जाखल बस-स्टैण्ड से लेकर थाने तक की है । उसको ऊंचा उठाया जाना चाहिए और ऊंचा उठाकर उसको बनाया जाना चाहिए । इसी तरह से रेलवे स्टेशन से लेकर जाखल गांव तक की सड़क को भी बनाया जाना चाहिए । यह सड़क बहुत ही खराब है और रेलवे स्टेशन को जाने के लिए लोगों को बहुत तकलीफ होती है (विघ्न) आप लोगों को तो थानों में जाना ही है इसलिए आराम से चले जाओ तो क्या दिक्कत है ? (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं . . . . . (घंटी) सर, घंटी तो कई बार बज चुकी है लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई । डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे थोड़ा सा समय और बोलने दीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूं । मेरे हल्के के स्कूलों में मास्टरों की काफी कमी है उस कमी का, मैं समझता हूं, कोई कारण नहीं हो सकता । हमारे उस एरिया के तो मास्टर होते नहीं हैं । वे हांसी, हिसार के आस-पास के हैं । वे उधर नहीं रहना चाहते । जैसे भी हो सके, सरकार मास्टरों को ट्रांसफर करके भेजे । उनको पूरी सख्ती से वहां भेजना चाहिए । दस जमा दो के जो दो स्कूल बनाए हैं, उनकी बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है, उसको परसों चालू किया है । उनमें जो अध्यापकों और कर्मचारियों व प्रोफैसरों की जरूरत है, उन्हें जल्दी वहां भेजा जाए क्योंकि लड़कियों को बहुत परेशानी होती है । उन्हें फतेहाबाद या टोहाना जाना पड़ता है । उपाध्यक्ष महोदय, जाखल पंजाब के बॉर्डर से लगता है । उसके कारण जाखल जंक्शन भी बहुत बड़ा है । चारों तरफ से गाड़ियां चलती हैं । मंडी बहुत बड़ी है । गांव बहुत बड़ा है । जाखल के साथ मेरे हल्के के 20 गांव लगते हैं । मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर ब्लाक बनाए जाएं । ब्लाक बनने से इस इलाके के लोगों की कई प्रकार की तकलीफ दूर होगी । गांव-गांव में बी0 डी0 ओ0 जाएंगे तो सड़कों और गलियों पर ध्यान देंगे । मेरा हल्का टोहाना के साथ पड़ता है । टोहाना के मंत्री जी भी हैं। वे हमारी तरफ पैसा नहीं देते हैं । अपनी तरफ लगा लेते हैं । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, आप बार-बार घण्टी मार रहे हैं इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। अन्त में मांगे राम गुप्ता जी ने, जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ (सालहावास) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । जैसा पीर चन्द जी ने कहा कि यह मांगे राम जी का बजट है । यह बात उनके मुंह से ठीक निकल गई । यह बजट चूल्हे, चक्की, मंगल सूत्र, सिंदूर यानी घर से बाहर निकला ही नहीं है। बजट से लोगों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को, विद्यार्थियों की उम्मीदें होती हैं कि बजट से कोई राहत महसूस होगी कुछ कर मुक्त होगा, कुछ मिलेगा लेकिन मांगे राम जी ने बड़ा डल और ड्राई बजट पेश किया है । पता नहीं, इन्होंने यह घर बैठकर बनाया है या कटवाल जी की बुआ के साथ बैठकर बनाया है । यह घर से बाहर नहीं निकला है । सरकार खोखले दावे करती है कि हम किसानों को बिजली देते हैं । पानी देते हैं । ये देते हैं । वो देते हैं । लेकिन देने लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जो डैफिसिट है, उसको हम कुछ कम कर सकते हैं, जो खर्चा है उसको बचा सकते हैं । डिपार्टमैंट वाईज जो वैस्टेज है, ट्रक, टैक्टर या कारें हैं, उनको समय पर ऑक्शन करके डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो इससे क्या होगा ? जो कम कीमत पर चीजें जा रही हैं, अगर वेस्टेज की सही समय पर डिस्पोजल कर दी जाए तो उन से ज्यादा कीमत सरकार को मिल सकती है । ऐसा प्रोवीजन यह हाउस कर सकता है । इस हाउस का यही काम है कि इस तरह की व्यवस्था करना । इस तरह के कानून

[चौ० जिले सिंह जाखड़]

बनाने का इस हाउस को पूरा हक है ताकि जिससे सरकार की आमदनी बढ़े न कि ट्रांसफर्ज चेंज करवाना, नौकरियों में भर्ती करना, थानों में किसी की पिटाई करवाना । यह काम इस हाउस का नहीं है जोकि यह सरकार करती जा रही है । इस तरह का प्रोजीजन इस हाउस को, सरकार को करना चाहिये ताकि डिपार्टमैंटवाईज जो-जो वेस्टेज है, उसका सही समय पर सदुपयोग किया जा सके और जो डिसपोजल के लिये पुरानी मशीनरी हो, उसका सही समय पर आक्शन करवाकर सरकारी खजाने में पैसा आ सके । सपोज कीजिये कि एक बस, या ट्रैक्टर खराब हो जाता है । अगर वह गाड़ी दो-चार, पांच लाख किलोमीटर चल गई उसके 200 किलोमीटर और चलने बाकी थे और उसका पम्प खराब हो गया तो उसमें नया पम्प लगवा दिया जाए साथ ही दो टायर लगवा दिये जाएं ताकि उस गाड़ी की कीमत बढ़ जाए । मेरा कहने का मतलब यह है कि गाड़ियाँ फिजूल में खड़ी रहने से भी खराब हो जाती हैं जिसके कारण सरकार को नुक्सान होता है । मेरा मतलब यह है कि जो गाड़ियां खड़ी हैं और वह चालू हालत में थीं जिनको समय पर डिस्पोज आफ करने से कुछ मशीनरी बच सकती थी उन्हें डिस्पोज आफ जल्दी करना चाहिए । कुछ आईटम्ज उन की ऐसी भी हो सकती थीं, जिनकी सेल में या आक्शन में कीमत बढ़ सकती थी अगर उनकी आक्शन समय पर कर दी जाती । इससे बजट में घाटे को काफी हद तक पूरा किया जा सकता था ।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ऐग्रीकल्चर के बारे में भी कहती है कि हमने इस क्षेत्र में किसानों को बड़ी सुविधा दी है, राहत दी है । स्प्रिंक्लर सैट्स के बारे में कल ही हाउस में एक क्वैश्चन आया था जिसका जवाब कैटेगरीकली देने की बजाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर टाल गये लेकिन सच्चाई यह थी कि इन्होंने स्प्रिंक्लर सैट्स पर सब-सिडी नहीं दी है । मुझे इस बात का पूरा ज्ञान है क्योंकि मेरे इलाके में बहुत सारे स्प्रिंक्लर सैट्स लगे हुए हैं । न ही इन्होंने किसानों को सब-सिडी दी थी और वह पैसा सरण्डर कर दिया । न ही जिस कम्पनी से वह सैट्स खरीदे गये, उन से रेट वगैरह ही तय किया । जो सबसिडी इन्होंने 1993-94 में दी वह 30.50 लाख रुपये की राशि थी और उसमें केवल 6.9 लाख रुपये ही खर्च हुए और जो मनी सरण्डर हुई, वह थी 24.2 लाख रुपये जोकि सब से ज्यादा है हालांकि उस वक्त बजट में इसके लिये बहुत थोड़ा पैसा रखा गया था । सब-सिडी सरण्डर करने का कारण यह था कि सरकार ने उस कम्पनी से रेट वगैरह फिक्स नहीं किया था और न ही सब-सिडी देने पर ध्यान दिया और न ही किसानों की मुश्किल की ओर ही ध्यान दिया गया जिस के कारण से किसान स्प्रिंक्लर सैट्स नहीं ले सके ।

इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहूंगा कि खाद के रेट्स कितने बढ़ गये हैं । बीज के रेट्स कितने बढ़ गये हैं । इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान

नहीं दिया । अगर समय पर किसानों को खाद व बीज मिल जाते , तो उनको काफी फायदा हो सकता था । यह बात तो ठीक है कि पिछले साल की निस्बत खाद ज्यादा है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक समय पर नहीं हुआ । अगर समय पर डी० ए० पी० तथा यूरिया किसानों को मिल जाती तो जो ब्लैक में यह चीज आई, वह कभी न आती जो अब स्थिति हुई , वह न आती । ब्लैक मार्किटिये बीच में न आते ।

डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से पैस्टीसाईडज का मामला है । दवाईयां भी असली नहीं रही हैं । जहर भी अगर किसान को असली न मिले तो उससे बुरी बात और क्या हो सकती है ? अगर किसान को अपने खेतों के लिये, अपनी बागवानी के लिये दवाईयां भी असली न मिलें और उन नकली दवाईयों का कोई असर भी न हो, तो उस बेचारे किसान के ऊपर क्या गुजरेगी ? इसको आप सब भली भांति समझते हैं । नकली दवाईयों का कोई असर हो ही नहीं सकता । मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह के जो ब्लैक-मार्किटिये हैं, जो नकली दवाईयां बेचते हैं, उन पर निगाह रखे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करें ताकि वे भविष्य में नकली दवाईयां न बेचें जिससे किसानों के खेतों को फायदा होने की बजायें नुक्सान हो ।

जहां तक बिजली पानी का सवाल है, इस बात को सरकार खुद मानती है कि पानी और बिजली में कमी आई है । इस बारे में सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि इरीगेटिड एरिया के अन्दर जो बिजाई की गयी, उसके आधार पर यह बात इकनामिक सर्वे आफ हरियाणा में साफ लिखा है :—

> "The percentage of net area irrigated to net area sown and gross area irrigated to total area cropped decreased from 76.0 and 77.9 in 1991-92 to 75.3 and 76.4, respectively, in 1992-93."

इसका मतलब यह हुआ कि . . . . . ।

चौधरी जगदीश नेहरा उपाध्यक्ष महोदय, जिले सिंह जी जो फिगर्ज तथा तथ्य दे रहे हैं, वह सदन को गुमराह करने वाली बात है। जो बारानी जमीन है, वह बारिश पर निर्भर करती है । सिंचाई में कोई कमी नहीं है । जो सिंचाई से बिजाई हुई, अगर उसमें बिजाई कम हुई, तो वह सिंचाई का कसूर है और यदि बारानी में बिजाई कम हुई, तो वह बारिश का कसूर है । यानि बारिश कम हुई है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : इसमें लिखा है "नेट इरीगेटिड एरिया" । इसमें बिजाई कम हुई क्योंकि नहरों में पानी नहीं था और ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली नहीं थी । दूसरी बात ये कहते हैं कि एस० वाई० एल० का निर्माण कार्य तथा डब्ल्यू० जे० सी० की डी-सिल्टिंग करेंगे और वी० एम० एल० में पानी ज्यादा लाएंगे । लेकिन बजट के अन्दर एस० वाई० एल० के लिए एक पैसा भी नहीं रखा ।

चौधरी जगदीश नेहरा : एस० वाई० एल० के लिए 16 करोड़ 60 लाख रुपए बजट में रखे हुए हैं (शोर)

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : आप यह बात बताएं कि 16 करोड़ रुपए से क्या-क्या करोगे ? यह तो हाथी के मुंह में जीरा देने वाली बात है । मैं बताना चाहता हूं कि इस नहर का निर्माण कार्य बन्द हो गया है और किसानों को पानी नहीं मिल रहा है । इस वजह से हरियाणा की लाईफ लाईन का नुक्सान हुआ । इस नहर के निर्माण वाली 34 कम्पनियां ऐसी हैं, जिन्होंने 2535.23 लाख रुपए का दावा आपके महकमे के ऊपर किया और यह पैसा आपसे लिया । इसके बावजूद आप कहते हैं कि बजट में इसके लिए 16 करोड़ रुपए रखे हैं । इस तरह से हमें 2535 लाख रुपए का नुक्सान हो गया । तो 16 करोड़ रुपए से क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : यह जो पैसा दिया गया है इसका ताल्लुक क्या एस0 वाई0 एल0 से है ?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : जी हां, मैं उन कम्पनियों के अलग-अलग नाम बता सकता हूं कि किस-किस कम्पनी ने कितने-कितने पैसे लिए ।

चौधरी जगदीश नेहरा : ये जो कम्पनियों की बात कर रहे हैं, उनके फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज इस समय मेरे पास नहीं हैं । हो सकता है कि किसी कम्पनी ने काम बन्द कर दिया हो, किसी का कोई डिसप्यूट हो या कुछ केस कोर्ट में पड़े हों । यह बात तो उसके बारे में है, जो पंजाब में काम हुआ है । यह मामला सब-जुडिस है इसलिए इसकी फैक्ट्स एण्ड फिगर्ज मैं नहीं दे सकता ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 2535.23 लाख रुपए उन कम्पनियों ने ले लिए । इसमें आपकी कोताही रही है । अगर आप ऐसे एग्रीमैंट न करते तो इतना पैसा फिजूल में हमारे एक्सचैकर से न जाता । अगर पैसा पंजाब गवर्नमैंट में भी जमा करवाया तो भी हमारा शेयर गया । इन तथ्यों के आधार पर आप इन-फ्यूचर ऐसे अनुबन्ध किसी कम्पनी से न करें । अगर किसी वजह से कोई काम बन्द हो जाए, तो वह कम्पनी सरकार पर दावे ठोक ठोक कर फिजूल खाते में काम बन्द कर देगी । वह इस तरह से करोड़ों रुपए बना रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ । इतना पैसा गया, आपको उसका पता क्यों नहीं ? आपको उसका पता होना चाहिए । दो-तीन कम्पनीज हों, तो ठीक है लेकिन ये तो 34 कम्पनीज हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर एक्वाडक्ट बन रहे थे, साईफन बन रहे थे । रेलवे के ब्रिज बन रहे थे । जो नाले नीचे से जा रहे हैं और ऊपर से जा रहे हैं, उनके एक्वाडक्ट बने हैं । बहुत से काम बन्द हो गए हैं । किसी का लिटिगेशन हो गया । किसी को पैसा दे दिया । किसी को देना है । यह मामला सब-जुडिस है । अगर आप कोई स्पैसिफिक बात कहें, तो हम उसकी इन्कवायरी करवा सकते हैं । लेकिन किसी को गलत पैसे की पेमेंट करेंगे, उसकी सम्भावना नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेहरा साहब, जो वहां पर एग्जीक्यूटिंग एजेंसिज हैं, क्या वे आपके डिपार्टमैंट की हैं ?

चौधरी जगदीश नेहरा : नहीं जी ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा कहना है कि ये किसी कम्पनी के साथ ऐसा कोई अनुबन्ध न करें जिससे स्टेट के एक्सचैकर को नुकसान हो । इसके अलावा, मेरा सुझाव है कि डब्ल्यू0 जे0 सी0 से हमारे रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ नारनौल, रोहतक और सोनीपत जिलों को पानी मिलता है । उस नहर को डी-सिल्ट नहीं किया गया है जो ताजेवाला हैड वर्क्स है, वह कमजोर है । उस नहर की हालत ऐसी है कि जैसे पानी के टब होते हैं । हमने कमेटी की तरफ से वहां विज़िट किया था । ताजेवाला हैडवर्क्स पर कैंकस हैं। उस नहर का ताजे वाला हैड वर्क्स से ले कर ऐण्ड तक सर्वे किया था । वह नहर सारी ऐसी है, जैसे टापू बने हों । उसमें भैंसे बैठी थीं । झुण्ड उगे हुए थे । मैं कहता हूं कि सरकार उसकी डि-सिल्टिंग करवा करके उसकी कैपेसटी दे बढ़ाए ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाईज़ किया जा सके । एक दिन में 70 लाख क्यूसिक पानी वेस्ट चला जाता है । बरसात के दिनों में उस पानी को स्टोर करके रोहतक, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़, नारनौल जिलों की नहरों में छोड़ दिया जाए क्योंकि उन ईलाकों के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है । वहां वाटर टेबल लगभग 100 फुट नीचे चला गया है । कम से कम उनको पीने का पानी तो मिल जाए ।

चौधरी जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आफ आर्डर है । मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने जो सवाल उठाए, उनका हमने जवाब दिया है । इन्होंने कहा कि ताजेवाला हैड वर्क्स टूटा हुआ है । मैं इनको बताना चाहूंगा कि हथनी कुण्ड बैराज बनाने के लिए समझौता हुआ है । उस पर डैम बनेंगे । डब्ल्यू0 जे0 सी0 जो 16,000 क्यूसिक्स की कैपेसिटी की है, उसको हम 28 हजार क्यूसिक्स की कैपेसिटी की बनाएंगे ताकि उस पानी को बैरानी ईलाकों में ले जा सकें और री-चार्जिंग कर सकें । लेकिन जो समझौता है, उसी समझौते का ये विरोध कर रहे हैं । उसी के बारे में सुझाव दे रहे हैं । आखिर आप चाहते क्या हैं ? आप सुझाव दे रहे हैं और आपकी पार्टी उसका विरोध कर रही है, ऐसा क्यों ?

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मेरा सुझाव है कि डब्ल्यू0 जे0 सी0 की डी-सिल्टिंग की जाए ।

चौधरी जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बात हम कह रहे हैं, वही बात ये कह रहे हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । अभी नेहरा जी ने प्वायंट आफ आर्डर के बहाने से जमुना एकार्ड का जिक्र कर दिया ।

[श्री सम्पत सिंह]

जो डी-सिल्टिंग की बात है, यह बिल्कुल सैपरेट है । इसकी डी-सिल्टिंग पांच स्टेट्स मिल कर करवाएंगी । ऐसी बात बिल्कुल नहीं है । यह स्टेट का अपना सबजैक्ट है और स्टेट की अपनी टैरिटरी है । जमना में जो गाद है, मिट्टी भरी हुई है उससे वहां आइलैंड बने हुए है । उसको आप रिमूव करें ताकि पानी का फ्लो ठीक हो । ये जिक्र कर रहे थे कि जमुना का पानी बढ़ जाएगा, हम इस बात को नहीं मानते । आपने 30 परसैन्ट पानी कम कर दिया और कम करके तीन स्टेट्स को दे दिया । आपने हमारे इंटैस्ट को सैकरीफाईस कर दिया । वह ईशू अलग है । यह केवल जमना नहर से गाद निकालने की बात थी । आप उस बात को टाल कर उसकी आड़ में इस समझौते की बात कर रहे हैं । यदि उसके बारे में डिस्कशन करनी है तो आप दो-चार घण्टे उस बारे में डिस्कशन कर लें, हम तैयार हैं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने ताजेवाला हैड वर्क्स का जिक्र किया कि उसमें करैक्स आए हुए हैं और कहा कि डब्ल्यू0 जे0 सी0 की कैपेसिटी बढ़ाएं और पानी लगातार मिलना चाहिए । इस बात का जमना अकोर्ड के साथ संबंध है । जो ये उसमें गाद की बात कह रहे हैं, और जो सुझाव दे रहे हैं, उसी सन्दर्भ में मैंने अर्ज किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी जिले सिंह जी, आप अपने हल्के की ही बातें कहें ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : मैं अपने हल्के के बारे में ही बात कर रहा हूं क्योंकि डब्ल्यू0 जे0 सी0 मेरे हल्के में जाती है । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन नहरों की सफाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाया जाये ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ सके और लोगों को पानी पहुंच सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में जिक्र करना चाहता हूं । इन्होंने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए लेकिन बिजली की फिर भी हालत खराब है । इन्होंने दिखाया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता कि बजट के सप्लीमैंटरी नोट में 205 में कुछ तहसीलों के नाम दिए हैं जैसा कि तहसील दादरी, नारनौल, महेन्द्रगढ़, सब तहसील मातनहेल अण्डर रिवाड़ी, सब तहसील साल्हावास, कोसली अण्डर झज्जर । यह तो रिवाड़ी में हैं । मैं बताना चाहता हूं कि यह गलत सूचना दी है । मेरा इलाका रिवाड़ी के साथ लगता है । वहां पर तो डीप ट्यूबवैल का अलग रेट है और हमारे यहां पर अलग है । इस बारे में मैं बिजली मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डीप ट्यूबवैल के हिसाब से जो टैरिफ रखा गया है वही हर जगह एक जैसा होना चाहिए ।

बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि साल्हावास के किसानों की संघर्ष समिति पिछले 14 महीने

से एजीटेशन चला रही थी । वे कल शाम मुझे मिले थे । अब फैसला हो गया है और बिजली का बिल भी जो लोग दे नहीं रहे थे, वे भी देना मान गए हैं । मैं साल्हावास भी गया था । उस समय मैं उनको आश्वासन देकर आया था । उसी दिन मैंने आर्डर कर दिए थे कि इसको ठीक ढंग से एग्जामिन करेंगे ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चलो सिंचाई मंत्री जी ने बता दिया कि इस पर ठीक ढंग से विचार करेंगे, तो मैं इस बात को खत्म करता हूं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने कागजों में ही बिजली बढ़ाई है । इन्होंने कुछ कट अनडिकलेयर्ड भी लगा रखा है क्योंकि बगैर सूचना के भी कई जगहों पर 3–4 घण्टे तक बिजली नहीं आती । मेरा अनुरोध है कि ऐसे अन डिक्लेयर्ड कट्स न लगाएं । इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जानी चाहिए ताकि बच्चे पढ़ सकें और लोग अपना अपना काम कर सकें । यह सरकार कहती है कि हरियाणा एक वैल्फेयर स्टेट है । मैं बताना चाहता हूं कि तामिलनाडू एक वैल्फेयर स्टेट है । वहां पर किसानों से ट्यूबवैल चलाने के बिजली के पैसे नहीं लिए जाते । चाहे वह एक घंटा ट्यूबवैल चलाएं या 6 घन्टे चलायें । इसी प्रकार से आन्ध्र प्रदेश एक वैल्फेयर स्टेट है, जहां बिजली की कौस्ट 1.36 रुपये आने पर भी किसानों से सरकार केवल 15 पैसे ले रही है । तो फिर इस तरह से हरियाणा वैल्फेयर स्टेट कहां हुई ? ये कहते हैं कि हरियाणा दो नम्बर की स्टेट है । यदि ये इसी प्रकार से चलते रहे तो हरियाणा 10 नम्बर पर आ जायेगा । मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पानीपत थर्मल प्लांट की 5वीं यूनिट का उद्घाटन हमने किया था और छठी यूनिट का शिलान्यास भी किया था । फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे समय में कोई काम नहीं हुआ ? यमुनानगर के प्लांट का सारा हिसाब-किताब हमने तैयार किया । हमने 1990 में इस प्रोजैक्ट को तैयार करके एन0 टी0 पी0 सी0 को दिया । वे काम न करें तो हम क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष : जिले सिंह जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और बिजली मन्त्री जी ने इनको एप्रिशियेट भी किया है । (विघ्न) आप अब कन्क्लूड कीजिए ।

13.00 बजे

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के कनैक्शन के लिए एक सैल्फ फाईनैंस स्कीम है । मेरे हल्के के कई लोगों ने सैल्फ फाईनैंस स्कीम के तहत पैसे जमा करवा रखे हैं । परन्तु उनको कनैक्शन नहीं दिए गए हैं । सरकार ने पैसा तो ले लिया लेकिन उसका फायदा किसान को नहीं हुआ और उसे कनैक्शन नहीं मिला । एक केस श्री राम कुमार पुत्र श्री सूरजीत कुमार, नया गांव, का है । उसने 15–12–91 को 2500 रुपये भरवाये थे क्योंकि उसने केवल कनैक्शन लेना था । उससे पैसा जमा करवा लिया गया लेकिन 18–12–1991 को जे0 ई0 ने उसको कह दिया कि आप इलिजिबल नहीं हैं क्योंकि यह ट्यूबवैल आपके भाई के सांझे खाते में है जबकि

[चौ० जिले सिंह जाखड़]

वह प्रिमसिज़ अलग है और वह अलग है । उसको कनैक्शन देने में अगर कोई हिच थी तो उससे पैसा क्यों भरवाया गया । अगर पैसा भरवाया गया है तो उसको कनैक्शन दिया जाना चाहिए था । करीब पांच साल उसे पैसा जमा करवाए हुए हो गए हैं और उसने फिटिंग भी करवा रखी है लेकिन उसको कनैक्शन आज तक नहीं मिला । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मार्च के दिनों में किसानों के कनैक्शन काटे जा रहे हैं । मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि सढौरा में भी कनैक्शन काटे जा रहे हैं । अगर आज मार्च के महीने में किसान के कनैक्शन काटे जाएंगे तो वे बिल आगे कहां से जमा करवाएंगे । मुख्य मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे समय में किसानों के कनैक्शन्ज़ न काटे जाएं अगर किसी का कोई बकाया है, तो दो महीने बाद आ जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रांसपोर्ट का सवाल है, सारी की सारी एक्सप्रैस बसें खरीदी गई हैं । 363 में से एक भी साधारण बस नहीं खरीदी गई । इन्होंने खुद माना है कि सारे फलीट में एक बस की कमी हुई है । जो 363 बसें खरीदी गई हैं, वे सारी की सारी एक्सप्रैस खरीदी गई हैं जो कि रोड्ज़ पर खाली चलती हैं किसी बस में 30 सवारियां होती हैं और किसी में 20 सवारियां होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि सौदा मंहगा हो गया है इसलिए किराया इन्क्रीज़ कर दिया। इन बसों का 25% किराया ज्यादा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राईवेट ट्रांसपोर्टरों को जो परमिट सरकार ने दिए हैं, वे सारे के सारे रो रहे हैं क्योंकि जो रूट्स इनको मिले हैं, वे वायेबल नहीं हैं और सरकार ने टैक्स ज्यादा लगा दिया है लेकिन उनको लम्बे रूट्स नहीं दिए । एक तरफ परमिट्स लेने वाले रो रहे हैं और दूसरी तरफ सवारियां परेशान हैं । सरकार ने छोटे-छोटे रूट्स पर से अपनी बसें हटा ली हैं और जब कोई तगड़ी ब्याह शादी होती है, तो परमिट वाली बसों को बुक कर लेते हैं और रूट्स पर बसें न मिलने के कारण सवारियां परेशान होती हैं और 10–20 किलोमीटर का सफर पैदल करें या कोई और आल्टरनेटिव ढूंढे । इसलिए सरकार से मेरा यह सुझाव है कि सरकार ने जो प्राईवेट परमिट्स दिए हैं, उनके रूट्स बढ़ा दिए जाएं या उनको ऐसे रूट्स दिए जाएं जहां उन की डिमांड है ताकि सवारियों को भी परेशानी न हो और प्राईवेट ट्रांसपोर्टर्ज़ भी घाटे में न चलें ।

उपाध्यक्ष महोदय, जे० आर० योजना के तहत 1993–94 में 34.63 लाख मैन डेज़ थे और 1994–95 में 33.29 लाख मैन डेज़ हैं । 15.35 लाख मैन डेज़ में से भी 9 महीने में आधे से भी कम मैन डेज़ कवर हुए हैं और बाकी के 3 महीनों में बाकी के मैन डेज़ ये लोग कैसे बना लेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, जौहड़ खोदने के लिए ट्रैक्टर्ज़ चलते हैं । पब्लिक हैल्थ में भी डिग्गी खोदने के लिए टैक्टर्ज़ का प्रयोग किया जा रहा है और कागजों में मैन डेज़ दिखा दिए जाते हैं इसलिए सरकार असत्य रिपोर्ट न दे और मजदूरों का जो काम है, वह मजदूरों से ही करवाएं और जौहड़ मजदूरों से ही खुदवाए जाने चाहिएं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में

कई जौहड़ ऐसे खुदवाए गए हैं, जिनकी जरूरत नहीं हैं क्योंकि सरकार को पता नहीं कि जौहड़ किस लिए होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जौहड़ इसलिए होते हैं ताकि बरसात का पानी इनमें इकट्ठा हो जाए और 2-4 महीने पशु पानी पी लें लेकिन सरकार पैसा खाने के लिए जौहड़ पर जौहड़ खुदवा रही है । एक-एक जगह पर ट्रैक्टरों से 5-5 जौहड़ खुदवा दिए हैं । इस बारे में मेरा सुझाव है कि मैन डेज़ कागजों पर हैं । असल में नहीं है । इसलिए मैन-डेज़ को सही इस्तेमाल किया जाए साथ ही इसे बढ़ाया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक इकनौमिक सर्वे ऑफ हरियाणा में लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम का जिक्र है पता नहीं यह कौन सी स्कीम है ? इसमें 0.50 करोड़ रुपया रूरल सैनिटेशन के लिए दिया गया है । यह पैसा कहां खर्च किया गया है । हमें तो कहीं नज़र नहीं आया । गांवों की सैनिटेशन के लिए बहुत थोड़ा पैसा सरकार ने रखा है । सड़कों पर कुरड़ियां पड़ी रहती हैं । महिलाओं, माताओं-बहनों को बाहर जाने के लिए बहुत तंगी है । वे बेचारी बार-बार उठती हैं । बार-बार बैठती हैं । सरकार को उनके लिए कोई अरेन्जमैन्ट करना चाहिए । इस बारे में मेरा सुझाव है कि 2-2, 4-4 एकड़ जमीन गांव के आस-पास छोड़ दी जाए और उसकी चारदिवारी करवा दें । वहां पर कम्यूनिटी लैट्रिन्ज कामयाब नहीं हैं क्योंकि शहरों में जहां वाटर सप्लाई है और सफाई वाले भी रहते हैं ये लैट्रिन्ज वहां पर भी वायेबल नहीं हैं तो फिर गांवों में तो इस किस्म की व्यवस्था का कोई फायदा नहीं है । (घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में जहां नकल रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं वहीं स्कूलों को भी अपग्रेड किया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया । जो बिल्डिंग लोग अपने आप बनाते हैं, उन स्कूलों को भी अपग्रेड नहीं करते । गुप्ता जी, मैंने पिछले बजट पर अपने भाषण में कहा था कि मेरे हल्के में गरोहड़ गांव में एक ऐसी बढ़िया बिल्डिंग है, जो शायद हरियाणा में रिकार्ड है कि ऐसी बढ़िया बिल्डिंग कहीं नहीं है । यह बिल्डिंग लोगों ने अपने पैसे से 25 लाख रुपये का चन्दा लगा कर बनाई है जिसमें एक हाल और 24 कमरे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस स्कूल को आज तक अपग्रेड नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि इसको लड़कियों के लिए 10 जमा 2 के स्कूल में अपग्रेड कर दें ताकि इलाके की लड़कियां ही इसमें पढ़ लें । शहरों में तो गुप्ता जी, सरकार पहले खुद स्कूल की बिल्डिंग बनाती है और वे अपग्रेड भी हो जाते हैं लेकिन इस के लिए बिल्डिंग होने के बावजूद इसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : जिले सिंह जी, आप वाइंड-अप कीजिए ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहता हूं कि इन्होंने 1994-95 में 3 गांवों में 110 लीटर प्रति व्यक्ति और 1995-96

[चौ० जिले सिंह जाखड़]

में 170 लीटर गांव में पानी देने का सुझाव है । इसमें भिवानी, रोहतक और रिंवाड़ी आते हैं । इसके अलावा इन्होंने प्राईवेट कनैक्शन भी दिए हैं । मैं भी एक मैम्बर हूं और मैंने भी एप्लाई किया हुआ है लेकिन मुझे कनैक्शन नहीं दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां भी ये कनैक्शन दें वहां वाटर वर्कस की कपैसिटी भी बढ़ाएं । उपाध्यक्ष महोदय, टेल पर पानी नहीं है और नलके सूखे पड़े हुए हैं । वहां पर वाटर सप्लाई की बहुत ही भारी कमी है । कागजों पर तो लोग बहुत ही अच्छा पानी पी रहे हैं लेकिन असल में वहां पर पानी नहीं है । मेरी इनसे गुजारिश है कि ये टेल पर पानी पहुंचाएं और कैपैसिटी भी बढ़ाएं । (घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, झज्जर तहसील रोहतक में है । वहां पर सड़कें नाम मात्र की हैं और जो हैं भी, वह ठीक नहीं हैं । उनमें 6–6 फुट गहरे खड्डे पड़े हुए हैं और पिछले तीन सालों से वहां पर सड़कों का कोई भी काम नहीं हुआ है । दूसरे यहां पर एक सैनिक स्कूल के लिए भजन लाल जी ने एक पत्थर लगाया था । उसका भी कुछ नहीं हुआ है ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इन्हें पांच लाख रुपया दिया है ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमें नहीं पता कि वह कौन ले गया है और इन्होंने किसको दिया है ? एक सड़क सालहावास से खानपुर तक है । जब हम दादूपुर से बिलोटा के तरफ आते हैं, तो पता चलता है कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट आ गया है । तो मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि जहां पर सड़कों की जरूरत है, वहां पर सड़कें बनवाएं और जो टूटी पड़ी हैं, उनकी रिपेयर करवाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : जिले सिंह जी, अब आप बैठ जाएं ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ओल्ड एज पैन्शन, विडोज पैन्शन और हैंडीकैप्ड पैन्शन के बारे में पूछना चाहता हूं कि जब से यानि कि जिस तारीख को कोई हैन्डीकैप्ड हुआ है या कोई विधवा हुई है, उसको उसी तारीख से पैन्शन दी जाएगी या नहीं ? उपाध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी की बात है । गवर्नर साहब को करनाल के अन्दर आना था । वहां पर फैसला किया गया कि गवर्नर साहब और मुख्य मंत्री के अलावा किसी की गाड़ी अन्दर नहीं जाएगी । वहां पर मंत्रियों की और एम० एल० एज० की गाड़ियां बाहर खड़ी रहीं । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों का प्रोटोकोल में 14वां नम्बर, एम० एल० ए० का 22वां नम्बर और चीफ सैक्रेटरी का 24वां नम्बर होता है । जब चीफ सैक्रेटरी की गाड़ी आई तो वह सीधी अन्दर चली गई । तो वहां पर एक ए० एस० पी० ने कहा कि सर, गाड़ी उधर ले जाएं । डी० सी० ने कहा कि इनको आने दो और जब पूछा गया कि किस ने गाड़ी को रोका था तो बताया गया कि "This Stupid Fellow" अगर इस तरह ब्यूरोक्रैट्स द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और आई० पी० एस० की बेइज्जती की

जाती है तो यह बहुत ही शर्म की बात है । सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए । इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

चौधरी जगदीश नेहरा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । सर, जो यह बात कही गयी है इसका तो कोई आधार नहीं है । जो आदमी इस हाउस में न हो और वह यहां पर अपनी बात को स्पष्ट न कर सकता हो तो ऐसे आदमियों के खिलाफ ऐलीगेशन नहीं लगाना चाहिए । इनकी यह बात अच्छी नहीं है ।

चौधरी जिले सिंह जाखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है मैंने तो चीफ सैक्रेटरी की पोस्ट के बारे में कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजमत खां ।

श्री अजमत खां (हथीन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । मैं आपके माध्यम से कुछ बातें तो बजट के बारे में कहना चाहूंगा । मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि पता नहीं क्यों आपकी निगाहें उस साईड में ही ज्यादा रहती हैं । हमारी साईड में तो आपकी निगाहें आती ही नहीं । हमारी तरफ भी आपकी निगाहें आनी चाहिएं । आप रिकार्ड उठाकर देख लें कि कितनी कम बार तो हमें टाईम मिलता है ? कितनी बार उस साईड के लोगों को टाईम मिलता है और हमारी तरफ से भी बोलने वाले को कितना समय बोलने के लिए मिलता है, यह आप देख लें । अगर हमारी तरफ आपकी निगाह नहीं जा सकतीं, तो आप हमारी सीट ही इधर से बदलवा दीजिए और ऐसी जगह हमें सीट दे दें जहां पर आपकी निगाहें चली जाएं ।

श्री उपाध्यक्ष : अजमत खां जी, कई बार तो ऐसा हुआ है कि जब आपका बोलने का वक्त आता है तभी आप हाऊस से खिसक जाते हैं ।

श्री अजमत खां : सर, मैं अर्ज कर रहा हूं कि कई बार ऐसा हो जाता है लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले चार साल हो गए आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए । मैंने अपने जो सवालात दिए थे, या तो वे डिस अलाउ हो गए हैं या फिर वे लास्ट में आए जिसकी वजह से मुझे अपने सवालात पूछने का समय ही नहीं मिला । सर, मुझे इस सब का अफसोस होता है । मैं अपने इलाके की कई बातें यहां पर लेकर आता हूं । लेकिन मुझे उन बातों को सदन के पटल पर रखने की इजाजत नहीं दी जाती । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्साफ हर आदमी को मिलना चाहिए । मेरा आपसे एक अनुरोध है । मेरी आवाज इन्साफ की आवाज है और मेरी मांग है कि मैं अपने जो भी सवालात यहां पर उठाना चाहता हूं उनके लिए मुझे समय नहीं दिया जाता जोकि दिया जाना चाहिए । जो एक एम0 एल0 ए0 बनकर आता है, अगर उसको साल में एक या आधा अवसर ही

[श्री अजमत खां]

बोलने के लिए मिलेगा तो वह कैसे इतने समय में अपनी बात बोल सकता है ? एक एम0एल0ए0 के कितने प्रिविलेज होते हैं, कितना उस पर पैसा खर्चा होता है । अगर वह सब हिसाब लगाया जाए तो एक एम0एल0ए0 की एक दिन की तनख्वाह चालीस हजार रुपये जाकर बैठती है । एक एम0एल0ए0 को अपने इलाके की बातों को कहने का तो वक्त मिलना ही चाहिए । अपनी बातों को कहने का तो उसका हक है । उसका प्रिविलेज है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अर्ज कर रहा हूं कि—

"अपने भी मुझसे खफा, बेगाने भी नाखुश,
मैं जहरे हलाहल को, कभी कह न सका कन्द"

सर, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हाउस के अन्दर बेजा बातों के लिए बहुत समय बर्बाद होता है । आप हमारे हकों के कस्टोडियन है । इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं इसलिए आपको यह सब देखना चाहिए । यहां पर एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं । लेकिन कभी भी काम की बातें यहां पर नहीं होती हैं । आपका हाउस की मर्यादा को मेनटेन करने का फर्ज बनता है । कौन सा ऐसा वक्त रहा है और कौन सा ऐसा आदमी है, जो दूध का धुला है और किस आदमी के समय में ज्यादती नहीं हुई है ? ज्यादती तो बाअौकात हालात से होती हैं, बाअौकात जानबूझकर होती हैं लेकिन कोई भी वक्त ऐसा नहीं रहा है, जिसमें ये ज्यादती न हुई हों । अगर उन ज्यादतियों को सरकार बेनकाब करे, तो अच्छी बात है । लेकिन अगर उनको छिपाने की बात हो, तो वह गलत बात है । लेकिन ज्यादती तो हमेशा छिपायी ही गयी है । सर, हर दौर में ये ज्यादती हुई है । इसलिए मैं अपोजीशन के लीडर्ज से भी और अपने साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे ऐसी बातों पर समय बर्बाद न करें ।

सर, अब मैं अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं क्योंकि कहीं बाद में ऐसा न हो जाए कि आपकी घंटी बज जाए । मैं पहले एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । ऐग्रीकल्चर के लिए पानी की जरूरत है और पानी या तो जमीन से आएगा या फिर नहरों से आएगा । बदकिस्मती से हमारा इलाका, फरीदाबाद, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी, जिधर से नहरें आती हैं, के लास्ट में जाकर पड़ता है । लेकिन अब उनके लिए पानी का इन्तजाम कैसे हो ? बरसात के दिनों में हमारे यहां यमुना रिवर में काफी पानी होता है । यह पानी गुड़गांव कैनाल से हमारे एरिये में पहुंचाया जा सकता है । 1978 में जो ड्रेनेज सिस्टम आउट लेट के लिए बनाया गया था, उसके बाद वह आज तक काम नहीं आया है । वहां ज्यादा बारिश भी नहीं हुई है । मेरा आपसे अनुरोध है कि बरसात के दिनों में हमारे इलाके की ड्रेन्ज को भर दिया जाए जो कि गुड़गांव कैनाल से भरी जा सकती है । इस पर केवल ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये की लागत आएगी । ड्रेनों के बीच में जगह-जगह पर बंबे लगा दिए जाने चाहिएं । इन बंबों के लग जाने से वह पानी रुक जाएगा

और जो पानी उन्हीं ड्रैनों के जरिए यमुना में जाकर गिरता है, वह पानी हमारे इलाकों में रहेगा जिससे फसलों की सिंचाई हो सकेगी और पानी का वाटर लेवल भी ऊपर रहेगा तथा मेवात के इलाके का 80 प्रतिशत रकबा काश्त भी हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था और इस बार भी मेरी अर्ज है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपये की लागत आएगी इसलिये इसे कर दिया जाए।

1980 में मलाई फीडर के नाम से एक फीडर बनाई गई थी। आज वहां के अफसरान जाकर देखें कि वहां कितना काम हुआ है ? किसी ने देखने की जरूरत महसूस नहीं की। कितना पैसा उस पर लगा है ? उसके बावजूद एक बून्द पानी भी आज तक उससे नहीं आया। क्यों वह पैसा बेकार लगाया गया और क्यों लोगों की जमीन ऐक्वायर की गई ? आज उस जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जे कर लिए। वाटर स्टोरेज के लिए जो जमीन खोदी गई थी, लोगों ने उस पर मिट्टी डालकर उन्हें जोहड़ों में तबदील कर लिया। कोई अफसर आज देखने के लिए नहीं जाता कि क्यों और किस परपज के लिए यह बनाई गई थी। ड्रैनें जो हैं, उनको भी लोगों ने जोहड़ों में शामिल कर लिया। उनकी सफाई तक नहीं होती। मलाई ड्रेन को लोगों ने खोदकर जोहड़ों में शामिल कर लिया और मछली पालन के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस तरीके से एक बार किसी चीज को बनाकर फेंक देना और उस पर पैसा वेस्ट करना जिस परपज के लिए वह बनाई गई है, उस परपज का पूरा न होना, क्या यह ठीक है ? मेरी आपसे अर्ज है कि मेवात के इलाके के लिए सबसे बेहतर सिस्टम यह है कि बरसात में ड्रेनज को भर दिया जाए, जगह जगह बांध लगा दिए जाए। इससे इतना पानी उसमें हो जाएगा कि पानी ऊपर आएगा और वह मीठा पानी होगा और ऐसा होने से एग्रीकल्चर की उपज भी बढ़ेगी। खाद, बीज सब सरकार देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन अफसरान ढिले करते हैं। जब जरूरत होती है, उस वक्त बीज नहीं मिलता, जब जरूरत होती है, खाद नहीं मिलता। वही खाद दस दिन के बाद आता है। वही बीज एक महीने के बाद आता है और कभी तो उस बीज को खाद के साथ जबरदस्ती देते हैं, क्योंकि बीज लेट आया और फिर किसान को जबरदस्ती देने की बात शुरू हुई। जो भी काम करने हैं, होते तो वे हैं, लेकिन अगर टाईम पर हों, तो अच्छा रहता है। एग्रीकल्चर जो हरियाणा की है, वह हरियाणा की ही नहीं बल्कि देश की रीढ़ की हड्डी है। हरियाणा ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। जितनी हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैदावार हो जाती है और यह सब सरकार की कोशिशों की बदौलत है। सरकार अच्छे बीज, खाद और पानी की सहूलियतें देकर किसान को प्रोत्साहन देती है। लेकिन अफसरान की लापरवाही से सरकार की बदनामी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क के साथ-साथ सफेदे के पेड़ लगे हुए हैं। अगर किसान उन पेड़ों को काटता है, तो सजा होती है, मुकदमे बनते हैं। अगर नहीं काटता तो उसके 10 एकड़ रकबे में फसल नहीं होती। जिन किसानों के खेत सड़क के किनारे हैं, उन्हें बहुत नुकसान होता है सरकार या तो इन किसानों को मुआवजा दे या यह पेड़ कटवाए।

[श्री अजमत खां]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में एक उटावड़ माइनर है । यह 1972 से बनी है । आज तक उसका रैवेन्यू देख लें कि कितना आया है । लास्ट टेल पर पानी कभी नहीं जाता । जो हमारा एरिया पड़ता है, वहां हमारे जाति-भाई आते हैं और पुलिस के जारए पानी ले जाते हैं । इससे हमारी बदनामी होती है । नहर 33 किलोमीटर तक बनी है । उसके लिए अफसरान ने कहा है कि इस में 33 कि0 मी0 नहर नहीं चल सकती । 68 बुर्जी तक हम यहां से दूसरी लाईन निकाल सकते हैं वह स्कीम यहां आई पड़ी है । यह स्कीम डेढ़ करोड़ रुपये की है । उससे हम इस परेशानी से बच सकते हैं । यह लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम है । उसका बैक नीचे है । पीछे से पानी आता है जब बिजली गई तो उसका पानी उल्टा लौट जाता है । टेल ऊंचा है और हैड नीचा है । अगर उसके हैड को ऊंचा करना है, तो उसका बैक ऊंचा करना पड़ेगा जिससे बिजली जाने की वजह से पानी वापस नहीं लौटे । मेरे हल्के में एक-दो गांव को छोड़कर, बाकी गांवों में पानी नहीं पहुंचता । उटावड़ माईनर के बारे में मेरी आपसे अर्ज है कि इसके लिए मैं 1982 से कोशिश कर रहा हूं । इस बार 80 बुर्जी तक पानी पहुंचा है । इस पानी को रैगुलर पहुंचाया जाए जिससे पीने के पानी का मसला हल हो और खेती के लिए भी पानी मिले ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड के मुताल्लिक बात कहना चाहता हूं । पलवल में एक मार्किट कमेटी है और हथीन में सब-यार्ड है । सिर्फ हथीन एक ऐसी जगह है, जहां पर मार्किट कमेटी नहीं है । हम हर साल 12-15 लाख रुपये का रैवेन्यू सरकार को देते हैं जबकि सिर्फ दो महीने सीजन चलता है । मार्किट कमेटी के लिये प्लाट्स भी अलाट हो गये हैं लेकिन वहां पर लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे । वे प्लाट्स या तो कैंसिल किए जाएं या वहां पर कंस्ट्रक्शन करवाई जाए । दूसरी बात यह है कि उस मंडी को सारा साल चालू रखवाया जाए ताकि आमदनी बढ़े और यह बात तभी होगी जब हथीन को सब-यार्ड की बजाये पूरी मार्किट कमेटी का दर्जा दिया जाएगा । यह काम बहुत ही जरूरी है ।

दूसरी बात यह है कि हथीन के अन्दर एक बस-स्टैण्ड भी होना चाहिये । इस के लिये जमीन एक्वायर हो चुकी है और पैसे भी दे दिये गये हैं । सिर्फ चार दीवारी बननी है । इस ओर सरकार ध्यान दे । अफसरों ने यह कह दिया कि साहब, हमने कुछ रूट्स प्राईवेट लोगों को दे दिये हैं । केवल पांच रूटों पर पांच बसें ही दी हैं । लेकिन साथ-साथ सरकारी बसें भी चलेंगी । वहां पर हमारा सैन्टर है । तहसील है और अगर खुदा ने चाहा कि कभी पलवल जिला बन गया तो हमारा हथीन भी सब-डिवीजन होगा । इसलिये वहां पर बस-अड्डा बनना बहुत जरूरी है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हैल्थ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । वहां पर एक हस्पताल है और वहां पर छोटी-छोटी डिसपैंसरियां छोटे-छोटे गांव में होनी बहुत जरूरी हैं जी0 यू0 डी0 और जी0 ए0 डी0 । जी0 यू0 डी0 डिसपैंसरी तो बराये

नाम ही है । जी0 ए0 डी0 हैं । सौंध में हमें एक भी जी0 यू0 डी0 और जी0 ए0 डी0 डिसपैंसरी नहीं मिली है । 17 हजार की आबादी वाला गांव है और वहां से एक डिसपैंसरी को उठा लिया गया है । वह शायद इसलिये किया गया कि होडल में एक सी0 एच0 सी0 बन गई और वहां से वह कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर है । बड़े गांव में जी0 यू0 डी0 तो जरूर ही खोली जाए और साथ-साथ डंगरों के हस्पताल भी हर पटवार हल्के में बनाए जाएं । यह सही है कि भजन लाल सरकार आने के बाद मेवात ऐरिया में बहुत डिवैल्पमैंट के काम हुए हैं जिससे मेवात ऐरिया को काफी फायदा हुआ है । जहां पहले कोई काम नहीं हो सकते थे, वहां पर डिवैल्पमैंट के काम हुए । स्कूल बने, सड़कें बनीं । पानी के बहुत काम हुए और दूसरे डिवैल्पमैंट के काम भी हुए । लेकिन एक बात गलत हो गई कि मेवात बोर्ड का जो दफ्तर है, वह गुड़गांव में ही रहने दिया गया । यह ठीक नहीं है । गुड़गांव में दफ्तर रहने से अफसरों को फायदा हो सकता है, उनको टैलीफोन का फायदा हो सकता है । उनको टी0 ए0/डी0 ए0 का फायदा हो सकता है लेकिन आम आदमी की जरूरत के बारे में उन अफसरों को कोई ध्यान नहीं है । आम लोगों की गुड़गांव में दफ्तर होने से जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं । इसलिये यह दफ्तर नूंह में ही रखा जाए, तो बेहतर होगा । उन अफसरों को चाहिये कि वे आम लोगों की जरूरतों को नजदीक से देखें और यह तभी हो सकता है, जब यह दफ्तर गुड़गांव में न होकर नूंह में होगा । दूसरा हमारे इलाके के कोई मुलाजिम उस दफ्तर में नहीं है । सारे बाहर के हैं । हर काम को गुड़गांव में जाकर करवाना, यह अच्छा नहीं होगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी एक यह गुजारिश है कि जो पैसा डिवैल्पमैंट के कामों पर लगाया जाए, उस पैसे की हमें भी जानकारी होनी चाहिये । उस पैसे के बारे में अफसर हमें भी बताएं कि हम फलां डिवैल्पमैंट के कामों के लिये यह-यह पैसा खर्च कर रहे हैं । इससे ऐसा होगा कि हमें मेवात बोर्ड के काम से वाकफियत रहेगी कि यह-यह काम बोर्ड ने करवाए हैं और यह-यह काम स्टेट के बजट से हुआ है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एजुकेशन पर दो-एक बातें करना चाहूंगा । डिप्टी स्पीकर साहब, एजुकेशन किसी भी इलाके, किसी भी कौम, किसी मुल्क के लिये काफी बुनियादी हैसियत रखती है । जिस कौम को आगे जाना होता है वह एजुकेशन लेती है और जिस कौम को पिछड़ना होता है, उससे एजुकेशन छीन ली जाती है । प्राईवेट स्कूल्ज मेवात के इलाके में हर जगह पर हैं । इस एजुकेशन के बारे में, सरकार ने बहुत कुछ किया है । इस बात को मैं क्या कहूं ? सरकारी आंकड़े कहते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, कुछ ऐसी प्रोबलम्ज हैं, जिनका हल किये बगैर मेवात का आदमी एजुकेशन नहीं पा सकेगा । अगर एक इलाके को, एक कौम को एजुकेशन से वंचित रखा गया, तो वह कौम, वह इलाका दुनियां की दौड़ में पीछे रह जाएगा

[श्री अजमत खां]

और आने वाली नसलें, जिनके पास कमाने के साधन नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, जमीनें नहीं होंगी, वे भटक जाएंगी । ऐसे लोगों को सम्भालना हमारे लिये मुश्किल हो जाएगा । वे लोग समाज के अन्दर रहकर जुल्म करेंगे । बुराईयां करेंगे । गन्दे रास्ते पर चलेंगे, डकैती करेंगे और इस तरह से वे लोग समाज के ऊपर एक तरह से कलंक सा बन कर रह जाएंगे और ऐसे लोग समाज के वातावरण को दूषित करते रहेंगे । इसलिये यह जरूरी है कि हर नौजवान को एजुकेशन दी जाए । अब एजुकेशन के बाद बात आती है नौकरियों की । नौकरियां तो तब मिलेंगी, जब हर आदमी एजुकेटिड होगा । इसी तरह से एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिये 10+2 के स्कूलों की भी जरूरत है । मेरे इलाके में केवल एक ही स्कूल जे0 बी0 टी0 का है । एक 10+2 का स्कूल 10-15 किलोमीटर के फासले पर है । लेकिन हमारे अपने दोस्तों के यहां शहरों में प्राइवेट स्कूल हैं, जिनमें उनके बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं । देहात के बच्चे 15-15 किलोमीटर से साईकल पर, बस पर लटक कर या ट्रैक्टरों पर आते हैं और उनका आने-जाने में बहुत टाईम खराब हो जाता है । कई बार उनके एक्सीडैंट्स भी हो जाते हैं । आप एजुकेशन को देहात में लाएं । आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल देहातों में खोलें । इससे उन लड़कों का भला होगा । ऐसा करने से गरीब आदमी ऊपर उठ सकेंगे । हमारे यहां दस-जमा-दो के स्कूल मेवात के कस्बों के अलावा बड़े गांवों में नहीं हैं । फिरोजपुर झिरका, नूंह और तावडू के कस्बों में तो दस जमा दो के स्कूल हैं, लेकिन देहातों में नहीं हैं । हमारे यहां 62 हाई स्कूलों में से 49 हाई स्कूलों में हैड मास्टर भी नहीं हैं और सब्जैक्ट टीचर भी नहीं हैं । सिर्फ 13 स्कूलों में हैड मास्टर हैं और वे स्कूल भी शहरों में हैं । तो आप ही बताएं कि हैड मास्टर और सब्जैक्ट टीचर के बिना काम कैसे चलेगा ? इस वजह से जिस बच्चे का साल खराब हो गया, वह कहां जाएगा ? आपके बच्चे तो शहरों में पढ़ते हैं और उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है । असल पता तो तब चले, जब शहर के बच्चों के मुकाबिले में देहाती बच्चे निकल कर आएं । यह तभी संभव होगा जब देहातों में जगह-जगह स्कूल खोले जाएंगे । किसी वक्त में शहरों और देहातों में एक जैसी पढ़ाई थी, लेकिन आज देहात से पढ़ाई निकल गई । इस वजह से आज शहरों के बच्चों की ही ज्यादा क्वालिफिकेशन होती है और उन्हीं को अच्छी नौकरियां मिलती हैं । देहात से शिक्षा को निकालने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं ।

इसके अलावा यहां पर बिजली के बारे में भी बात की जाती है । यह कहना कि हमारे यहां बिजली नहीं है, यह गलत बात है । मैं कहता हूं कि पहले के मुकाबिले में बिजली का उत्पादन बढ़ा है तथा इसे और बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि आने वाले चार-पांच सालों में बिजली की पैदावार और बढ़ेगी । फिजूल में शोर मचा कर हाउस का समय बर्बाद करना, कोई अच्छी बात नहीं है । हर आदमी को सच्चाई कहनी चाहिए । (घण्टी) डिप्टी स्पीकर साहब, थोड़ा समय और दें । मैं आपके हुक्म को मानूंगा । मैं अर्ज कर रहा था कि जो

बिजली के बारे में कहा जाता है, वह सिर्फ सियासी प्रौपेगन्डे के लिए कहा जाता है और अपना फायदा उठाने के लिए कहा जाता है । अगर बिजली कहीं एक दिन में खरीदी जाती या कोयले की तरह से रेल में लाई जाती तो मसला हल हो सकता था । लेकिन बिजली तो पैदा की जाएगी, इसको स्टौर नहीं किया जा सकता है । इसलिए पावर के लिए जो सरकार ने काम किया है, वह सराहनीय है । मैं समझता हूं कि इस बारे में जो कुछ हो रहा है, वह ठीक ही हो रहा है और मैं इसके लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

एक बात यहां पर विकास की आती है । ये मेरे भाई हैं और मैं इस बात से इन्कार नहीं करता । इन्होंने लोगों को राजी करने के लिए पैन्शन दे दी और कर्जा माफ किया गया । कर्जा माफ करने के बारे में इन्होंने बहुत पहले शोर मचा दिया इसलिए लोगों ने कर्जा वापिस करने से इन्कार कर दिया । उस वजह से उस कर्जे का ब्याज बढ़ गया । पैन्शन के लिए सब ने हाथ फैलाए । आज यह आदत सी बन गई है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, वह 100 रुपए लेने के लिए हाथ फैलाता है । इसमें एक बात जरूर है कि कुछ जैनुईन लोग इससे वंचित रह गए हैं । पता नहीं, किस वजह से रह गए हैं ? इसके अलावा हम एक बात को मानते हैं कि डिवैल्पमैंट के जो काम हैं, उसको कोई तजुर्बेकार आदमी ही कर सकता है । आप देखें कि हरियाणा में कितने डिवैल्पमैंट के काम हुए हैं । हर गांव में पक्की गलियां हैं । स्कूलों के कमरे बने हुए हैं । हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है । यानी सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को दी गई हैं । ये डिवैल्पमैंट के काम तभी होते हैं, जब कोई पैसा इकट्ठा करने वाला हो और उस पैसे का ठीक इस्तेमाल करना जानता हो । आदमी को पैसा लेने का भी और उसको खर्च करने का भी तरीका आना चाहिए । हमारे नेता ने पैसा इकट्ठा करने के बारे में भी सीखा और उसको खर्च करने के बारे में भी सीखा । यही कारण है कि प्रान्त में जगह-जगह डिवैल्पमैंट के काम हो रहे हैं ।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय केवल 4 मिनट के लिये बढ़ा लिया जाए ।

आवाजें : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का समय 4 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

वर्ष 1995-96 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री अजमत खां : डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं आगरा कैनाल के बारे में कहना चाहूंगा । हमारे फरीदाबाद जिले का आगरा कैनाल के साथ जिन्दगी और मौत का सवाल है । उस कैनाल का कंट्रोल यू0पी0 सरकार के पास है । उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे भी हैं । हमारे आदमी ही, वह नाजायज कब्जे कर रहे हैं । हमने ही उनका रैवेन्यू नहीं दिया है । यह बात सही है लेकिन वह रैवेन्यू इसलिए हम से वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वे हमें पानी नहीं देते हैं । मैं कहता हूं कि सरकार इस मसले को हाई लैवल पर बहुत तेजी के साथ उठाए । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सी0एम0 साहब से अर्ज करूंगा कि जिस तरह से आपने जमुना नदी के पानी का फैसला करवा दिया तथा और भी बहुत से फैसले करवाए हैं, उसी तरह से आप यह मसला भी हल करवाएं । क्या आगरा कैनाल का फैसला नहीं हो सकता ? आप उसका फैसला करवा करके उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लें । हमें यू0पी0 वाले पूरा पानी नहीं देते हैं । आप उस कैनाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लें । हमारे लिए यह काफी होगा । इसी से हमारी जिन्दगी बन जाएगी । आप यूं समझें कि आगरा कैनाल हमारे इलाके के लिए जिन्दगी और मौत का सवाल है । अगर आपने उसका कोई हल नहीं करवाया और इस मसले को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो पता नहीं यह मसला कब तक यूं ही लटका रहेगा ? हमें बार-बार यह कहा जाता है कि इस मसले को हल कर रहे हैं । हमें तो डिसिप्लिन का डर लगता है, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड आदमी हैं । अगर हम इन-डिसिप्लिन्ड हो गए, तो हम अपने हिस्से का पानी उनसे जरूर ले लेंगे । लेकिन हम चाहते हैं कि आप उस पानी को ले लें । पानी हमारी हद में से जाता है । हमारे सामने से जा रहा है । हमारे खेत तरस रहे हैं । हमारे बच्चे तरस रहे हैं । मेरी आपसे अर्ज है कि अगर आप पानी नहीं ले पाए, तो हो सकता है हम अपने हिस्से का पूरा पानी लेने पर मजबूर हो जाएं । इसलिए मेरी अर्ज है कि आप इस बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ।

डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट पेश किया गया है, यह बहुत अच्छा है । भाई जिस आदमी को जिससे कुछ लेना ही नहीं, देना ही देना है, उसे अच्छा ही कहा जाता है । लोगों से लिया कुछ नहीं, उनको दिया ही दिया है । उन पर कोई बोझ नहीं लादा है, इसलिए यह बजट बहुत शानदार है । डिप्टी स्पीकर साहब, डिवैल्पमैंट के कामों के लिए जो पैसा रखा गया है, उसके लिए मैं सरकार और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि जो पैसा डिवैल्पमैंट के कामों के लिए रखा गया है, वह ठीक है । किसी देश प्रदेश के लिए डिवैल्पमैंट भी बुनियादी बात है ।

आखिर में मैं अपने हल्के की सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा । मेरे हल्के में एक-एक दो-दो किलोमीटर की सड़कें बननी रह गई हैं, उनको बनाया जाए । वे सड़कें इसलिए रह गई क्योंकि जिस वक्त वे बनाई गई, उस समय 1974 में फलड

का जमाना था । इसलिए 1974 में 15-15 और 20-20 किलोमीटर का फर्क पड़ा । एक सड़क है; स्यापणकी से बिरोहपुर राजपूत । यह दो किलोमीटर का टुकड़ा बनना है इसके न बनने से लोगों को 25 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना-जाना पड़ता है । इसी तरह से सिहा से मरोली गांव की सड़क दो किलोमीटर बननी है । उसके न बनने से लोगों को 27 किलोमीटर का चक्कर काट कर आना जाना पड़ता है । मेरे हल्के में एक गुमरेड़ा गांव है । वह आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है । आज तक उस गांव की पक्की सड़क नहीं बनी है जबकि सरकार की यह पालिसी है कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा । मेरे हल्के में गुमरेड़ा गांव और टोंगा गांव ऐसे गांव हैं, जो सड़क से नहीं जोड़े गए हैं । इसी तरह से रिणावा खुर्द से पोट तक की सड़क है । आरीदेव से नाटोली की सड़क है । थाइका से निमाणा तक की सड़क है । लोहाणा से सोहरी तक की सड़क है । इन गांवों की सड़कों को बनाया जाए । एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिन सड़कों की मुरम्मत करवाई है और जिन सड़कों को बनवाया है, वह बहुत अच्छी हैं । सड़कों की बहुत अच्छी मुरम्मत करवाई है । आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के की मैंने जो छोटी-छोटी सड़कों के बारे में कहा है, उनको जरूर बनवाएं । ये सारी सड़कें मार्किट कमेटी को जाती हैं । यदि मार्किट कमेटी उनको बनाना मान ले तो वे सारी सड़कें बन सकती हैं । जो तरक्की का दरवाजा खुला हुआ है, वह हमेशा खुला रहेगा । यह बंद नहीं होगा । उन सड़कों को बनाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा दे, ताकि लोगों को सहूलियत हो । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अजमत खां जी, जब आपने अपनी स्पीच शुरू की, तो बीच में आपने एक बात कही कि आप द्वारा दिए हुए सवाल लगते नहीं हैं, या लगते हैं तो बहुत पीछे लगते हैं । किसका सवाल लगा, किसका नहीं लगा, आगे लग गया या पीछे लग गया । उसका एक सैट प्रोसैस है, सैट प्रोसीजर है । इसमें किसी की कोई कोशिश नहीं कि किसी सदस्य का सवाल पीछे लगे और न ही ऐसी कोशिश की कोई किसी की नीयत है ।

श्री अजमत खां : डिप्टी स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि अगर मैं गलती पर हूं तो मैं अपनी गलती मानता हूं लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आप कम से कम पिछले चार साल का रिकार्ड निकाल कर देख लें, मेरी कहां और क्या गलती हो गई ?

Mr. Deputy Speaker : Now the House stands adjourned till 2.00 p m. on Monday the 20th March. 1995.

*13.34 hrs. | (The Sabha then *adjourned till 2.00 P. M. on Monday the 20th March, 1995)

26751—H.V.S.—H.G.P., Chd.